



# सहकार सुगंध

PRGI NO. MAHMUL/2005/16099

● पुणे ● वर्ष : २२ ● अंक ०२ ● मे २०२६ ● पृष्ठे ४४ ● किंमत : रु. ३०/- ● संपादक : भालचंद्र कुलकर्णी

## सहकार भारती आयोजित 'सहकार महोत्सव' यशस्वी



सोलापूर उद्योजकता महोत्सव



पुणे सहकार महोत्सव



सहकार सुगंध प्रकाशित 'बँकिंग साक्षरता' पुस्तकाचे प्रकाशन



सहकार चळवळ विस्तारासाठी संशोधन हवे



विदर्भस्तरीय सहकार परिषद यशस्वी

# तुमच्या बचतीत वाढ करा



**10.10%\***  
व्याजदर

9.00%  
1 ते 2 वर्षे

10.00%  
2 ते 3 वर्षे

10.10%  
3 ते 5 वर्षे

\* किमान गुंतवणूक ₹ 1,000 व अधिक • व्हेस्ट नागरिकांसाठी 0.5% जास्त व्याज (६० वर्षांवरील)  
डेडीअर मधील व्याजदर १ एप्रिल २०२६ पासून लागू | \*केवळ सध्यासाठी. \*नियम व अटी लागू

## MULTIPURPOSE SERVICES

|                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LIFE INSURANCE</b></p>  | <p><b>GENERAL INSURANCE</b></p>  | <p><b>MUTUAL FUND</b></p>  | <p><b>DSA LOANS</b></p>  | <p><b>GOLD LOAN</b></p>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



१ मे  
महाराष्ट्र  
दिन  
निमित्त



बौद्ध पोर्णिमा  
निमित्त



रा.ल. उपाख्य भाऊसाहेब शेळके  
संस्थापक अध्यक्ष, राजर्षी शाहू परिवार



बकरी ईदच्या

सर्वांना मंगलमय  
हार्दिक शुभेच्छा...!

तुमच्या सेवेत सदैव तयार..!

संदीप शेळके

अध्यक्ष, राजर्षी शाहू परिवार

### संस्थेची वैशिष्ट्ये

- एकूण ६९ शाखेचा विस्तार
- २००० कोटीचा व्यवसाय
- १,५०,००० सभासद संख्या
- 'शाहू पे हे' पेमेंट ऑप विकसित करणारी भारतातील पहिली पतसंस्था.
- महिला बचत गटाच्या माध्यमातून ७५ हजार महिलांना २५० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप.
- १०५ कोटी रु. सोने तारण कर्ज वाटप.



LOCKERS सुविधा



NEFT, RTGS सुविधा  
उपलब्ध



SMS अलर्ट



DOORSTEP बँकिंग



MOBILE बँकिंग



DEPOSITE सुविधा



LOAN सुविधा



CORE बँकिंग



NET बँकिंग



GOLD LOAN  
उपलब्ध



MSEDCL  
वीज बिल भरणा केंद्र



अनेक प्रकारच्या पॉलिसी  
काढण्याची व  
प्रीमियम भरण्याची सुविधा

ISO ९००१:२०१५ मान्यता प्राप्त संस्था, FCBA पुरस्कार प्राप्त संस्था,

मल्टीस्टेट फेडरेशनचा सहकार गौरव पुरस्कार प्राप्त संस्था

बँको पुरस्कार प्राप्त संस्था

कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश

राजर्षी शाहू  
मल्टीस्टेट को ऑप क्रेडीट सोसायटी म.बुलडाणा

सौ.मालती शेळके

अध्यक्षा, राजर्षी शाहू मल्टीस्टेट  
को. ऑफ क्रेडीट सोसा. मर्या. बुलडाणा



www.rajarshishahumultistate.com

9359941853

**₹२५,०००**  
कोटींच्या व्यवसायाची  
अभिमानारूपद वाटचाल,  
प्रगतीचा नवा अध्याय

**७ राज्यात  
उपस्थिती**

**१६५ शाखांचे  
विस्तृत जाळे**

## लेखापरीक्षित निकाल

(₹ कोटींमध्ये)

| तपशील                   | ३१-०३-२०२६ | ३१-०३-२०२५ |
|-------------------------|------------|------------|
| एकूण व्यवसाय            | २५,३६०     | २३,१०५     |
| ठेवी                    | १६,२४४     | १४,८४९     |
| कर्जे                   | ९,११६      | ८,२५६      |
| ढोबळ नफा                | २८७        | २५२        |
| निव्वळ नफा              | १५५        | १८५        |
| स्वनिधी                 | १,७७३      | १,६३९      |
| ढोबळ अनुत्पादित कर्जे   | ३.११%      | ३.५९%      |
| निव्वळ अनुत्पादित कर्जे | ०.००%      | ०.००%      |
| पुंजी पर्याप्तता        | १६.८९%     | १७.४८%     |

[www.tjsb.bank.in](http://www.tjsb.bank.in) | ☎ : 022-48897210



# आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सह स्मार्ट बँकिंगचा नवा अनुभव!



शासकीय नियमावलीवर आधारित  
अत्याधुनिक कोअर बँकिंग सोल्यूशन



NPA व्यवस्थापन आणि  
सुबक रिपोर्ट्सची सुविधा



सुलभ कर्ज अर्ज – सुरक्षित, सोपी  
आणि जलद डिजिटल प्रक्रिया!



संस्थेच्या वाढीसाठी NetPay UPI  
QR कोड सुविधा

● Certification ●



netwin  
Ideas to Life

नाविन्य, विश्वास आणि  
गुणवत्तेचं प्रतीक.



- AI-सक्षम प्रणालीद्वारे आधुनिक आणि गतिमान बँकिंग सेवा
- तुमचा चेहरा तुमची ओळख – खाते उघडण्यासाठी फक्त एक सेल्फी पुरेशी!
- आधार OTP आणि डिजिटल ई-केवायसी द्वारे खाते सुरु करा
- बायोमेट्रिक वर आधारित अचूक प्रमाणीकरण
- स्मार्ट डॅशबोर्ड्स आणि रीअल टाईम डेटा नियंत्रणाची सुविधा
- संपूर्णतः पेपरलेस, जलद आणि सुरक्षित व्यवहार अनुभव

आजच आपल्या संस्थेला  
बनवा AI-सक्षम!



0293 669 9900



sales@netwinindia.in



www.netwin.in

f @ X v



अधिक माहितीसाठी  
स्कॅन करा



# जनसेवा सहकारी बँक लि., हडपसर, पुणे.

जनसामान्यांची असामान्य बँक, जनसेवेसाठी वचनबद्ध !

## जनसेवा घरकुल कर्ज

रो हाऊस, बंगला, प्लॉट खरेदीसाठी  
किफायतशीर कर्ज उपलब्ध.  
(सिबिल स्कोरनुसार व्याजदर)

Processing Fee

**0%**

Rate of Interest

**7.50%\***

Onwards



## जनसेवा शैक्षणिक कर्ज

देशांतर्गत तसेच परदेशातील  
शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध.

Processing Fee

**0%**

Rate of Interest

**8.90%\***

Onwards

\* अटी लागू



मुख्य कार्यालय: प्लॉट क्र. १४,  
हडपसर इंड. इस्टेट, पुणे १३.

फोन: ०२०-२६७०४३०० ते ०४ (५ लाईन्स)  
[www.janasevabankpune.bank.in](http://www.janasevabankpune.bank.in)

॥ बिना संस्कार नहीं सहकार ।  
बिना सहकार नहीं उद्धार ॥

# सहकार सुगंध



ISBN : 978-81-940842-0-4

मे २०२६ (वर्ष २२, अंक ०२)

संपादक :

भालचंद्र कुलकर्णी (मोबाईल : ९८२२८८२५०९)

सहसंपादक :

विनायक कुलकर्णी (मोबाईल : ९४२२३२१६२६)

## वर्गणीचे दर

वार्षिक वर्गणी : रु. ७००/- फक्त  
त्रैवार्षिक वर्गणी : रु. १८००/- फक्त  
खालील QR कोड स्कॅन करून ऑनलाइन पेमेंट करावे.  
Please Visit : [www.sahakarsugandha.org](http://www.sahakarsugandha.org)

## QR कोड

कृपया QR कोड स्कॅन  
करून ऑनलाइन पेमेंट  
करावे. किंवा  
खालील बँक खात्यात थेट  
रकम जमा करावी.



## A/c Name

A/c Name :  
Sahakar Printing & Publications Pvt. Ltd.  
Bank Name : State Bank of India  
(Hingne Khurd, Pune Branch)  
Current a/c No. : 36931889346  
IFS Code - SBIN0007159

## सहकार सुगंध कार्यालय

ऑफिस नं. १५, विष्णू प्रिया अपार्टमेंट,  
५ वा मजला, ईशान रेस्टॉरंटच्यावर,  
गणेशमळा, सिंहगड रोड,  
पुणे - ४११०३०. मो. : ८८०५९८१६७३  
ईमेल : [sahakar.sugandha@gmail.com](mailto:sahakar.sugandha@gmail.com)

सहकार प्रिंटिंग अँड पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

संचालक मंडळ :

डॉ. उदय जोशी (संचालक, राष्ट्रीय अध्यक्ष)  
सीए सतीश मेढी (संचालक, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष)  
श्री. विनय खटावकर (संचालक)  
श्री. भालचंद्र कुलकर्णी (व्यवस्थापकीय संचालक)

मार्गदर्शक : सहकार भारती पदाधिकारी

डॉ. उदय जोशी (राष्ट्रीय अध्यक्ष)  
श्री. दीपक चौरसिया (राष्ट्रीय महामंत्री)  
श्री. दीनानाथ ठाकूर (संरक्षक)  
श्री. संजयजी पाचपोर (राष्ट्रीय संघटनमंत्री)  
श्री. दत्ताराम चाळके (महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष)  
श्री. विवेक जुगादे (महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री)  
श्री. शरद जाधव (महाराष्ट्र प्रदेश संघटनमंत्री)  
डॉ. मुकुंद तापकीर, श्री. सतीशजी मराठे,  
श्री. ज्योतिंद्रभाई मेहता, श्री. विष्णूजी बोबडे,  
श्री. संजय परमणे

जाहिरात व वर्गणीदार विभाग समन्वयक :

सौ. अंजली लागू, श्रीमती पौर्णिमा राईलकर

मुखपृष्ठ मांडणी, अक्षरजुळणी व डिझाइन :

सौ. अर्चना गाढवे

‘सहकार सुगंध’ हे मासिक मालक, सहकार प्रिंटिंग अँड पब्लिकेशन्स प्रा. लि. यांचेसाठी प्रकाशक भालचंद्र वसंत कुलकर्णी यांनी मुद्रक विवेक श्रीधर देशपांडे यांच्या श्रीपाद प्रिंटेर्स, शॉप नं.२, कोनार्क उद्योग, स.नं. १७७, एरंडवणा, पुणे ४११ ००४ येथे छापून ऑफिस नं. १५, विष्णू प्रिया अपार्टमेंट, गणेशमळा, सिंहगड रोड, पुणे ४११ ०३० येथे प्रसिद्ध केले. संपादक - भालचंद्र वसंत कुलकर्णी

‘Sahakar Sugandha’ monthly is owned by Sahakar Printing & Publications Pvt. Ltd., Published by Bhalchandra Vasant Kulkarni at Office No. 15, Vishnu Priya Apartment, Ganeshmala, Sinhagad Road, Pune 411 030 Printed by Vivek Shridhar Deshpande at Shripad Printers, Shop No. 2, Konark Udyog, S.N. 177, Erandwane, Pune 411 004.  
Editor : Bhalchandra Vasant Kulkarni



## आर्थिक साक्षरता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाची अपरिहार्यता

नुकतेच सहकार सुगंधने बँकिंग साक्षरता या पुस्तकाचे प्रकाशन केले आहे. ज्येष्ठ बँकिंग तज्ञ गणेश निमकर यांच्या सिध्दहस्त लेखणीतून उतरलेल्या या पुस्तकात आर्थिक, बँकिंग साक्षरतेसंबंधी विविध घटकांची माहिती सविस्तरपणे दिलेली आहे. या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने बदलते बँकिंग आणि साक्षरतेची गरज यावर परिसंवाद झाला. अनेक दिग्गजांनी यामध्ये सहभाग घेतला. बँकिंग, सहकार आणि पतसंस्था चळवळीमध्ये सक्रिय राहणाऱ्या सर्वांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आणि नाबार्डचे संचालक सतीश मराठे, सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे, बुलडाणा अर्बनचे संस्थापक भाईजी चांडक, महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष अजय ब्रह्मेचा, नॅफकॅबचे उपाध्यक्ष मिलिंद काळे, सहकार भारती महाराष्ट्राचे महामंत्री विवेक जुगादे अशा दिग्गजांनी परिसंवादात सहभाग घेतला. या परिसंवादात अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली, त्याचाच हा परामर्श!

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार, महिला बचत गट, लघुउद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठे परिवर्तन घडत आहे. या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी सहकार क्षेत्र, आर्थिक व बँकिंग साक्षरता आणि डिजिटल तंत्रज्ञान हे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. आजच्या काळात या तिन्ही घटकांचा परस्पर संबंध समजून घेणे आणि त्यांना सक्षम करणे ही काळाची गरज बनली आहे. भारतातील सहकार चळवळ ही केवळ आर्थिक संस्था नसून सामाजिक परिवर्तनाची शक्ती आहे. ग्रामीण भारतात शेतकऱ्यांना पतपुरवठा, शेतीसाठी आवश्यक साधने, बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योग आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सहकारी संस्थांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, पतसंस्था आणि नागरी सहकारी बँकांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार दिला आहे.

सहकार क्षेत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वांच्या सहभागातून सर्वांचा विकास. नफा हा अंतिम उद्देश नसून सदस्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक उन्नती हे त्याचे मुख्य ध्येय असते. त्यामुळेच ग्रामीण आणि दुर्बल घटकांना आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार क्षेत्र प्रभावी माध्यम ठरले. मात्र बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत सहकारी संस्थांसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. वाढती स्पर्धा, आर्थिक गैरव्यवहार, तांत्रिक कमतरता, व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेचा अभाव आणि डिजिटल प्रणालींचे अपुरे ज्ञान यांमुळे अनेक संस्था अडचणीत आलेल्या दिसतात. या परिस्थितीत सहकार क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक साक्षरतेची जोड देणे अत्यावश्यक झाले आहे.

आजही ग्रामीण भागातील मोठा वर्ग बँकिंग व्यवहार, कर्जप्रक्रिया, विमा, गुंतवणूक, डिजिटल पेमेंट, बचत योजना आणि आर्थिक नियोजन याबाबत पुरेसा जागरूक नाही. अनेक लोक फसवणुकीला बळी पडतात किंवा चुकीच्या आर्थिक निर्णयांमुळे कर्जबाजारी होतात. यावर उपाय म्हणजे आर्थिक आणि बँकिंग साक्षरता. आर्थिक साक्षरता म्हणजे केवळ पैसे साठवणे नव्हे, तर उत्पन्न, खर्च, बचत, गुंतवणूक आणि कर्ज यांचे योग्य नियोजन समजणे होय. बँकिंग साक्षरतेमुळे नागरिकांना बँक खाते, एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, यूपीआय, कर्ज सुविधा आणि सरकारी योजनांचा लाभ प्रभावीपणे घेता येतो.

आज शासन विविध योजना राबवत आहे; परंतु माहितीच्या अभावामुळे अनेक लाभार्थी त्यापासून वंचित राहतात. आर्थिक साक्षरता वाढल्यास नागरिक स्वावलंबी बनतील, बचतीची सवय लागेल आणि आर्थिक शिस्त निर्माण होईल. विशेषतः महिला स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी आणि युवक यांना आर्थिक शिक्षण दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होऊ शकते.

डिजिटल क्रांतीमुळे बँकिंग व्यवहार जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक झाले आहेत. यूपीआय, मोबाईल बँकिंग, आधार आधारित व्यवहार, ऑनलाइन कर्ज प्रक्रिया, डिजिटल खाते उघडणे आणि ई-गव्हर्नन्स यामुळे आर्थिक सेवा गावागावात पोहोचल्या आहेत. सहकारी संस्थांनीही या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे गरजेचे आहे. डिजिटल लेखापद्धती, ऑनलाइन व्यवहार, सदस्यांची माहिती व्यवस्थापन, ई-ऑडिट आणि पारदर्शक आर्थिक प्रणाली यामुळे सहकारी संस्थांवरील विश्वास वाढू शकतो. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवणेही शक्य होते. आपण सर्वच आता स्मार्टफोन वापरत असलो तरी डिजिटल व्यवहारांबाबत पुरेसे प्रशिक्षण घेतलेले नसते. त्यामुळे सायबर फसवणूक, ओटीपी घोटाळे, बनावट ॲप्स आणि ऑनलाइन आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. म्हणूनच डिजिटल साक्षरता ही आर्थिक साक्षरतेइतकीच महत्त्वाची ठरते. जर सहकारी संस्थांनी डिजिटल व्यवहारांचे प्रशिक्षण दिले, ऑनलाइन बँकिंगची माहिती दिली आणि सायबर सुरक्षेबाबत जागृती केली, तर समाज अधिक सक्षम होईल.

सहकार क्षेत्र, आर्थिक-बँकिंग साक्षरता आणि डिजिटल तंत्रज्ञान हे ग्रामीण आणि राष्ट्रीय विकासाचे तीन मजबूत आधारस्तंभ आहेत. सहकार चळवळीची सामाजिक ताकद, आर्थिक साक्षरतेची जागरूकता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाची गती यांचा योग्य संगम घडवला तर भारत अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करू शकतो. आज गरज आहे ती केवळ तंत्रज्ञान वापरण्याची नाही, तर ते समजून जबाबदारीने स्वीकारण्याची. आर्थिकदृष्ट्या सजग आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम नागरिक निर्माण झाले, तरच सहकार क्षेत्र नव्या युगात टिकून राहून विकासाचा खरा मार्गदर्शक ठरेल. जय सहकार!



संपादकीय...



सहकार भारती आयोजित सहकार महोत्सव यशस्वी

# सहकाराचा जागर होण्यासाठी सहकार महोत्सवाच्या आयोजनाची आवश्यकता

## राज्य सहकारी बँक प्रशासक विद्याधर अनास्कर

**पुणे –** सहकार क्षेत्रातला सहकार आगामी काळात अधिक प्रमाणावर विकसित होण्यासाठी आणि सहकाराचा जागर होण्यासाठी यापुढील काळात ठिकठिकाणी सहकार महोत्सव आयोजित करणे आवश्यक आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे. सहकार भारती पुणे विभाग आणि अस्तित्व फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय सहकार महोत्सवाचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

सिंहगड रस्तावरील कलाग्राम येथे आयोजित महोत्सव उद्घाटन प्रसंगी सहकार भारती पुणे महानगराचे अध्यक्ष सीए दिनेश गांधी, अस्तित्व फाउंडेशनच्या संचालक डॉ. राजश्री जायभाये, सहकार भारती राष्ट्रीय प्रकाशन प्रसिद्धी प्रमुख आणि सहकार सुगंध मासिकाचे संपादक भालचंद्र कुलकर्णी, राष्ट्रीय महिला प्रमुख रेवती शेंदुर्णीकर, सहकार भारती पुणे विभाग प्रमुख गिरीश भवाळकर, राज्य गृहनिर्माण फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, सहकार महोत्सवाचे प्रमुख श्रीकृष्ण घोलप, सहकार भारती पुणे जिल्हा बँक प्रकोष्ठ प्रमुख सीए डॉ. केतन जोगळेकर, सहकार भारती राष्ट्रीय पतसंस्था प्रकोष्ठ प्रमुख शिरीष देशपांडे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन समिती सदस्य डॉ. रवींद्र शिंगणापूरकर, सहकार भारती ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष विनायक तांबे, सहकार भारती पिंपरी चिंचवड महानगरचे अध्यक्ष दशरथ जाधव, प्रदेश कोषप्रमुख औदुंबर नाईक उपस्थित होते.

**\* विविध सहकारी संस्थांचा सहभाग –**

महोत्सवासाठी यशदा, पुणे महानगरपालिका, सावित्रीबाई फुले पुणे

विद्यापीठ आणि पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे सहकार्य लाभले. महोत्सवात सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, ग्रामीण आदिवासी उद्योजक तसेच अन्नप्रक्रिया, हस्तकला, वस्त्र, इमिटेशन दागिने, सेंट्रिय व आयुर्वेदिक उत्पादने, वनाधारित उद्योग आणि महिला बचत गट अशा विविध सहकारी संस्था सहभागी झाल्या होत्या. एकूण १२५ स्टॉल महोत्सवात होते.

**\* चळवळ यशस्वी होण्यास नेतृत्व महत्वाचे –**

कोणतीही चळवळ यशस्वी होण्यास किंवा लयास जाण्यास त्या चळवळीचे नेतृत्व कारणीभूत असते, असे नमूद करून ते म्हणाले, सहकार क्षेत्राला लाभलेल्या सहकार भारतीच्या नेतृत्वामुळे सहकार चळवळ सर्वांथाने प्रगती करित आहे. सहकार भारतीमुळे सहकार चळवळीला नैतिक अधिष्ठान लाभले आहे. सहकार क्षेत्र हा खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा सुवर्णमध्य आहे. स्व. लक्ष्मणराव इनामदार यांनी सहकार क्षेत्रासंदर्भात आखून दिलेल्या वाटेवर सहकार भारती ही संस्था चालत असल्याने सहकार भारतीकडे नैतिक नेतृत्व म्हणून पाहिले जाते. सहकारातील चुकीच्या गोष्टींमुळे सहकार चळवळ अधोगतीला जात होती. सहकार भारतीने या चळवळीला सावरण्याचे काम केले आहे. राजकारण्यांना त्यांचे राजकारण घडवून आणण्यासाठी द्रव्य आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. द्रव्य आणि मनुष्यबळ हे सहकाराचे बलस्थान असल्याने अनेक राजकारणी सहकार क्षेत्रात आले. तळागाळापर्यंत सहकार क्षेत्र पोहोचत नाही, तोपर्यंत सहकार क्षेत्राचा उद्देश खऱ्या अर्थाने साध्य होणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. काही वर्षांपूर्वी शालेय स्तरावर सहकार भांडारे कार्यरत होती आणि या मध्यमातून सहकार क्षेत्राची ओळख विद्यार्थ्यांना होत असे. मात्र आता ही भांडारे कालबाह्य



महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महोत्सवास सदिच्छा भेट दिली.

झालेली आहेत, असे ते म्हणाले.

**\* सुसंस्कारित सहकार व्यापक व्हावा -**

देशपांडे म्हणाले की, महोत्सवांच्या माध्यमातून सुसंस्कारित सहकार सर्वदूर पसरणे आवश्यक आहे. आसाम, मेघालय, मणिपूरपासून २८ राज्य आणि ६५० जिल्ह्यांमध्ये सहकार भारती कार्यरत आहे. लहान आणि छोट्या व्यावसायिकांना चालना देण्यासाठी महोत्सवांची गरज आहे. डॉ. शिंगणापूरकर म्हणाले की, महाराष्ट्राला सहकाराची कर्मभूमी मानले जाते. दुर्दैवाने सहकारावर झालेल्या गैर आक्रमणांमुळे सहकार क्षेत्र स्वार्थाकडे गेलेले दिसते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुरू करण्यात आलेल्या विखे पाटील अध्यासनामार्फत सहकार क्षेत्राची तत्वे तळगाळापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. सुहास पटवर्धन यांनी मनोगत व्यक्त केले.

**\* 'धे भरारी' स्मरणिका प्रकाशन -**

भारत माता आणि स्व. लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून महोत्सवास प्रारंभ करण्यात आला. भाग्यश्री सखी फाउंडेशनच्या भाग्यश्री बोरकर यांच्या 'धे भरारी' या स्मरणिकेचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. प्रास्ताविक कुलकर्णी यांनी केले. ते म्हणाले, सहकार भारतीची आजवरची वाटचाल तसेच सहकार क्षेत्राला मूल्य आणि संस्कार याची जोड देण्याचा प्रयत्न सहकार भारतीच्या वतीने केला जात आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राचे चांगले स्वरूप अधिक विकसित होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सहकार भारती वाटचाल करीत आहे.

मिलिंद कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन आणि भवाळकर यांनी आभार मानले. महोत्सवात 'सहकार आणि वाणिज्य क्षेत्रातील करिअरच्या वाटा'

यावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विखे पाटील अध्यासनाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल कारंजकर यांचे मार्गदर्शन सत्र झाले.

**\* महोत्सवाला महापौर मंजुषा नागपुरे यांची सदिच्छा भेट -**

सहकार महोत्सव म्हणजे सहकार, व्यवसाय आणि समाज यांना जोडणारा पूल आहे, असे नमूद करून त्या म्हणाल्या की अशा स्वरूपाचा महोत्सव ठिकठिकाणी होण्याची गरज आहे. त्यामध्यमातून विविध उपक्रम करण्यात यावेत. सहकारी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सबल होण्यासाठी महोत्सव होणे गरजेचे आहे. संस्कार आणि सहकार यांची सांगड अधिक व्यापक प्रमाणावर घालण्याची गरज आहे.

सहकार क्षेत्रात जे विविध घटक कार्यरत आहेत, ते सक्षम होण्यास हातभार लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महिला उद्योजक यांना चांगले व्यसपीठ उपलब्ध झाले आहे. आगामी काळात व्यापक स्वरूपात महोत्सव आयोजित करण्यात यावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी विविध स्टॉलना भेटी देऊन माहिती घेतली.

**\* विविध स्पर्धांचा बक्षीस समारंभ -**

महोत्सवाच्या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या निबंध लेखन, डिजिटल पोस्टर मेकिंग आणि काव्य वाचन स्पर्धा बक्षीस समारंभ आणि महोत्सवाच्या कालावधीत स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या युवक यांना प्रमाणपत्र प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. मोरेश्वर सुखदेवे, महोत्सव प्रमुख श्रीकृष्ण घोलप, विनायक तांबे, डॉ. राजश्री जायभाय, अनिल कारंजकर, गिरीश भवाळकर आदी यावेळी उपस्थित होते. तीन दिवसीय महोत्सवात अंदाजे १५ हजार पेक्षा अधिक



महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी महोत्सवास भेट दिली.



महोत्सवाच्या समारोपास बोधिसत्व सहकारी रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉ.मोरेश्वर सुखदेवे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विखे पाटील, सहकार अध्यासनाचे प्रमुख अनिल करंजकर सर उपस्थित होते. त्यांचे स्वागत व सन्मान महोत्सव प्रमुख श्रीकृष्ण घोलप यांनी केले.

नागरिकांनी भेट दिली तर २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल झाली असल्याचा अंदाज आहे.

✽ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी युवकांनी हातभार लावावा -

ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी युवकांनी सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून उद्योग उभारावेत, यामधून रोजगार निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास हातभार लागेल असे मत प्रा. अनिल करंजकर यांनी सहकार महोत्सवातील सहकारातून रोजगार निर्मिती या चर्चासत्रात बोलतांना व्यक्त केले.

सहकारी संस्थांनी वाजवी नफा मिळविणे योग्य आहे, असे नमूद करून ते म्हणाले. सहकारी संस्थामध्ये लोकशाही पद्धतीने निर्णय होत असतो. मात्र खासगी संस्थामध्ये ज्याच्याकडे भाग भांडवल अधिक आहे. तो नियंत्रण खासगी संस्थेवर ठेवतो. सहकारी संस्था या व्यावसायिक असून त्यांनी

नफ्याबाबत जागरूक राहायला हवे. पण ते अंतिम उद्दिष्ट असता कामा नये सध्याच्या काळात नोकरी मिळणे अवघड होत आहे.

परिणामी युवकांना स्व. रोजगारशिवाय पर्याय नाही यासाठीचे भांडवल उभारणे, जागा मिळविणे वितरण व्यवस्था याची गरज आहे. तसेच ग्रामीण भागात लहान स्वरूपात सहकारी संस्था युवक स्थापन करू शकतात. यामधून रोजगार निर्मिती होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला अधिक चालना मिळणार आहे.

महोत्सवास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार हेमंत रासने, मध्य प्रदेशातील खासदार नरेंद्र वर्मा, विद्या सहकारी बँक संचालक प्रदीप गारटकर, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे आदींनी भेट दिली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

## यवतमाळ अर्बन बँकेतर्फे विदर्भस्तरीय सहकार परिषद

### स्व.लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती निबंध स्पर्धेचे बक्षीस वितरण

यवतमाळ - आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचे औचित्य साधून यवतमाळ अर्बन बँकेतर्फे विदर्भस्तरीय सहकार परिषद आणि स्व. लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती निबंध स्पर्धेचा बक्षीस वितरण पार पडला. सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी आणि आरबीआय संचालक सतीश मराठे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर कोहरे सहकार भारतीचे प्रदेश महामंत्री विवेक जुगादे होते. प्रास्ताविकात बँकेचे अध्यक्ष डॉ. नितीन खर्चे यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने नेट एनपीए शून्य टक्के करून नेत्रदीपक प्रगती केल्याचे सांगितले. सहकार भारतीचे प्रेरणास्रोत स्व. लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या जीवनावर आधारित डॉ. खर्चे यांच्या पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले.

यवतमाळचे उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी शुभेच्छा देताना बँकेने सहकार परिषद घेऊन एक चांगला उपक्रम राबविल्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी सहकार परिषदेचे उद्घाटन करताना, सांगितले की, सन २०१४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, अशी स्थिती होती. परंतु, गेल्या १० वर्षात उल्लेखनीय परिवर्तन झाल्याचा आवर्जून उल्लेख केला.



विदर्भस्तरीय सहकार परिषदेचे दीपप्रज्वलन करताना रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे, डावीकडे सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी आणि उजवीकडे बँकेचे अध्यक्ष डॉ. नितीन खर्चे.

सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी यांनी बँकेने ३ हजार कोटींचा व्यवसाय पूर्ण करून भरारी घेतली असल्याचे सांगितले. सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून सहकार परिषदेला शुभेच्छा दिल्या. सहकार वर्षानिमित्त बँकेने घेतलेल्या लक्ष्मणराव इनामदार स्मृती राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचा निकाल घोषित करण्यात आला.

एकूण ४ गटांत झालेल्या या स्पर्धेसाठी राज्यभरातून तीन हजार स्पर्धकांनी सहभागी झाले. सर्व विजेत्यांना

रोख रक्कम स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. उपाध्यक्ष अजिंदरसिंह चावला यांनी स्पर्धेविषयी माहिती सांगितली.

समारोपप्रसंगी सहकार भारतीचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री संजय पाचपोर म्हणाले, शेवटच्या माणसाच्या जीवनात उन्नती सहकाराच्या माध्यमातूनच येऊ शकते. म्हणूनच जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सहकारी संस्था सुरू झाल्या पाहिजेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बँकेचे सहस्रव्यवस्थापक गजानन वैद्य यांनी उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.

## सहकार चळवळीच्या विस्तार व सक्षमीकरणासाठी ग्रामीण भागात संशोधन हवे

**पुणे** – सहकार चळवळीच्या विस्तारासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी ग्रामीण भागात संशोधन व्यापक प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे, असे मत आरबीआय संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकार अध्यासन आणि इंडियन सोसायटी फॉर स्टडीज इन को-ऑप. यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

विद्यापीठाचे प्रकुलगुरु डॉ. पराग काळकर, अध्यासनाचे माजी प्रमुख डॉ. मुकुंद तापकीर, माजी सहकार अपर आयुक्त दिनेश औडळकर, सहकार सुगंध मासिकाचे संपादक भालचंद्र कुलकर्णी उपस्थित होते. मराठे यांनी सांगितले की, संशोधन आणि नवोन्मेष यांच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम होऊ शकते. सहकार क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी ग्रामीण भागातील संशोधनावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.



डॉ. काळकर म्हणाले की, सहकार आणि शाश्वत विकासासाठी एआय आधारित संशोधनावर विद्यार्थी आणि संशोधक यांनी भर द्यावा तसेच डिजिटल युगात सहकार क्षेत्राने नवीन संधीचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. अध्यासनाचे प्रमुख अनिल कारंजकर यांनी प्रास्ताविकात अध्यासनाची माहिती सांगितली. डॉ. पूनम शिंदे यांनी सूत्रसंचालन तर आनंद यादव यांनी आभार मानले.

## सोलापूर सहकार भारती आयोजित उद्योजकता महोत्सवास उस्फूर्त प्रतिसाद



**सोलापूर** – सहकार भारती सोलापूर जिल्हा यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला 'Women Expo for Women Empowerment' हा महिला उद्योजकांसाठी महोत्सव उत्साहात २४ ते २६ एप्रिल २०२६ या कालावधीत झाला. या उपक्रमाने 'महिला सक्षमीकरणाच्या' दिशेने एक ठोस आणि आशादायी पाऊल टाकले आहे.

प्रदर्शनात तब्बल ११० स्टॉल्सच्या माध्यमातून

विविध क्षेत्रातील महिला उद्योजकांनी कष्ट, जिद्द आणि आत्मविश्वास यांचे सुंदर दर्शन घडवले. सर्व उद्योजकांना विनामूल्य स्टॉल देण्यात आले होते. प्रत्येक स्टॉल हा केवळ व्यवसाय नव्हता, तर एका महिलेच्या संघर्षाची, स्वप्नांची आणि यशाकडे वाटचाल करणाऱ्या प्रवासाची कहाणी होती. महिलांनी स्व कर्तृत्वाने सिद्ध केले की, संधी मिळाल्यास महिला कोणत्याही क्षेत्रात

उल्लेखनीय कामगिरी करू शकतात.

प्रदर्शनाचे उद्घाटन महिला भाजपा प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ यांचे हस्ते तर सहकार भारती प्रदेश संघटन मंत्री शरद जाधव सोलापूर महापौर विनायक कोंड्याल, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती दिलीप माने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शहाजी पवार यांचे उपस्थितीत करण्यात आले.

सोलापूर वासियांनी या महिला उद्योजकांना भरभरून प्रोत्साहन दिले. तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमात सुमारे ४० हजार लोकांनी भेट दिली तर सर्व उद्योजकांचा एकूण व्यवसाय लाखांमध्ये झाला.

समारोपास सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेश संपर्क प्रमुख संजय परमणे व औदुंबर नाईक प्रदेश कोष सह प्रमुख उमेश विरदे प्रदेश दुग्ध प्रकोष्ठ प्रमुख, जयवंत शेळगीकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, कार्यक्रम अध्यक्षा सुधा अळळीमोरे, संतोष गायकवाड, विभाग प्रमुख, किरण करकमकर जिल्हाध्यक्ष, यशवंत बुन्हाडे, जिल्हा महामंत्री उपस्थित होते यावेळी तरुण भारतच्या विशेष अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

## जनता सहकारी बँकेचा १७,५०० कोटींचा एकूण व्यवसायाचा टप्पा पूर्ण

**पुणे** – जनता सहकारी बँकेने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात १७,५०० कोटींचा व्यवसायाचा टप्पा पूर्ण केला आहे. बँकेने वर्षभरात ठेवी वाढ, कर्ज वाटप आणि एकूण व्यवसायात वाढ केली आहे.

ठेवी १०८११.४० कोटी तर कर्ज वाटप ६७११.२१ कोटी झाले आहे तर एकूण व्यवसायात १२९० कोटी इतकी वाढ झाली आहे. तो वाढून १७५२२.६१ कोटी इतका झाला आहे. बँकेच्या सध्या महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात ७१ शाखा आणि २ विस्तारित कक्ष कार्यरत आहेत.

## एमआयडीसी कार्यालयास सहकार भारती पदाधिकाऱ्यांची भेट

**मुंबई** – सहकार भारती वायव्य विभागाचे महामंत्री योगेश राणे सहसंघटन प्रमुख स्मिता मोटे, महिला प्रमुख मनीषा चव्हाण यांनी एमआयडीसी कार्यालयास भेट दिली आणि सहकार भारतीच्या कार्याबाबत सविस्तर माहिती सांगितली.

सहकार भारती विविध प्रकारच्या सहकारी क्षेत्रांमध्ये कसे कार्य करते, याचेही स्पष्टीकरण करण्यात आले. मोटे यांनी हौसिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांसाठी हेलप डेस्क सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली. चव्हाण यांनी सांगितले की, या हेलप डेस्कमुळे नागरिकांना कायदेशीर बाबी समजून घेण्यास व त्यासाठी तयारी करण्यास देखील मदत होईल.

# सहकारी बँकांनी विश्वासाहतेबरोबरच बँकिंग साक्षरता वाढवण्याची गरज आरबीआय संचालक सतीश मराठे यांची सूचना

## सहकार सुगंध प्रकाशनाचे 'बँकिंग साक्षरता' प्रकाशित



‘बँकिंग साक्षरता’ पुस्तक प्रकाशन प्रसंगी छायाचित्रात डावीकडून भालचंद्र कुलकर्णी, अजय ब्रह्मेचा, राधेशाम चांडक, मिलिंद काळे, अनिल कवडे, सतीश मराठे, डॉ. उदय जोशी, विवेक जुगादे आणि गणेश निमकर.

पुणे - दैनंदिन व्यवहारात नागरी सहकारी बँकांनी बदलत्या काळानुसार सर्वेक्षण बदल करणे गरजेचे आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगात गुंतवणूकदारांबरोबरच कर्जदार देखील चिकित्सक झाला आहे, त्यामुळे विश्वासाहता जपण्याबरोबरच बँकिंग साक्षरता वाढवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचे संचालक सतीश मराठे यांनी येथे सांगितले.

सहकार सुगंध आयोजित ‘बदलते बँकिंग’ या परिसंवादात ते बोलत होते. जागतिक पुस्तक दिनाचे औचित्य साधून ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ गणेश निमकर लिखित ‘बँकिंग साक्षरता’ या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले. त्यानिमित्ताने परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी, राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे, बुलडाणा क्रेडिट सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक, नॅफकबचे उपाध्यक्ष मिलिंद काळे, महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष अजय ब्रह्मेचा, सहकार भारतीचे प्रदेश महामंत्री विवेक जुगादे, सहकार सुगंध मासिकाचे संपादक भालचंद्र कुलकर्णी आणि पुस्तकाचे लेखक गणेश निमकर व्यासपीठावर उपस्थित होते. राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे आणि राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी तृक्श्राव्य माध्यमातून यावेळी शुभेच्छा दिल्या.

### \* आर्थिक साक्षरता वाढविण्याची गरज -

परिसंवादात मराठे म्हणाले की, सध्याच्या स्थितीमध्ये देशातील किमान ५० टक्के जनता बँकिंग क्षेत्रापासून दूर आहे. त्याचबरोबर आर्थिक साक्षरता वाढावण्याची गरज आहे. एकीकडे गुंतवणूकदारांची संख्या वाढत आहे, कर्ज व्यवहार वाढत आहेत, तर दुसरीकडे व्याजदर दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. या बदलत्या बँकिंगच्या दृष्टीने ग्राहकांमध्ये बँकिंग साक्षरता होणे आवश्यक असून त्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरणारे आहे. जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकेत काही संचालक वर्षानुवर्षे कार्यरत आहेत तर काही बँका या मुख्य कार्यकारी अधिकारीच चालवितात. नव्या लोकांना आणि विशेषतः तरुणांना सहकारात काम करण्यास वाव मिळावा, यादृष्टीने नागरी सहकारी बँकांमध्ये संचालकांना असलेला दोन टर्म कालमर्यादित कायदा योग्यच असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. केंद्र सरकारचे नियम सर्वच बँकांना बंधनकारक आहेत. नागरी बँकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आता स्वतंत्र फोरमदेखील निर्माण केला आहे.

### \* नवीन परवाना बाबत धोरण? -

डॉ. जोशी म्हणाले की एकूणच बँकांची संख्या कमी करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. तर नवीन बँक परवान्याबाबत नेमके धोरण अद्याप ठरलेले नाही. याबाबत सहकार मंत्रालयाने नव्याने अभ्यास गट नियुक्त

पुढील पानावर...



सहकारी बँकांनी काळानुसार आवश्यक ते बदल दैनंदिन व्यवहारात करणे गरजेचे आहे. आज एकीकडे गुंतवणूकदार संख्या आणि कर्ज व्यवहार वाढत आहेत. हे लक्षात घेता ग्राहक साक्षरता आणि त्यांना खात्री देणे आवश्यक आहे यासाठी ‘बँकिंग साक्षरता’ पुस्तक उपयुक्त आहे असे मत आरबीआय आणि नाबार्ड संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले आहे.

सध्याच्या स्थितीमध्ये देशातील किमान ५० टक्के जनता बँकिंग क्षेत्रापासून दूर आहे त्याचबरोबर आर्थिक साक्षरता वाढावी गरजेचे आहे. एकीकडे गुंतवणूकदार संख्या वाढत आहे तर कर्ज व्यवहार वाढत आहेत दुसरीकडे व्याजदर कमी होत आहे. या सर्व बाबींबाबत साक्षरता होणे आवश्यक असून त्यासाठी पुस्तक उपयुक्त ठरणार आहे.



मागील पानावरून...

## सहकारी बँकांनी विश्वासाहतेबरोबरच बँकिंग साक्षरता

केला असून त्याबाबत विचार विनिमय सुरू आहे. निवडक मोठ्या काही पतसंस्थांचे रूपांतर नागरी बँकेमध्ये करण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे सुमारे २००३ पासून नवीन बँकेला परवानगी मिळालेली नसल्याने परिणामी पतसंस्था वाढीस प्राधान्य मिळाले आहे.

### \* सामाजिक बँकिंग क्षेत्र वाढविण्याची गरज -

चांडक म्हणाले की, यापुढील काळाची गरज लक्षात घेता सामाजिक बँकिंग क्षेत्र वाढविण्यावर जास्तीत जास्त भर देण्याची गरज आहे. या उपक्रमामुळे बँकिंग क्षेत्रातील ठेवी वाढण्यास मदत होणार आहे. आम्ही गेली अनेक वर्षे जाणीवपूर्वक हा प्रयत्न करीत आहोत. आयुक्त कवडे यांनी सांगितले की, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च कमी व्हावा असा प्रयत्न आहे. यासाठी डिजिटायझेशनवर अधिक भर देण्याची योजना सुरू केली आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासाहता देखील वाढणार आहे. निवडणुकीसाठी इव्हीएम यंत्रणेचा वापर करावा यासाठी निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव दिला आहे, यादृष्टीने निवडणूक प्राधिकरणाने नवीन सॉफ्टवेअर देखील तयार केले आहे.

### \* विलीनीकरण प्रक्रिया अनिवार्य -

काळे म्हणाले की, आजवर कॉसमॉस बँकेत १९ बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. जेथे व्यवसायिकदृष्ट्या चुकीचे निर्णय झाले होते, तेथील सहकारी बँकांचे कॉसमॉस बँकेमध्ये विलीनीकरण करून घेतले आहे. मात्र जेथे भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब झाल्याने बँक अडचणीत आली आहे, अशा बँका घेतलेल्या नाहीत विलीनीकरणाच्या माध्यमातून नवीन भागात शाखा विस्तार आणि व्यवसाय वाढीस मोठी संधी आहे तर ब्रम्हेचा म्हणाले की, सध्याच्या काळात बँकांसाठी नवीन परवाने मिळणे अवघड आहे. पतसंस्थांचे रूपांतर बँकेत करता येणे शक्य होणार आहे. याबाबत विविध पतसंस्थांबरोबर चर्चा सुरू आहे.

जुगादे यांनी सांगितले की, राज्याचे नवीन सहकार धोरण तयार होत असतांनाच सहकार कायदा देखील नव्याने तयार होत आहे. नवीन स्पर्धात्मक

युगाचे भान, तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर आणि तरुणांच्या सहकाराकडून अपेक्षा यांचा समावेश नव्या कायद्यात व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहोत.

### \* पुस्तक लेखनामागची भूमिका -

पुस्तकाचे लेखक निमकर यांनी पुस्तक लेखनामागची भूमिका मांडताना सांगितले की, बँकिंग क्षेत्राबाबत आजवर तीन पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली आहेत. केवळ सहकारी बँक नाही तर आणि सर्व बँकांचा विचार करण्यात आला आहे. लेखनाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात अथवा जे या क्षेत्रात कार्यरत नाही, त्यांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक साक्षरता आणि बँकिंग साक्षरता हे दोन विषय स्वतंत्र आहेत. केवळ बँक नाही तर पतसंस्था ठेवीदार आणि अन्य घटकांना पुस्तक उपयुक्त ठरणार आहे.

### \* सकारात्मक सहकार सर्वत्र पोचावा -

संपादक कुलकर्णी यांनी स्वागत करताना स्पष्ट केले की, जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे गेली काही वर्षे पुण्यात पुस्तक महोत्सव आयोजित करण्यात येत आहे.

परिणामी आगामी काळात पुणे शहर पुस्तकाची राजधानी व्हावी. यावेळी त्यांनी सहकार सुगंध मासिकाची गेल्या २२ वर्षांची वाटचाल, तसेच सहकार महर्षी ग्रंथ याबाबत सविस्तर माहिती सांगितली. सहकार सुगंध मासिक मराठीसह हिंदी इंग्रजी भाषेत प्रकाशित करण्यात येते, अशी माहिती त्यांनी सांगितली. सकारात्मक सहकार सर्वत्र पोचावा हा त्यामागचा हेतू आहे, असे ते म्हणाले.

सुरुवातीला भारत माता पूजन करण्यात आले. त्यानंतर कॉसमॉस सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष स्व. डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांना शांतिमंत्र म्हणून दोन मिनिटे उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन स्नेहल दामले यांनी केले. पुस्तकाच्या निर्मितीसाठी योगदान देणारे जयंत काकतकर, राजेंद्र पोतनीस, प्रमोद महाजन आणि प्रणिता महाजन यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.



# लोकसहभागातून नवे सहकार धोरण करणार -सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई - राज्याचे नवीन धोरण अधिक सक्षम करण्यासाठी सहकार भारतीच्या माध्यमातून सूचना शासनाला मिळाल्या आहेत. सहकार धोरण बनविण्यासाठी सहकार भारतीने सहकार क्षेत्रातील तज्ञ मंडळींसोबत संवाद साधून त्यांची मते जाणून घेतली आहेत. सर्व सूचनांवर विचार करून लोकसहभागातून नवे सहकार धोरण तयार करू असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

राज्याचे नवे सहकार धोरण ठरविण्यासंदर्भात राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. पणमंत्री जयकुमार रावल, सहकार सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, नाबार्डच्या मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीमती रश्मी दराद उपस्थित होते. सहकार भारतीचे महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री व राज्य सहकार धोरण उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य जुगादे यांनी सहकार धोरणासंदर्भातील अहवाल सहकारमंत्री पाटील सादर केला.

राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचेही सहकार धोरण लवकरच तयार केले जाणार असून नवे सहकार धोरण हे सर्वसमावेशक व सखोल अभ्यास करून केले जाणार आहे. सहकार धोरण हे अधिक सक्षम व भ्रष्टाचारमुक्त व्हावे, अशी मागणी जुगादे यांनी समिती सदस्यांपुढे केली. बैठकीत सहकार क्षेत्रासाठी उपयुक्त असलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींचे सादरीकरण करतांना ते म्हणाले की, देशामध्ये सन २०२१ मध्ये



सहकाराचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर देशाचे गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्र अधिक गतीने कार्य करीत आहे. काही प्रमाणात कमी झालेला सहकार क्षेत्रावरील विश्वास आता पुन्हा वृद्धिंगत होत आहे.

बैठकीला समितीचे सदस्य डॉ. संतोष कोरपे, माजी सहकार आयुक्त मधूकर चौधरी, अप्पर निबंधक व सचिव संतोष पाटील, अप्पर निबंधक राजेश सुरवसे, हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, राज्य साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

## सहकाराची ताकद वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण हाच उत्तम पर्याय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे - कोणत्याही क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रशिक्षणाला पर्याय नाही. सहकार क्षेत्राची ताकद वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण हाच उत्तम पर्याय आहे. नफा कमावणाऱ्या सहकारी संस्थांना भार वाटणार नाही इतके नाममात्र शुल्क आकारून प्रशिक्षण देता यावे, यासाठी सहकार विभागाने प्रस्ताव सादर करावा, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या येथील संचालक मंडळाच्या कार्यालयाचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, आमदार सुनील कांबळे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, राज्य सहकारी संघाचे संचालक संजीव कुसाळकर, शिवाजीराव नलावडे आदी उपस्थित होते.

प्रशिक्षणासाठी चांगली वास्तू आवश्यक असून तेथील वातावरण चांगले पाहिजे, असे नमूद करून ते म्हणाले, प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधी खर्चाचे काटेकोर नियोजन आराखडा तयार करावा. प्रशिक्षणाच्या खर्चातून शिक्षण निधी वजा करून, येणारी तूट लक्षात घेऊन त्याच्या खर्चास पावसाळी अधिवेशनामधील पुरवणी मागण्यांमध्ये सादर करण्यात येईल. राज्य सहकारी संघाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. राज्यात सहकार विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. परंतु सद्या त्याची सुरुवात राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये सहकार विभाग सुरू करून त्या-त्या विद्यापीठांमध्ये सहकार विषयाचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील.

दरेकर म्हणाले, राज्य सहकारी संघाला १०० वर्षांची परंपरा आहे. सहकार



क्षेत्राला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी सहकारी संघ बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सहकार चळवळीला दिशा देण्यासाठी संस्थांमध्ये आत्मविश्वास असला पाहिजे. सहकारी संस्थांनी सामाजिक दायित्व जपले पाहिजे. राज्यातील अडीच लाख सहकारी संस्थांना हक्काचे प्रशिक्षण केंद्र देण्याचा मानस असून त्यासाठी सुसज्ज प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून मिळवावा सहकारी संघांचा बंद झालेला शिक्षण निधी सुरू करावा. चळवळीला सशक्त करण्यासाठी

राज्य शासनाच्या पाठबळाने निश्चित गती देण्यात येईल. राज्यातील सहकार चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ताकद देण्याचे काम करण्यात येईल. त्यासाठी राज्यातील सहकाराचे पालकत्व शासनाने घ्यावे.

आमदार सुनील कांबळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आयुक्त तावरे यांनी सांगितले की, देशातील ८० हजार विकास सोसायट्यांमध्ये केंद्राच्या योजनेतून राज्यात १२ हजार सोसायटी यांचे संगणकीकरण पूर्ण केले आहे. त्यासाठी गटसचिव यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यांचे लेखापरीक्षण ऑनलाईन पूर्ण करण्यात आले आहे.

बँक प्रशासक अनास्कर यांनी सांगितले की, सहकार शिक्षणातून विचार मिळतो आणि अंमलबजावणी प्रशिक्षणातून मिळते. राज्य सहकारी संघाने हे काम करायला हवे, त्यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र आर्थिक तरतूद होणे गरजेचे आहे. तसेच सहकार धोरणाला अधिक गतिमान करायला हवे.

सुरुवातीला सुनंदा सुपनेकर यांनी स्वागत आणि सूत्रसंचालन केले. मानद सचिव रामदास मोरे यांनी प्रास्ताविक आणि उपाध्यक्ष अर्जुन बोरुडे यांनी आभार मानले.

# सहकार सुगंध मासिकाचे जिल्हा प्रतिनिधी मेघराज जाधव पुरस्काराने सन्मानित



मुरुड, रायगड - सहकार सुगंध मासिकाचे जिल्हा प्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ पत्रकार मेघराज जाधव यांना मुंबई विश्व संवाद केंद्राच्या वतीने देवर्षी नारद पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान करून नुकतेच सन्मानित करण्यात आले.

चिपळूण येथील डी.बी.जे. महाविद्यालयात हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. सन्मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ आणि रोख २१ हजार रुपये असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. यावेळी राजेश जोष्टे, अभिजीत जोग आणि प्रसाद काथे उपस्थित होते. जाधव यांच्या यशाबद्दल त्यांचे अनेकांनी अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.

## योगीराज पतसंस्थेला साडेचार कोटींचा नफा

पुणे - येथील योगीराज सहकारी पतसंस्थेने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात ४ कोटी ५५ लाख रुपयांचा नफा मिळविला असून सदस्यांना १५ टक्के लाभांश जाहीर करण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षात संस्थेने ४०० कोटी व्यवसायाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, अशी माहिती अध्यक्ष ज्ञानेश्वर तपकिर यांनी सांगितली.

ते म्हणाले, संस्थेच्या १६२ कोटीच्या ठेवी असून १३० कोटी कर्ज देण्यात आले आहे. संस्थेने ६८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. एकत्रित व्यवसाय १९२ कोटी झाला असून ६७.६९ टक्के सीडी रेशो राखण्यात यश मिळविले आहे. पतसंस्थेच्या वतीने विविध समाजोपयोगी योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहेत.

## बिresh्वर को ऑप. क्रेडिट सोसायटी संचालक सल्लागारपदी शिरीष देशपांडे

पुणे - येथील बिresh्वर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीच्या संचालक सल्लागारपदी शिरीष देशपांडे यांची निवड करण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवड सहकारी बँक अध्यक्ष आणि

सहकार भारती पतसंस्था प्रकोष्ठप्रमुख म्हणून ते कार्यरत आहेत.

बाळासाहेब देवरस रुग्णालयाचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे आहे.

## तिरुपती सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी गोविंद मुंदडा

पुणे - येथील तिरुपती सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी गोविंद मुंदडा यांची निवड करण्यात आली आहे. भाग भांडवल ३ कोटी ४४ लाख रुपये असून १३७ कोटी ६० लाख ठेवी आहेत. ९८ कोटी १२ लाख कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. खेळते भांडवल

१६५ कोटी ४६ लाख इतके आहे. संस्थेला ऑडिट वर्ग अ मिळाला आहे.

अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल संचालक तसेच अधिकारी, कर्मचारी, खातेदार, हितचिंतक यांनी मुंदडा यांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.



कर व व्यापारी विषयक कायद्यातील क्लिष्ट विषयांची सहज सोप्या भाषेत माहितीसह आर्थिक गुंतवणूक, आरोग्याविषयी माहिती देणारे व्यापारी बांधवांचे हक्काचे एकच व्यासपीठ

स्थापना १९५०

# व्यापारी मित्र

मासिकातील एखाद्या माहितीने आपला लाखो रुपयांचा फायदा होऊ शकतो.

संस्थापक संपादक : स्व. श्री. जी. डी. शर्मा

Payment Gateway link



भारतात कुठेही  
निश्चित अंक मिळण्यासाठी  
मॅगझीन पोस्टिंगसह वर्गणीदर

| ३ वर्षासाठी | २ वर्षासाठी | १ वर्षासाठी |
|-------------|-------------|-------------|
| २९००        | २०००        | १०५०        |

'परशुराम कुटी', १०६/९, एरंडवणा, पुणे - ४११००४  
फोन (०२०) २५४३ १०९४ (W) : 94218 80290  
E-mail : sampadak@vyaparimitra.com



## पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, पुणे

स्थापना ४ सप्टेंबर १९१७

मुख्य कार्यालय - ४ ब, बी.जे.रोड, पुणे - ४११ ००१

फोन नं. : ०२० २६३०४१०० www.pdccbank.com

१०७ वर्षांचा गौरवशाली इतिहास असणारी देशातील अग्रगण्य जिल्हा बँक

\* बँकेच्या विविध कर्ज योजना \*

- शेतीपूरक कारणासाठी अ. गु. कर्ज
- वाहन कर्ज
- सोनेतारण कर्ज
- शेतीकर्ज - शासकीय अनुदानित कर्ज योजना - १०.५०%
- व्यावसायिक कॅश क्रेडिट
- ग्राहक उपयोगी वस्तू कर्ज
- औद्योगिक कर्ज
- गृह कर्ज

\* बँकेच्या अत्याधुनिक सुविधा \*

- एनी ब्रँच बँकींग
- आरटीजीएस
- एनईएफटी
- मोबाईल बँकींग
- यूपीआय सुविधा
- ई-कॉमर्स
- लॉकर सुविधा उपलब्ध

\* किफायतशीर व्याजदर

\* जलद कर्ज पुरवठा

\* सुलभ कर्ज प्रक्रिया

बँकेची आर्थिक स्थिती  
३१/०३/२०२५ अखेर

- ठेवी - १४७६६.८४ कोटी
- कर्ज - १२०५९.०३ कोटी
- एकूण व्यवसाय - २६८२५.८७ कोटी

आकर्षक व्याजदर

दि. २३/०६/२०२५ पासून  
ठेवीवरील व्याजदरात वाढ  
२ वर्षांकरिता ७.००%  
(ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक  
१% व्याजदर)

\* विद्यमान संचालक मंडळ \*

मा.प्रा.डॉ. दिगंबर गणपत दुर्गाडे  
अध्यक्ष

मा. अनिरुद्ध यशवंत देसाई  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मा. सुनील काशिनाथ चांदेरे  
उपाध्यक्ष

अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा.

# डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा २०२३ - सहकारी बँकांपुढे आव्हान

## \* DPDP कायद्याची पार्श्वभूमी -

निवृत्त न्यायाधीश पुट्टस्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार या याचिकेत निवृत्त न्यायाधीश श्री. पुट्टस्वामी यांनी केंद्र सरकारच्या आधार योजनेमुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचे सांगत त्या योजनेला आव्हान दिले होते.

सदर याचिकेत केलेली विनंती ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने मान्य करत गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हा भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत 'मुलभूत अधिकार' असल्याचे घोषित केले. या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पूर्वीच्या निर्णयांना अमान्य करण्यात आले.

तद्नंतर केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार माहिती संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश श्री. बी. एन्. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. सदर समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार सन २०१९ मध्ये 'माहिती संरक्षण' विधेयक सादर केले गेले. तथापी त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदीमुळे ते मागे घेण्यात आले. तद्नंतर सदर विधेयकात काही दुरुस्त्या करण्यात येऊन कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या विधी विभागाने दि. ११ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या राजपत्राद्वारे डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण अधिनियम २०२३ अंमलात आणला. अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण नियम २०२५ द्वारे हा कायदा अधिकच सक्षम करण्यात आलेला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी १८ महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने म्हणजेच दि. १४ मे २०२७ पर्यंत संबंधितांनी करावयाची आहे.

## \* DPDP कायद्याचे महत्त्व -

भारतीय नागरिकांच्या माहितीची गोपनीयता राखण्याच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या डिजिटल स्वरूपातील वैयक्तिक माहितीच्या प्रक्रियेचे नियंत्रण करण्यासाठी अंमलात आणलेला हा महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा ग्राहकाच्या डिजिटल वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करताना पारदर्शकता, जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि ग्राहकाची संमती यावर भर देतो. शिवाय हा कायदा डिजिटल कंपन्यांना माहितीच्या गोपनीयतेचा भंग केल्यास जबाबदार धरतो व त्यांचेवर दंडात्मक कारवाई करतो.

भारतात डिजिटल तंत्रज्ञानात क्रांती होत असताना भारतीय नागरिकांच्या माहितीच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. भारताच्या डिजिटल प्रणालीमध्ये दररोज बँकिंग, ई-कॉमर्स, आरोग्य सेवा, दूरसंचार आणि शासकीय सेवांमध्ये अब्जावधी माहितीच्या देवाण घेवाणीचे व्यवहार होत असतात. या कायद्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे, सेबीची नियमावली, माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा २००० यामध्ये असणाऱ्या विविध तरतुदींमध्ये एकवाक्यता नव्हती. मात्र DPDP कायदा हा सर्व क्षेत्रांसाठी एकसमान, तंत्रज्ञान निरपेक्ष नियमावली तयार करतो. हा कायदा डिजिटल स्वरूपात जमा केलेली माहिती किंवा वैयक्तिक माहिती जी नंतर डिजिटलाईज्ड करण्यात आली, अशा माहितीला लागू होतो.

## \* DPDP कायद्याची भौगोलिक व्याप्ती खालीलप्रमाणे -

१) भारतात प्रक्रिया केलेल्या वैयक्तिक माहितीस हा कायदा लागू राहील. २) सदर वैयक्तिक माहितीवर केवळ कायदेशीर कारणासाठीच प्रक्रिया करण्यात येईल. ३) माहिती धारकाने अशा माहितीवर काही विशिष्ट

कारणांसाठी प्रक्रिया करणेसाठी स्पष्ट संमती देणे आवश्यक राहील. ४) वैयक्तिक माहितीवर केली जाणारी प्रक्रिया ही वरील कायद्याशी सुसंगत असावी. ५) अन्य कारणांसाठी वैयक्तिक माहितीचा वापर करावयाचा असल्यास माहिती धारकाची पुनः संमती घेणे आवश्यक राहील.

या कायद्यात काही महत्त्वाच्या संज्ञांचा समावेश करण्यात आला, ज्यामध्ये...

१) माहिती धारक - अशी व्यक्ती जिच्याशी संबंधित वैयक्तिक माहिती आहे. उदा. बँकेचा ग्राहक

२) माहिती विश्वस्त - अशी व्यक्ती / संस्था जी माहिती धारकाच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर केव्हा व कशासाठी करायचा हे ठरविते. उदा. बँक, वित्तीय संस्था, क्रेडिट सोसायटी इ.

३) माहिती प्रोसेसर - माहिती विश्वस्तांच्या वतीने माहिती धारकाच्या माहितीवर प्रक्रिया करणारी संस्था उदा. व्हॅंडर / आयटी कंपन्या इ.

४) संवेदनशील वैयक्तिक माहिती - माहिती धारकाची अशी माहिती ज्यामध्ये त्याचा पासवर्ड, बायोमेट्रिक डेटा, अनुवांशिक माहिती, ओळख क्रमांक, त्याची आर्थिक माहिती, आरोग्याशी अथवा वैवाहिक जीवनाशी संबंधित माहिती, धार्मिक आणि राजकीय माहिती इ. चा समावेश आहे.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती धारकाची केवळ आवश्यक असेल तितकीच माहिती, माहिती विश्वस्त याने घ्यावी. धारकाची अतिरिक्त माहिती घेण्यात येऊ नये व प्रत्येक माहितीवर प्रक्रिया करताना त्यासाठी योग्य ते कारण असणे गरजेचे आहे. उदा. एखादी व्यक्ती एखाद्या औषधाच्या दुकानातून औषधे खरेदी करते व रक्कम अदा केल्याची पावती मिळण्यासाठी तिचा मोबाईल क्रमांक देते, अशा वेळी सदर दुकानदाराने केवळ ग्राहकाला पावती पाठविण्यासाठी त्याच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करावी.

\* माहिती साठविण्याचा कालावधी - माहिती धारकाची माहिती आवश्यकतेपेक्षा जास्त काळ ठेवू नये. अशी माहिती साठविण्याचा कालावधी योग्य कारणासह नमुद केलेला असावा. गरज संपल्यावर माहिती आपोआप नष्ट करण्याची यंत्रणा असावी.

\* माहितीबाबत पारदर्शकता आणि मंजूरी - माहिती विश्वस्तांनी माहिती धारकाला साध्या, सरळ, सोप्या भाषेत माहिती द्यावी. माहिती धारकाने दिलेली मंजूरी ही विनाअट आणि स्पष्ट असावी. उदा. एखादी व्यक्ती एखाद्या विमा कंपनीच्या ॲपद्वारे / वेबसाईटद्वारे विमा पॉलिसी घेते. समजा त्या कंपनीने त्या व्यक्तीस विमा पॉलिसी देण्यासाठी तिच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि माहिती संरक्षण मंडळाकडे तक्रार करण्याचा हक्क सोडण्याची संमती घेतली असेल, तर अशा वेळी तक्रार करण्याचा हक्क त्या व्यक्तीने सोडण्यासंबंधीचा भाग हा अवैध राहील.

\* माहितीची सुरक्षितता आणि जबाबदारी - माहिती विश्वस्थांनी माहिती धारकाच्या वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता जपण्याकरिता योग्य ती सुरक्षा यंत्रणा राबवावी. माहिती प्रोसेसर यांनी माहितीवर केलेल्या सर्व प्रक्रियेची नोंद ठेवावी. या कायद्याशी संबंधित सर्व संस्थांनी जबाबदारी आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील.

\* माहिती धारकाचे मुलभूत हक्क - या कायद्यांतर्गत माहिती धारकास त्याची वैयक्तिक माहिती का व कशासाठी वापरली जातेय, हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे व त्याने मागणी केल्यास जबाबदार संस्थांनी धारकास त्याच्या माहितीवर केल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेची माहिती देणे

पुढील पानावर...

आवश्यक आहे. संबंधित संस्थांनी अशी माहिती ३० दिवसांच्या आत स्पष्ट, सुरचित आणि सहज वापरता येईल अशा स्वरूपात धारकाला द्यावी. उदा. एखादी व्यक्ती एखाद्या बँकेत मोबाईल ॲपद्वारे किंवा नेट बँकिंगद्वारे खाते उघडून व्यवहार करते, त्यावेळी केवायसी प्रक्रियेसाठी व्हिडिओ आधारित ओळख देते व तिच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यास संमती देते, अशा वेळी बँकेने त्या व्यक्तीकडे वैयक्तिक माहिती मागण्यापूर्वी तिला माहितीचे स्वरूप आणि प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशाची माहिती द्यावी.

#### \* मुख्य अपवाद -

या कायद्याला खालील बाबी अपवाद आहेत.

१) माहिती धारकाने स्वतःच्या वैयक्तिक कारणासाठी प्रक्रिया केलेली माहिती. उदा. एखादी व्यक्ती तिची वैयक्तिक माहिती ब्लॉगद्वारे / सोशल मिडियाद्वारे सार्वजनिक करते, त्यावेळी या कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. २) कायद्यातील बंधनामुळे माहिती धारक किंवा अन्य व्यक्तीने सार्वजनिक केलेली माहिती. ३) काही आपत्कालीन परिस्थितीत अथवा सुरक्षेच्या किंवा योजनेच्या प्रचाराच्या कारणास्तव केंद्र अथवा राज्य सरकारने प्रक्रिया केलेली माहिती. उदा. एखादी गर्भवती महिला जर सरकारी योजनेतून लाभ घेणेसाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ॲप / वेबसाईटवर नोंदणी करते आणि त्याच उद्देशासाठी तिच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी संमती देते, अशा वेळी शासन तिच्या माहितीवर प्रक्रिया करून सदर महिला अन्य कोणत्या शासकीय लाभासाठी पात्र आहे का ते ठरवू शकते.

#### \* DPDP कायद्यातील मुख्य तत्त्वे -

१) दुरुस्तीचा हक्क - माहिती धारकास त्याची चुकीची भरलेली अथवा अपूर्ण असलेली माहिती दुरुस्त करता येते व त्याप्रमाणे माहिती विश्वस्तानी सदर माहिती विहित मुदतीत दुरुस्त करून देणे आवश्यक आहे.

२) माहिती काढून टाकण्याच्या हक्क - या कायद्यांतर्गत माहिती धारकाची जितकी विशिष्ट व कायदेशीर उद्देशासाठी माहिती आवश्यक असेल तितकीच माहिती घेण्यात यावी व अनावश्यक माहिती नियमितपणे तपासून काढून टाकावी. उदा. एखादी व्यक्ती एखाद्या संस्थेचे टेलिमेडिसिन ॲप डाऊनलोड करते, त्यावेळी सदर संस्था त्या व्यक्तीकडून वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी तिच्या मोबाईल क्रमांकाच्या वापरासाठी संमती मागते. सदर व्यक्तीने अशी संमती दिल्यावर त्या संस्थेने त्या व्यक्तीच्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर केवळ टेलिमेडिसिन सेवेसाठीच करावा.

माहिती धारकास माहिती विश्वस्ताकडे त्याची असलेली माहिती काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. उदा. माहिती ज्या हेतूसाठी घेण्यात आलेली आहे, त्याची पूर्तता झाली असेल किंवा माहितीची आवश्यकता राहिलेली नसेल किंवा धारकाला त्याच्या माहितीवर कोणतीही प्रक्रिया करून घ्यावयाची नसेल किंवा माहितीवर अनधिकृतपणे प्रक्रिया झालेली असेल, इ. कारणास्तव माहिती धारक त्याची माहिती हटवू शकतो अथवा काढून टाकण्याची मागणी करू शकतो.

#### ३) संमती मागे घेण्याचा हक्क -

माहिती धारक कोणत्याही क्षणी आपल्या माहितीवर प्रक्रिया करण्यास दिलेली संमती मागे घेऊ शकतो. तथापि संमती मागे घेण्यापूर्वी माहितीवर केलेली प्रक्रिया वैध राहिल. उदा. एखादी व्यक्ती एखाद्या संस्थेच्या इ-कॉमर्स / वेबसाईटची वापरकर्ता आहे. समजा तिने काही खरेदीसाठी ऑर्डर देताना तिच्या वैयक्तिक माहितीच्या प्रक्रियेस संमती दिली असेल व नंतर ती दिलेली संमती मागे घेतली तर ती संस्था तिला पुढील ऑर्डर देण्यापासून थांबवू शकते, पण आधी दिलेल्या ऑर्डरची पूर्तता करण्यासाठी

माहितीवर होणारी प्रक्रिया थांबवू शकत नाही.

#### ४) माहिती हस्तांतरणाचा हक्क -

लागू असल्यास माहिती धारक आपली वैयक्तिक माहिती एका संस्थेकडून दुसरीकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करू शकतो. उदा. एखादा ग्राहक एका दूरसंचार सेवा पुरवठेदारास त्याच्या वैयक्तिक माहितीच्या प्रक्रियेस संमती देतो. सदर सेवा पुरवठेदार दुसऱ्या डेटा प्रोसेसर सोबत करार करतो, जेणेकरून त्याच्या ग्राहकांना मोबाईल ॲपद्वारे सेवा देता येईल. जर आता त्या ग्राहकाने ॲप डाऊनलोड केले, तर तो ग्राहक सेवा पुरवठेदाराला त्याच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यास संमती देतो. मात्र ग्राहक जेव्हा ते ॲप वापरणे थांबवतो, त्यावेळी सेवापुरवठेदाराने त्या ग्राहकाच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करणे थांबवावे, मात्र उर्वरित बिलांसाठी तो आवश्यक तेवढी प्रक्रिया सुरू ठेवू शकतो.

५) मुलांसाठी विशेष संरक्षण - १८ वर्षाखालील मुलांशी संबंधित माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी त्यांच्या पालकांची संमती घेणे आवश्यक राहिल.

#### \* संमती व्यवस्थापक यांचे एकत्रीकरण - नवीन कायद्यातील

तरतुदीनुसार संमती व्यवस्थापक हे मध्यस्थ म्हणून काम करतील. हे व्यवस्थापक भारतातील नोंदणीकृत संस्था असून ते इंटरऑपरेबल प्लॅटफॉर्म प्रदान करतात. माहिती धारक एकाच प्लॅटफॉर्मवरून अनेक माहिती विश्वस्तांना माहिती प्रक्रिया करण्यासाठी संमती देऊ शकतात, त्याचे पुनरावलोकन करू शकतात अथवा दिलेली संमती मागे घेऊ शकतात.

माहिती विश्वस्तांनी मान्यताप्राप्त संमती व्यवस्थापक प्रणालींचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून एकसंघ संमती प्रणाली तयार होऊन पारदर्शकता वाढीस

लागेल.

#### \* माहिती विश्वस्त हा महत्त्वपूर्ण मानला जातात, जर तो...

१) मोठ्या प्रमाणावर माहिती धारकाच्या वैयक्तिक तथा संवेदनशील माहितीवर प्रक्रिया करतो. २) माहिती प्रक्रियेवर प्रणालीबद्ध देखरेख ठेवतो.

\* स्वतंत्र ऑडिट - महत्त्वाच्या माहिती विश्वस्तांनी उदा. बँकांनी स्वतःचे स्वतंत्र ऑडिट करणे आवश्यक आहे. माहिती संरक्षण अनुपालनाचे देखील दरवर्षी त्रयस्थ संस्थेकडून ऑडिट करून घ्यावे. सदर ऑडिटर हा पात्र आणि स्वतंत्र असला पाहिजे. अधिकृत प्राधिकरणाने विनंती केल्यास त्यांना लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा. सदर अहवालातील निष्कर्षावर आधारित सुधारणा करावी.

#### \* तक्रार निवारण यंत्रणा -

१) महत्त्वाच्या माहिती विश्वस्तांनी माहिती धारकांच्या तक्रार निवारणासाठी योग्य ती यंत्रणा उभारावी.

२) माहिती धारकांच्या तक्रार निवारणासाठी माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. ३) यासाठी तक्रार निवारणाचा कालावधी सुमारे ३०-४५ दिवसांचा राहिल. ४) माहिती धारकाला निकालाच्या विरोधात याचिका (अपील) करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. ५) सर्व तक्रारी तथा त्यांच्या न्याय निवाड्याचे दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक राहिल.

#### \* माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती व त्याची कार्ये -

या कायद्यांतर्गत माहिती विश्वस्तांनी (अथवा बँकेचे माहिती संरक्षण मंडळ) माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. त्याचा दर्जा बँकेच्या मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या खालोखाल राहिल. सदर अधिकाऱ्याने थेट संचालक मंडळ अथवा प्रशासकीय संस्थेला रिपोर्ट करणे जरूरीचे राहिल. माहिती धारकांच्या तक्रारीसाठी हा अधिकारी

पुढील पानावर...

मुख्य संपर्क अधिकारी म्हणून कामकाज पाहील. तो वरील कायद्याची अंमलबजावणी, नियमांचे पालन व्यवस्थितरीत्या होत आहे अथवा नाही, यावर देखरेख ठेवेल. तसेच संस्थेला माहिती सुरक्षिततेच्या जबाबदारीबाबत तो सल्ला देईल, अंतर्गत माहिती सुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी करेल, ग्राहकांमध्ये जागरूकता आणेल, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देईल, धोरणाचे पालन न झाल्यास त्यासंबंधी माहिती संरक्षण मंडळाला रिपोर्ट करेल, माहितीवर केल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेची नोंद ठेवेल, माहिती धारकांकडून आलेल्या तक्रारींचे निवारण करेल, तसेच भारतीय माहिती संरक्षण मंडळाबरोबर समन्वय राखेल. माहिती संरक्षण अधिकाऱ्यास आवश्यक असणारी पात्रता जरी तुर्तास दिलेली नसली तरी सदर अधिकाऱ्यास कायद्याचे, तांत्रिक बाबींचे तसेच सायबर सिक्युरिटीबाबतचे ज्ञान असणे गरजेचे राहील.

**\* माहितीचे उल्लंघन आणि अधिसूचनेसंदर्भात बंधने** - माहिती धारकाच्या वैयक्तिक माहितीचे उल्लंघन झाल्यास, माहिती विश्वस्तानी अशा उल्लंघनामुळे माहिती धारकाचे नुकसान होत असल्यास त्याची त्वरित माहिती सदर प्रभावित माहिती धारकांना द्यावी व सदर उल्लंघन हाताळण्यासाठी अथवा होणारी हानी कमी करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी सहाय्य करावे. तसेच अधिक वेळ न घेता भारताच्या माहिती संरक्षण मंडळाला कळवावे. उल्लंघनाबाबतचा सर्व तपशील उदा. उल्लंघनाचे स्वरूप, कालमर्यादा, त्याचा परिणाम इ.चे दस्तऐवजीकरण करावे.

#### \* अधिसूचनेतून सूट -

१) वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक झाली असल्यास २) तांत्रिक आणि संस्थात्मक स्तरावर केलेल्या उपाययोजनांमुळे जोखीम प्रभावीपणे कमी झाली असल्यास ३) तातडीने केलेल्या कारवाईमुळे नुकसान टाळले गेले असल्यास

#### \* DPDP कायद्याची अंमलबजावणी -

DPDP नियम २०२५ नुसार संस्थांना नियमांचे पालन टप्प्याटप्प्याने करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.

प्रथम टप्प्याचा कालावधी दि. १४ नोव्हेंबर २०२५ ते दि. १४ मे २०२६ असणार आहे. या कालावधीत कायद्यानुसार प्रशासन (गव्हर्नन्स) स्ट्रक्चर तसेच संबंधित धोरणे संस्थांना (बँकांना) तयार करावी लागणार आहेत. माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून योग्य ती संपर्क यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल. संमती व्यवस्थापक एकत्रिकरणासाठी नियोजन करावे लागेल. संमती व्यवस्थापकाची नेमणूक भारतीय माहिती संरक्षण मंडळाद्वारे केली जाईल.

दुसरा टप्पा हा दि. १५ मे २०२६ ते दि. १४ नोव्हेंबर २०२६ असा राहील. या कालावधीत संमती व्यवस्थापक इंटरफेसची अंमलबजावणी सुरू करणे आवश्यक राहील.

तसेच सुधारित संमती संकलन प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.

स्वयंचलित माहिती प्रणाली लागू करावी लागेल.

त्याचबरोबर किमान तिसरा टप्पा हा दि. १५ नोव्हेंबर २०२६ ते दि. १४ मे २०२७ असा राहील. या कालावधीत ऑपरेशनल बाबींची पूर्ण पूर्तता संस्थांना करावी लागेल. नवीन संमती मसुदा ग्राहकांकडून घ्यावा लागेल. लेखापरीक्षण तथा DPIA यंत्रणा निश्चित करावी लागेल.

**\* संमती व्यवस्थापक पर्यावरण** - नियामकीय अपेक्षा - या नियमांतर्गत संमती व्यवस्थापकांनी भारताच्या माहिती संरक्षण मंडळाकडे नोंदणी करावी. हे व्यवस्थापक देशात कार्यरत असतील. ते माहिती विश्वस्तांपासून स्वतंत्र असतील. ते परस्पर-सुसंगत आणि तंत्रज्ञान निरपेक्ष असतील. ते ठराविक संमती इंटरफेस प्रदान करतील.

**\* कार्यात्मक क्षमता** - संमती व्यवस्थापक प्लॅटफॉर्मद्वारे खालील सुविधा प्रदान केल्या जातील. **अ) संमती देणे** - माहिती धारक एकाच इंटरफेसद्वारे अनेक माहिती विश्वस्थांना संमती देऊ शकतात. **ब) संमती पुनरावलोकन** - यात सर्व सक्रिय संमत्या आणि प्रक्रियेच्या उद्देशाचे अवलोकन करता येते. **क) संमती व्यवस्थापन** - येथे संमती प्राधान्याचे आणि माहिती हाताळण्याचे पॅरामीटर्स बदलता येतात. **ड) संमती मागे घेणे** - येथे दिलेली संमती त्वरित मागे घेता येते. **इ) माहिती विषयक विनंती** - येथे फाईल्सशी संपर्क, त्यात दुरुस्त्या आणि काढून टाकण्याच्या विनंती हाताळल्या जातात.

#### \* माहिती विश्वस्थांची संमती व्यवस्थापक प्लॅटफॉर्मशी जुळवणी

- माहिती विश्वस्थांना मान्यताप्राप्त संमती व्यवस्थापक प्लॅटफॉर्मशी जुळवून घेणे, माहिती व्यवस्थापकांकडून जारी करण्यात आलेली संमती टोकन्स स्वीकारणे, संमती व्यवस्थापकांद्वारे माहितीवर प्रक्रिया करणेसाठी दिलेली संमती मागे घेण्याची विनंती मान्य करणे, इ. कार्ये करावी लागतात.

#### \* सुरक्षा आणि तांत्रिक मानके -

१) संवेदनशील वैयक्तिक माहितीचे प्रसारण दरम्यान एन्क्रिप्शन करणे. २) साठवलेल्या संवेदनशील वैयक्तिक माहितीचे एन्क्रिप्शन करणे. ३) केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच संबंधित एन्क्रिप्शन हाताळता येईल, अशी व्यवस्थापन प्रणाली बसवणे. ४) एन्क्रिप्शनचे नियमित लेखापरीक्षण आणि पडताळणी करणे.

#### \* माहिती प्रवेश नियंत्रण -

१) आवश्यकतेनुसार केवळ मर्यादित माहिती देणे. २) भूमिका किंवा गुणधर्म आधारित प्रवेश नियंत्रण ३) संवेदनशील माहितीच्या हाताळणीसाठी मल्टी फॅक्टर प्रमाणीकरण ४) नियमित प्रवेशाचे पुनरावलोकन करणे आणि अनावश्यक प्रवेश काढून टाकणे.

**\* ऑडिट ट्रेल्स** - १) संस्थांनी सर्व वैयक्तिक माहिती प्रवेशाचे संपूर्ण ऑडिट लॉग ठेवणे. २) प्रत्येक प्रवेशासाठी वापरकर्त्याची ओळख व वेळेची माहिती ठेवणे. ३) ऑडिट लॉग किमान एका वर्षासाठी जतन करणे. ४) बदल अथवा अवाजवी हस्तक्षेप न करता येणारी ऑडिट यंत्रणा वापरणे.

#### \* भारतीय माहिती संरक्षण मंडळाची स्थापना -

भारतीय माहिती संरक्षण मंडळाची स्थापना केंद्र सरकारद्वारा केली जाईल. त्याची कार्ये खालीलप्रमाणे - १) माहिती धारकाच्या अधिकारांचे अथवा वैयक्तिक माहितीचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी स्वीकारून चौकशी करणे. २) कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास माहिती विश्वस्थांना सूचना व निर्देश जारी करणे. ३) त्यांना आर्थिक दंड व अन्य शिक्षा सुनावणे. ४) दंडाविरुद्ध आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेणे. ५) संमती व्यवस्थापकांची नोंद ठेवणे. ६) DPDP कायद्यातील तरतुदींच्या पालनासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करणे. ७) भविष्यात नियमांचे उल्लंघन होऊ नये याकरीता योग्य त्या उपाययोजना आखणे. ८) साक्षीदारांना समन्स देणे आणि त्यांची चौकशी करणे. ९) संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडणे, सदर कागदपत्रांची तसेच संगणकीय माहितीची तपासणी करणे. १०) तातडीच्या सुधारात्मक किंवा प्रतिबंधात्मक उपायांचे निर्देश देणे.

#### \* दंड आणि अंमलबजावणी -

या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास आकारण्यात येणारा दंड खालीलप्रमाणे राहील - १) माहिती विश्वस्ताने माहिती धारकाच्या वैयक्तिक माहितीचे होणारे उल्लंघन टाळण्यासाठी योग्य त्या सुरक्षा उपाययोजना न केल्यास कमाल रु. २५० कोटीपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. २) वैयक्तिक माहिती उल्लंघनाची माहिती, संरक्षण मंडळ अथवा संबंधित माहिती धारकास न दिल्यास कमाल रु. २०० कोटीपर्यंत दंड होऊ शकतो. ३)

पुढील पानावर...

# डॉ. किरण ठाकूर दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकारिता पुरस्काराने सन्मानित

पुणे - लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. किरण ठाकूर यांना खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या हस्ते दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकारिता पुरस्काराने एका समारंभात गौरविण्यात आले आहे.

ज्येष्ठ साहित्यिक प्र. दिलीप फडके अध्यक्षस्थानी होते. सत्काराला उत्तर देताना डॉ. ठाकूर यांनी सांगितले की, पत्रकारिता हे केवळ बातमीचे माध्यम नसून समाज जागृतीचे प्रभावी माध्यम आहे. यापुढील काळात सत्यनिष्ठ आणि अभ्यासपूर्ण लेखनाची परंपरा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.



## सहकार पुरस्काराच्या रकमेत मोठी वाढ

पुणे - राज्यातील सहकार क्षेत्राला अधिक गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाने सहकार पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सहकार महर्षी, सहकार भूषण आणि सहकार निष्ठा या तीन पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करण्यात येणारा आहे.

सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी सन १२-१३ पासून सहकार पुरस्कार योजना सुरू करण्यात आली आहे. पुरस्कार

सुरू झाल्यापासून प्रथमच रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सहकार महर्षी पुरस्काराच्या रकमेत एक लाखावरून तीन लाख तर सहकार भूषण पुरस्कार रकमेत ५१ हजारावरून दीड लाख तर सहकार निष्ठा पुरस्कार रकमेत २५ हजारांवरून ५१ हजार अशी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सहकार चळवळीला नवे बळ मिळणार आहे.

## पुणे पीपल्स बँकेचा कार्याचा पाच पुरस्कारांनी गौरव

पुणे - पुणे पीपल्स को-ऑप. बँकेचा बेस्ट मल्टिस्टेट अर्बन को-ऑप. बँक या पुरस्कारासह अन्य विविध पारितोषिके प्रदान करून गौरव करण्यात आला. तिसरी राष्ट्रीय नागरी सहकारी बँकिंग शिखर परिषद नुकतीच झाली. बँक अध्यक्ष श्रीधर गायकवाड तसेच अन्य पदाधिकारी यांना यावेळी गौरविण्यात आले.

बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष मोहिते संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बँकेने आर्थिक वर्षात ३ हजार ६३ कोटींचा एकूण व्यवसाय केला आहे. एकूण ठेवी १ हजार ८४१ कोटींच्या असून १ हजार २२२ कोटी इतके कर्जवाटप करण्यात आले आहे.

मागील पानावरून...

## डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा २०२३ - सहकारी बँकांपुढे आव्हान

महत्त्वपूर्ण माहिती विश्वस्ताच्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्या न पाळल्यास कमाल रु.१५० कोटीपर्यंत दंड होऊ शकतो. ४) या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचे अथवा नियमांचे पालन न केल्यास कमाल रु.५० कोटीपर्यंत दंड होऊ शकतो.

दंडाची रक्कम निश्चित करताना संबंधित प्राधिकरण माहिती उल्लंघनाचे स्वरूप व गंभीरता, माहितीचा प्रकार (विशेषतः आर्थिक माहिती), प्रभावित ग्राहकांची संख्या, निष्काळजीपणा किंवा जाणीवपूर्वक केलेले कृत्य, बँकेचा पूर्वीचा अनुपालन इतिहास आणि नुकसान कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना यांचा सखोल विचार करते.

**\* अंमलजावणी प्रक्रिया -** १) भारतीय माहिती संरक्षण मंडळाकडे तक्रार करणे. २) माहिती विश्वस्तांची प्राथमिक चौकशी करणे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे. ३) उल्लंघन झाल्यास निर्णय घेणे. ४) दंडाची सुनावणी करणे. ५) अपील यंत्रणा कार्यान्वित करणे.

**\* अनुपालन निर्देश -** १) भारतीय माहिती सुरक्षा मंडळ सुधारात्मक कारवाईसाठी बंधनकारक निर्देश जारी करेल. २) मर्यादित वेळेत अनुपालन पूर्तता करेल. ३) माहिती धारकाला संरक्षण देणेसाठी अंतरीम उपाययोजना आखेल. ४) अनुपालनासाठी नियमित देखरेख ठेवेल.

**\* नागरी उपाय -** माहिती धारकांना असलेले अधिकार - १) अनाधिकृत माहिती प्रक्रियेकरिता नुकसान भरपाई मागणे. २) वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनाकरीता स्थगिती आदेश मागणे. ३) गंभीर उल्लंघनासाठी फौजदारी तक्रार दाखल करणे. ४) झालेल्या नुकसानासाठी भरपाई मागणे.

**\* बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र -**

१) या कायद्याच्या तरतुदी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांना पूरक आहेत. २) ग्राहकाच्या खात्यातील माहितीसाठी आणि व्यवहाराच्या नोंदीसाठी विशेष संरक्षण आवश्यक आहे. ३) पेमेंट कार्ड डेटासाठी PCI-DSSचे अनुपालन आवश्यक आहे. ४) ठराविक कालावधीत

रिझर्व्ह बँकेस माहिती उल्लंघनाची सूचना देणे आवश्यक आहे. ५) माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याने मुख्य जोखीम अधिकाऱ्यास किंवा मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी यांना अहवाल द्यावा.

**\* बँकांनी करावयाचे कामकाज -**

१) सर्व वैयक्तिक माहिती प्रक्रिया क्रियाकलापांची माहिती करून घेणे. २) माहिती स्रोत, उद्देश, माहिती जतन करण्याचा कालावधी निश्चित करणे. ३) DPDP कायद्यांतर्गत गोपनीय धोरण तयार करणे व ते वेळोवेळी अद्ययावत करणे. ४) तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे. ५) माहिती हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सातत्याने प्रशिक्षण देणे. ६) सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करणे. ७) माहिती सुरक्षा अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वेगाने प्रसार होत असताना नव्याने अंमलात आलेला हा कायदा ग्राहकांना सुरक्षा प्रदान करतो, त्यांची विश्वासाहता वाढीस लावतो. बँकेच्या ग्राहकाची केवायसी माहिती, आर्थिक व्यवहारांची नोंद तसेच आधार आणि पॅनसारखी अत्यंत संवेदनशील माहिती हाताळत असल्यामुळे त्या उच्च जोखीम गटात मोडतात. परिणामी त्यांच्या बाबतीत दंडाची रक्कम तुलनेने अधिक असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे माहिती संरक्षणाच्या दृष्टीने बँकांनी अत्यंत दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे. निष्काळजीपणामुळे बँकांकडून ग्राहकांच्या माहितीचे उल्लंघन झाल्यास बँकेला केवळ मोठा आर्थिक दंडच बसत नाही, तर तिच्या प्रतिमेला, नावलौकिकाला धक्का लागू शकतो. सबब या कायद्यातील तरतुदींचे पालन केवळ पूर्तता करण्यासाठी न करता बँकांनी त्याकडे संधी म्हणून पाहिले पाहिजे व या आव्हानास स्विकारण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.

- सौ. सायली संजय भोईर, सरव्यवस्थापिका, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक लि.

\*\*\*\*\*

# सहकार क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सीए इन्स्टिट्यूटचा पुढाकार 'आयसीएआय'च्या शिष्टमंडळाची सहकार आयुक्त तावरे यांच्याशी चर्चा

पुणे - इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) वेस्टर्न इंडिया रीजनल कौन्सिलच्या (डब्ल्यूआयआरसी) शिष्टमंडळाने राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांची भेट घेऊन सहकार क्षेत्रातील विविध महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.

'डब्ल्यूआयआरसी'चे अध्यक्ष सीए सौरभ अजमेरा यांच्या नेतृत्वाखाली व प्रभागीय सहकार समितीचे अध्यक्ष सीए अभिषेक धामणे यांच्या पुढाकाराने शिष्टमंडळात आयसीएआय पुणे शाखेचे अध्यक्ष सीए प्रणव आपटे यांच्यासह विभागीय समिती सदस्य सीए राजेश अग्रवाल पुणे शाखेचे उपाध्यक्ष सीए निलेश येवलेकर, खजिनदार सीए नंदकुमार कदम, सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ सीए वसंत गुंड व सतीश मुंदडा उपस्थित होते.

बैठकीत २०२६ ते २०२८ या कालावधीसाठी ऑडिटर पॅनल नोंदणीची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच, महाराष्ट्रासाठी प्रस्तावित नव्या



सहकार कायद्याच्या निर्मितीत चार्टर्ड अकाउंटंट्सना सहभागी करून घेण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली. आयकर व जीएसटीप्रमाणे धोरण निर्मितीत सीए इन्स्टिट्यूटचे योगदान महत्वाचे असल्याचे प्रतिनिधींनी नमूद केले.

सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याची मागणीही करण्यात

आली. आर्थिक वर्ष २०१३-१४ पासून या मानधनात कोणताही बदल झालेला नसताना, कामाचा व्याप, नियमांचे पालन आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या वाढल्या असल्याकडे प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. या संवादातून सहकार प्रशासन आणि सनदी लेखापरीक्षक यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

## पुणे पीपल्सचा ३०६३ कोटी व्यवसायाचा टप्पा पार

पुणे - येथील पुणे पीपल्स सहकारी बँकेने अमृत महोत्सवी वर्षात भक्कम प्रगतीचा नवा टप्पा गाठला आहे. आर्थिक वर्षात ३०६३ कोटी व्यवसायाचा टप्पा पार केला आहे तर १३५७ कोटींची व्यवसायात वाढ केली आहे, अशी माहिती बँक अध्यक्षा श्रीधर गायकवाड यांनी सांगितली.

बँकेच्या एकूण ठेवी १८४१ कोटी झाल्या असून कर्ज वाटप १२२२ कोटी इतके झाले आहे. सीडी रेपो ६६.४१ कोटी इतका असून एनपीए शून्य टक्के राखण्यात यश मिळविले आहे बँकेच्या वतीने विविध योजना ग्राहकांसाठी देण्यात आल्या आहेत. आगामी आर्थिक वर्षात बँकेच्या नवीन ३ शाखा तर राज्याबाहेर शाखा सुरू करण्याचा मानस आहे.

## महिलांनी सायबर क्राईम विषय काळजीपूर्वक हाताळावा

कोल्हापूर - रोजच्या जीवनात महिलांनी सायबर क्राईम हा विषय काळजीपूर्वक हाताळला पाहिजे. याकडे दुर्लक्ष न करता त्याबाबत सविस्तर माहिती घ्यावी असे आवाहन माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ हेमंत देशमुख यांनी केले आहे.

जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन आणि सहकार भारती सहकार प्रशिक्षण सहकारी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील सहकारी बँकेमधील महिला संचालिका व पदाधिकारी

यांच्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

असोसिएशन संचालिका विजया जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश शिंदे, तसेच अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी देशमुख यांनी विषयाची सविस्तर मांडणी केली. तसेच यावर रुपेश कुंभार यांनी विवेचन केले. आजरा अर्बन बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत गंभीर यांनी समारोप सत्रात मनोगत व्यक्त केले. सांगली अर्बन बँक संचालिका अश्विनी आठवले यांनी सूत्रसंचालन केले.

## मोहनावती जि.प.शिक्षक पतसंस्था अध्यक्षपदी सचिन रामदिनवार सचिवपदी डॉ. शिवाजी कराळे

नांदेड - मोहनावती जिल्हा परिषद शिक्षक व कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षा पदी सचिन रामदिनवार तर सचिवपदी डॉ. शिवाजी कराळे यांची नुकतीच बिनविरोध निवड करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी अनिल मारमवार तर कोषाध्यक्षपदी संजय सातमवार यांचीही एकमताने निवड करण्यात आली.

पतसंस्थेच्या नूतन कार्यकारिणीस राज्य पुरस्कार प्राप्त मुख्याध्यापक गोविंद चव्हाण, संकल्प प्रतिष्ठानचे संस्थापक बालाजी बामणे, शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष व्यंकट गंदपवाड, नांदेड सहकारी पतपेढीचे संचालक प्रल्हाद राठोड, मधुकर गायकवाड, संजय कोटगिरी, स्वीय सहाय्यक सुधीर चव्हाण, शिवाजी गेडेवाड, पांडुरंग दिनकर, अशोक पाटील, विठ्ठल मुखेडकर, शंकर कुसुमकर, बाळू नाईक इत्यादींनी शुभेच्छा दिल्या.

## सहकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणावर भर

पुणे - प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि अचूकता यावी त्याचप्रमाणे त्याचे संगणकीकरण व ऑनलाईन लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने घेतला आहे. संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात सहकार विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे पतसंस्था ई-ऑडिटमध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सर्व संस्थांना ईआरपीवर आधारित एका सामायिक संगणक प्रणालीवर आणणे आणि राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँक यांच्या माध्यमातून नाबार्डशी जोडण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्याच्या सहकार विभागाने १२ हजार विविध कार्यकारी सोसायटी यांची निवड केली आहे. सन २४ आणि २५ या आर्थिक वर्षासाठी या संस्था ई-ऑडिटसाठी पात्र होत्या. आजवर एकूण ११ हजार ९८१ विविध कार्यकारी सोसायटीचे लेखा परीक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.

# सहकार क्षेत्राला मार्गदर्शक ठरणारा कोर्ट निकाल

दिनांक १७/१०/२०२५ रोजी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाचे न्यायाधीश मा. अमितजी बोरकर यांनी संजीव भास्कर पाठक व अन्य विरुद्ध रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., पुणे, महाराष्ट्र राज्य व अन्य यांच्या दाव्यात याचिकाकर्ते यांच्या रिट याचिकांचा अंतिम निकाल जाहीर केला व रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., पुणे यांचा सहकार कायदा कलम ८८ चा संबंधित संपूर्ण चौकशी अहवाल सदोष आढळल्याने रद्दबातल केला. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला रुपी बँकेने आव्हान देण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्पेशल लिव्ह पिटीशन (SLP) सादर केले होते. ते पुढील सुनावणीसाठी दाखल करून घेण्याबाबत झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत दिनांक २० एप्रिल २०२६ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही SLP स्वीकारण्यास नकार देऊन बँकेला मा. मुंबई उच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन सादर करण्याची मुभा दिली. न्यायालयाच्या या दोन्ही महत्त्वपूर्ण पातळ्यांवर नाकारली गेलेली ही केस मूळात समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वर उल्लेख केलेल्या निकालाचा योग्य प्रकारे अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न केल्यास असे लक्षात येते की, भविष्यकाळात हा निकाल सहकार क्षेत्रात कार्यरत विविध प्रकारच्या संस्था व उच्च पदाधिकारी, तसेच उच्च शासकीय अधिकारी यांना मार्गदर्शक ठरावा.

सध्या रुपी बँकेचा परवाना आर.बी.आय.ने रद्द केला असून, ही बँक सध्या 'एक सहकारी सोसायटी' या स्वरूपात अस्तित्वात आहे व तिची अवसायनाची प्रक्रिया सुरु आहे.

महाराष्ट्रात कार्यरत विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांचे एक प्रमुख नियामक (regulator) महाराष्ट्र शासन आहे व हे नियमन महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० (संक्षेपात - सहकारी कायदा) च्या अंतर्गत केले जाते.

सहकारी संस्थांचे काम करताना त्यात काम करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीकडून काही अनियमितता किंवा गंभीर चूक होणे शक्य असते व तसे होताना काही वेळा दिसते. परिणामस्वरूप त्या संस्थेला काही आर्थिक नुकसानदेखील सोसावे लागते हा आपला सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशा वेळी या नियामकाला त्याचे कर्तव्य म्हणून त्या संस्थेतील संबंधित संशयित व्यक्तीची चौकशी करून ते दोषी ठरल्यास त्यांना शिक्षा देणे कायद्याने आवश्यक ठरते.

**\* सहकारी कायदा, कलम २(२०) -** या निकालात सहकारी कायदा, कलम २(२०)चा कायदेविषयक उहापोह करून या कलमाच्या आधारे सहकारी संस्थांत कार्यरत जबाबदार व्यक्तीचे निर्धारण करून त्यांच्यावर आवश्यक चौकशीनंतर योग्य ती कारवाई करावी हे निर्देशित केले आहे.

या कलमात 'ऑफिसर' या संज्ञेची व्याख्या केली आहे. सहकारी संस्थेच्या मंजूर पोटनियमानुसार निवडणूक किंवा नियुक्तीद्वारे पदासीन झालेली कोणीही व्यक्ती, ज्याच्यावर एक जबाबदार पदाधिकारी म्हणून संस्थेचे नियंत्रण, संस्थेच्या व्यवसायात मार्गदर्शन आणि त्यासंबंधी वित्तीय आणि व्यवस्थापनविषयक निर्णय घेणे व मंजुरी देणे ही जबाबदारी असते. अशा सर्व व्यक्ती 'ऑफिसर' या संज्ञेस सामान्यपणे व्याख्येच्या दृष्टीने पात्र ठरतात. यामध्ये संस्थेचे सर्व संचालक आणि (कोणतेही पदनाम असलेला) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो संचालक मंडळाचा पदसिद्ध सदस्य असतो, यांचा या व्याख्येच्या दृष्टीने प्रामुख्याने समावेश होतो असा खुलासा दिला आहे.

संस्था व्यवस्थापनाने अन्य अधिकारी यांची निवड करून प्रशासन सुचारू स्वरूपात चालावे म्हणून संस्थेत नियुक्ती केलेली असते. ते व्यवस्थापन मंडळाच्या निर्देशानुसार त्यांचे नेमून दिलेले काम करतात. त्यांना संस्थेला मार्गदर्शन करण्याचे, नियंत्रण करण्याचे व वित्तीय आणि व्यवस्थापनविषयक मंजुरी देण्याचे कोणतेही अधिकार सामान्यपणे नसतात. या व्यक्ती या कलमांतर्गत 'ऑफिसर' या संज्ञेस वरील व्याख्येच्या दृष्टीने सहसा पात्र होत नाहीत व त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सहकार

कायदांतर्गत सामान्यपणे चौकशी व कारवाई करता येणार नाही असे स्पष्टीकरण या निकालपत्रात दिले आहे. मात्र अशा अधिकाऱ्यांकडून अनवधानाने काही नियमबाह्य कृती घडली असेल व त्यामुळे संस्थेस काही आर्थिक नुकसान झाले नसेल, तर त्यांची अंतर्गत विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर अनुशासनिक कारवाई केली जाऊ शकेल. हे या निकालात दर्शविले आहे. कलम ८८ हे जाणीवपूर्वक व विश्वासघाताने केलेल्या कृती (culpable conduct) मुळे संस्थेला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आहे. ते प्रोसिजरमध्ये अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे शिक्षा करण्यासाठी नाही हे या निकालात स्पष्ट केले आहे.

तथापि या निकालपत्रात पुढे हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या अधिकाऱ्यांना बँक व्यवस्थापनाने संस्थेच्या मंजूर पोटनियमास अनुसरून मंजुरीचे किंवा / आणि मंजुरीची शिफारस करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत आणि जर त्यांच्याकडून संस्थेस आर्थिक नुकसान होण्यास कारणीभूत

असलेली एखादी गंभीर चूक किंवा कृती झाली असेल आणि जर ती ठोस कागदोपत्री पुराव्यानिशी सिद्ध होत असेल, तर त्यांचा कलम २(२०) मधील विस्तारित व्याख्येनुसार 'ऑफिसर' या संज्ञेअंतर्गत समावेश करता येईल व त्यांची कलम ८८ अंतर्गत चौकशी करता येईल किंवा त्यांची अंतर्गत विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर अनुशासनिक व दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकेल.

**\* संस्थेतील दोषी व्यक्ती कोण? -** या महत्त्वाच्या निकालाने आणखी एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे, ती अशी की, सहकार कायदा, कलम ८८ अंतर्गत जबाबदारी निश्चित करताना ती सामूहिक किंवा केवळ गृहितकांवर आधारित अशा मोघम स्वरूपाची ठरविता येणार नाही, तर कलम ८८ अंतर्गत 'ऑफिसर' या संज्ञेस पात्र असणाऱ्या किंवा त्याच्या विस्तारित संज्ञेस पात्र होऊ शकणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची एखादी वैयक्तिक कृती, जी त्या व्यक्तीने जाणीवपूर्वक

व हे माहित असताना की, या कृतीमुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान होणार असेल तर त्या कृतीला कायदानुसार ळीषरीरपलश म्हणून ठरविता येईल व त्या व्यक्तीस वैयक्तिक जबाबदार धरता येईल, अर्थात जर त्या कृतीसंबंधी ठोस कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध असतील तर अशी जबाबदारी निश्चित करताना अपहार, भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, विश्वासघात, फसवणूक यासारखे संस्थेचे आर्थिक नुकसान करू शकणारे अन्य महत्त्वाचे घटक देखील विचारात घेता येतील. परंतु त्यासाठी विशिष्ट भक्कम कागदोपत्री पुरावे असणे आवश्यक राहिल हे या निकालाने पुरेसे स्पष्ट केले आहे.

या निकालाने सहकारी बँकांच्या अधिकारी वर्गाबद्दल व त्यांच्या संस्थेतील भूमिकेबद्दल पुरेशी स्पष्टता केली आहे. ती अशी की, अधिकारी व्यक्तीने संस्थेच्या मंजूर पोटनियमास अनुसरून त्यांना दिलेल्या कर्तव्य सूची (duty list) नुसार व त्यांना प्राप्त लेखी निर्देशानुसार एखाद्या कर्ज किंवा अन्य आर्थिक प्रकरणी त्यावेळी त्याच्यासमोर उपलब्ध असलेली कागदपत्रे व आकडेवारी आणि त्याच्या बँकिंग ज्ञान व अनुभवानुसार प्रामाणिकपणे छाननी करून मंजुरीची केवळ शिफारस केली असेल आणि त्यानंतर भविष्यकाळात काही अन्य कारणाने ते कर्जखाते एन.पी.ए. झाल्यामुळे किंवा काही अन्य आर्थिक प्रकरणी दुसऱ्या एखाद्या कारणाने संस्थेस आर्थिक नुकसान झाले, तर त्या व्यक्तीस वैयक्तिक जबाबदार धरता येणार नाही. परंतु misfeasance, अपहार, भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, विश्वासघात, फसवणूक असे काही महत्त्वाचे घटक त्यांच्याविरुद्ध लेखी कागदोपत्री ठोस पुराव्यानिशी सिद्ध होत असतील, तर मात्र सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अंतर्गत कारवाई करता येईल ही गोष्ट या निकालात निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे सध्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतेही कर्ज किंवा अन्य आर्थिक प्रकरण योग्य असले, तरी शिफारस करताना जी भीती बसली आहे, ती या निकालाने दूर होणे अपेक्षित आहे. अर्थात जर त्यांनी आपले काम हे नियमानुसार, पारदर्शी पद्धतीने व प्रामाणिकपणे केले



भालचंद्र कुलकर्णी  
१८२२८ ८२५०९

असेल तर!

**\* सहकारी संस्थेसंबंधी चौकशी व कारवाईची विधिवत कार्य-पद्धती (procedure) -** सहकार विभागाच्या सक्षम निबंधकाला एखाद्या सहकारी संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीची खातरजमा करून त्याचे मूल्यांकन करण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो. त्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम ८१ अंतर्गत केलेले लेखा परीक्षण, कलम ८३ अंतर्गत केलेल्या चौकशीचा अहवाल किंवा सहकारी बँकांचे दुसरे नियामक असलेल्या आरबीआयने कलम ८४ अंतर्गत केलेल्या निरीक्षणाचा अहवाल, किंवा कलम १०५ अंतर्गत अवसायक यांचा अहवाल, ज्यामध्ये गंभीर त्रुटी, अनियमितता आणि संस्थेला आर्थिक नुकसान झाले असल्याच्या बाबी संबंधित संशयित व्यक्तींच्या नामोल्लेखासह अधोरेखित केल्या असतील, तर सक्षम निबंधक अशा संबंधित संशयितांची आवश्यक चौकशी करून योग्य ती कारवाई करू शकतील. त्यांनी हे काम सहकार कायद्यातील संबंधित कलमांना अनुसरून करणे अपेक्षित आहे. ही सर्व कलमे अत्यंत स्वयं-स्पष्ट आहेत. संबंधित संशयित व्यक्तींना आपले म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी देणे हेदेखील कायद्याने प्राधिकृत अधिकार्यावर बंधनकारक आहे. या प्रकारची चौकशी व कारवाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ च्या नियम ७२ मध्ये निर्देशित मार्गदर्शी सूचनांना अनुसरून टप्प्याटप्प्याने करणे आवश्यक आहे. या कारवाईत कलम ८८ अंतर्गत आरोप निश्चित करून व ते सिद्ध करून वसुली करणे याबरोबरच आवश्यक असल्यास एकाच वेळी फौजदारी स्वरूपाची कारवाई देखील केली जाऊ शकेल. नियम ७२ मध्ये निर्देशित मार्गदर्शी सूचनांना अनुसरून न केलेली कारवाई ही नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे अशी कारवाई बेकायदेशीर ठरू शकेल. या चौकशी व कारवाईसाठी आधारभूत लेखा परीक्षण किंवा निरीक्षण यांच्या प्रारंभ दिनांकापासून पूर्वीची अधिकतम पाच वर्षांतील खाती व कृती या कारवाईसाठी विचारात घेता येतील. त्यापूर्वीची किंवा नंतरची खाती व कृती नाही हेसुद्धा कायद्याने स्पष्ट केले आहे.

**\* अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात रूपी बँकेबाबत नेमके काय घडले ?**

बँकेतील अधिकाऱ्यांना कायद्याने व्याख्येच्या दृष्टीने आपोआप लागू नसताना ते 'ऑफिसर' या संज्ञेस पात्र आहेत असे मोघमपणे गृहित धरून त्यांच्यावर कलम ८८ अंतर्गत सरळ कारवाई करण्यात आली, जी त्यांच्यावर निश्चितच अन्यायकारक होती.

प्रारंभी नियम ७२ अंतर्गत अधिकारी यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. कलम ८३ अंतर्गत प्राप्त चौकशी अहवाल किंवा आरबीआयने कलम ८४ अंतर्गत केलेल्या निरीक्षणाचा अहवाल यामध्ये एकाही अधिकाऱ्याचा कोणताही तशा प्रकारचा नामोल्लेख नसताना कालांतराने त्यांना नियम ७२ अंतर्गत प्रथमच नोटीस देऊन सरळ कलम ८८ अंतर्गत चौकशी का करू नये म्हणून कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. जी कायद्याला नक्कीच अभिप्रेत नव्हती.

त्यानंतर अनेक वर्षे कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू होती. त्यावेळी अधिकारी यांनी misfeasance, अपहार, भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, विश्वासघात, फसवणूक केल्याचा प्राधिकृत अधिकारी यांनी कोणताही ठोस कागदोपत्री पुरावा देऊन ही बाब चौकशीत त्यांच्याविरुद्ध सिद्ध केलेली नाही आणि तरीदेखील त्यांच्यावर अंतिम आरोप निश्चित करून ते संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असल्याचे ठरवून त्यांना आरोपपत्र देण्यात आले. त्याचे दिलेले कारण असे की, ज्या एन.पी.ए. झालेल्या कर्जप्रकरणी संस्थेस आर्थिक नुकसान झाले, त्या कर्ज प्रकरणावर त्यांनी मंजुरीची शिफारस केली होती, जी त्यांच्या नियमित कामकाजाचा एक अविभाज्य भाग होता. खरे तर त्यांनी कोणतीही कर्जमंजुरी दिलेली नव्हती. कारण त्यांना तो अधिकारच नव्हता. त्यानंतर संस्थेच्या नुकसान भरपाईसाठी पुढील वैयक्तिक जमी कारवाईदेखील करण्यात आली. परंतु या वसुली कारवाईला मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक १५/०९/२०२२ रोजी या सर्व दाखल सर्व रिट याचिकांच्या अंतिम सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली.

अंतिमतः या संदर्भात अधिकारी यांनी ज्या विविध रिट याचिका मा. मुंबई

उच्च न्यायालयाला सादर केल्या होत्या, त्या सर्व एकत्रितपणे निकाली काढून मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले आहे. तथापि एखाद्या अधिकाऱ्याने संस्थेच्या मंजूर पोटनियमातील तरतुदीच्या विरुद्ध काही अनियमितता / गंभीर चूक केल्याचे व त्यामुळे संस्थेस आर्थिक नुकसान झाल्याचे आढळल्यास शासनाने प्राधान्याने येत्या सहा महिन्यांत, आवश्यक असल्यास, केवळ कलम ७२ मधील तरतुदीस अनुसरूनच पुन्हा नव्याने नोटीस देऊन आणि चौकशी करून त्यांच्यावर misfeasance, अपहार, भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, विश्वासघात, फसवणूक केल्याचा कागदोपत्री ठोस पुरावा देऊन त्यांच्यावर आरोप सिद्ध होत असल्यास सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अंतर्गत कायदेविषयक कारवाई करावी अशी सूचना केली आहे.

या केससंबंधी संबंधितांकडून, तसेच अॅड. श्रीपाद पंचपोर, अॅड. श्रीवल्लभ पंचपोर आणि अॅड. सौ. राधिका उर्सेकर, ज्यांनी कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यापासून ते मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिकाकर्त्यांची बाजू भक्कमपणे व प्रभावीपणे मांडली, अशा जाणकार तज्ञ व्यक्तींकडून अधिक माहिती घेता असे लक्षात आले की, या केसमध्ये निष्कारण अडकविलेले रूपी बँकेचे अधिकारी यांनी त्यांना नेमून दिलेले काम नियमानुसार अतिशय प्रामाणिकपणे व चोखपणे केले होते. प्राधिकृत अधिकारी यांना इतकी प्रदीर्घ चौकशी करूनदेखील एकाही अधिकाऱ्याने केलेल्या कामात misfeasance, अपहार, भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, विश्वासघात, फसवणूक केल्याचा एकही ठोस कागदोपत्री पुरावा सिद्ध करता आलेला नाही. कारण यापैकी कोणाही अधिकाऱ्याने त्या प्रकारची एकही चुकीची कृती केलेलीच नव्हती, त्यामुळे तसा काही पुरावा अस्तित्वात असायचे देखील काही कारण नव्हते. त्यांनी फक्त त्यांना वरिष्ठांनी नेमून दिलेल्या कर्ज प्रकरणावर केवळ शिफारस करण्याचे काम केले होते. तरीसुद्धा सिद्ध होत नसताना त्यांच्यावर अत्यंत मोघम स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले, जे त्यांच्यावर अन्यायकारक तर होतेच, परंतु कायदेशीरपणे नव्हते. त्यामुळेच मा. कोर्टाने प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल सदोष असल्याचे आढळल्याने हा अहवाल या निकालाद्वारे रद्द केला आहे ही खरी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे यापुढे तरी शासनाने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कोणाही बँक अधिकाऱ्यावर निष्कारण अन्याय होऊन त्यांचे मनोबल खच्ची होणार नाही, याची काळजी घ्यावी ही अपेक्षा आहे.

यापुढील काळात जर पुन्हा कधी एखाद्या सहकारी संस्थेच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध अशा प्रकारे कारवाई करण्यात आली, तर प्रत्येक न्यायालयीन स्तरावर प्रदीर्घ काळ या केसचा एक केस लॉ म्हणून संदर्भ दिला जाईल एवढा हा महत्त्वाचा मार्गदर्शी कोर्ट निकाल आहे.

अशा प्रकारे या अधिकाऱ्यांचा गेली सतरा वर्षे चाललेला कायदेविषयक संघर्ष व त्यामुळे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना झालेला मनःस्ताप संपला. या निमित्ताने सहकार क्षेत्राला मार्गदर्शक ठरेल असा एक मार्गदर्शी कोर्ट निकाल सामान्य जनतेसमोर आला आहे. या निकालामुळे सामान्य जनतेला या केसच्या संदर्भातील वर उल्लेख केलेली खरी वस्तुस्थिती समजून घेता येईल व या अधिकाऱ्यांविषयी जनतेचे काही गैरसमज झाले असतील, तर ते त्यांना दूर करता येतील. हा सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पूर्वी काम केलेल्या व सध्या कार्यरत सर्व अधिकाऱ्यांना मिळालेला मोठा दिलासा आहे. त्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढेल आणि ते अधिक जोमाने आपल्या कामाला लागतील व भविष्य काळात त्यांच्या संस्थांचा सर्वांगीण विकास करतील आणि आपल्या संस्थेच्या सर्व ठेवीदारांच्या हिताचे सदैव रक्षण करतील असा विश्वास वाटतो. या निकालाचे सहकारी बँकिंग वर्तुळात चांगले स्वागत झाले आहे.

(संदर्भ : दिनांक १७/१०/२०२५ चा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचा त्यांच्या वेबसाईटवर प्रकाशित Writ Petition No. 10750 of 2022 चा संबंधित निकाल आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर प्रकाशित दिनांक २० एप्रिल २०२६ चा संबंधित निकाल)

लेखक - भालचंद्र कुलकर्णी, पुणे. मो.नं.- ९८२२८ ८२५०९

\*\*\*\*\*

# संस्कारातून सहकार - सहकारातून समृद्धी

**\* संस्कारांचे महत्त्व** - साधारण ६०-६५ वर्षांपूर्वीचा, माझ्या बालपणीचा काळ. आम्ही पाच भावंडे आईभोवती कडे करून बसायचो. मोठ्यांपासून सुरुवात करून सर्वांना चहा देणे किंवा जेवणाची ताट देणे आणि मग स्वतः घेणे हे माझे म्हणजे सगळ्यात धाकट्याचे काम असायचं. थोरल्या भावाला अपुरे होणारे कपडे व त्याची जुनी पुस्तके वापरणे, त्याच्या वह्यांतील रिकामे कागद काढून नव्या वह्या तयार करणे यात आम्हाला काहीच गैर वाटत नव्हते. यातूनच 'एक तीळ सात जणांत वाटून खावा' ही म्हण आम्ही शब्दशः जगलो. सहकाराच्याच भावना शिकवावी लागली नाही आणि हेच खरे संस्कार!!

मला वाटतं, त्याकाळी सर्व गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये असेच संस्कार व्हायचे आणि कदाचित त्यामुळेच यातून थोर सहकार महर्षींच्या मनात सहकार्याची बीजे पेरली गेली असतील! बहुसंख्य सहकार अद्वय हे याच वर्गातून पुढे आलेले आहेत. जसे ग्रामाधीन सहकाराच्या संस्कारांमुळे अनेक फायदे झाले. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्येसुद्धा असेच संस्कार घडले. मित्राला, शेजाऱ्याला मदत करावी, दारी आलेल्या याचकाला विन्मुख पाठवू नये अशा संस्कारांमुळेच शाखेतील स्वयंसेवक समाजाच्या मदतीसाठी प्रथम पुढे जातो आणि तेही कोणताही गाजावाजा न करता!! त्याचप्रमाणे समाजामध्ये देखील एकमेकांना मदतीचा हात दिल्याने विना सहकार नाही उद्धार याची जाणीव अनेक लोकांना झाली.

**\* संस्कारातून सहकार** - औद्योगिकीकरणाच्यापूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था ही बंदिस्त अर्थव्यवस्था गणली जायची. भारताची निर्यात नगण्य होती; मात्र आयात जास्त म्हणून इथला माल इथेच खपवायला लागायचा!! रुपया भारतातच राहायचा. सर्वसामान्यांच्या चाकोरीबद्ध जीवनात नाविन्यपूर्ण असे काहीही नव्हते. त्यावेळी गरिबांच्या किंवा गृहिणींच्या हाती पैसा येणे दुरापास्त होते आणि त्यातूनच मार्ग निघाला तो भिशीचा. ग्लोबल्ली चालणारी भिशी योजना अनेक गृहिणींच्या स्वप्नपूर्तीला सहाय्यभूत ठरते आहे. सहकारामुळेच खरेदीची कुवत प्राप्त होते. सहकारामुळेच स्वामित्वप्राप्ती होते, निर्णयक्षमता अंगी बाणते. सामान्य शेतकरीदेखील सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या साखर कारखान्याचा भागीदार झाला आहे. नफ्याच्या वाटपातील कमिशनखोरीला आळा बसला आहे. सहकाराचे - धवलक्रांतीचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजेच डॉ. वर्गीस कुरियन यांचे अमूल सहकारी बँकांनी तर देशभर जाळे पसरवून सर्वसामान्यांना आर्थिक मदत देण्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे, हे निःसंशय. समाजाच्या सर्व घटकांच्या प्रगतीसाठी विविध योजनांना मूर्त स्वरूप देणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक सहकारी संस्था व बाजारपेठा स्थापन केल्या. डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी देशातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याची निर्मिती केली. वैकुंठभाई मेहता हे तर एक वेगळेच रसायन. स्वतः गर्भश्रीमंत असूनही गरिबांसाठी कार्य करण्याची उमेद त्यांनी राखली आणि शेवटपर्यंत गरिबांसाठी ते कार्य करीत राहिले. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रयत्नांमुळेच सहकारी चळवळीत शासन सहभाग आला आणि नवीन पर्व उदयाला आले. ग्रामीण भागात विकेंद्रीकरण करणे, औद्योगिकीकरण करणे, सहकारी संस्था स्थापन करणे याला त्यांनी चालना दिली. सहकारी संस्थांमध्ये राजकारणी जोडे बाहेर ठेवले पाहिजेत, असे त्यांचे ठाम मत होते. यशवंतराव चव्हाण यांनी पंचायत राज सशक्त केले तर वसंतदादांनी मार्केटयार्डची निर्मिती केली.

**\* सहकार विस्तार** - १९४७ नंतर सहकार चळवळीमध्ये राजकारण होऊ लागले. सहकारातल्या अडचणी सोडविण्यासाठी धडाडीने त्याचा बिमोड करण्यासाठी नाव पुढे आले ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला वाहून घेतलेल्या चार भावांतील एक - लक्ष्मणराव माधवराव इनामदार अर्थात वकील साहेबांचे. सहकारामध्ये

राजकीय शक्तींचा हस्तक्षेप आणि सहकाराचे स्वाहाकारात झालेल्या रूपांतराने लक्ष्मणराव प्रचंड अस्वस्थ होते. सहकार क्षेत्रामध्ये जर निस्पृह, निस्वार्थी, अनन्यभावाने - सेवाभावाने काम करणारी माणसे असतील तर सहकार क्षेत्र पुन्हा एकदा तरारून उठेल, याची त्यांना खात्री होती. सहकाराची शिकवण लक्ष्मणरावांना घरातूनच मिळाली आणि त्यातूनच त्यांनी सहकार भारतीची निर्मिती केली. विना सहकार नाही उद्धार याला त्यांनी जोड दिली. 'विना संस्कार नाही सहकार' याचप्रमाणे 'जागृत सभासद सबल सहकार' आणि 'सबल सहकार

समृद्ध भारत' ही सहकार भारतीच्या वाटचालीची सूत्रे त्यांनी दिली. वकिलीच्या शिक्षणानंतर संघकार्यात आयुष्य वाहिलेले लक्ष्मणराव यांच्याबद्दल भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी - 'माझ्यातला कार्यकर्ता घडवणारे' असे गौरवोद्गार काढलेले आहेत; यातच त्यांची महानता कळून येते. कसलाही अहंकार नसलेले लक्ष्मणराव शुद्ध लोकशाहीवादी होते आणि म्हणूनच सर्वांना व्यक्त होण्यासाठी संधी देत सर्वांना बरोबर घेऊन जात त्यांनी यवतमाळ नागरी सहकारी बँक लिमिटेडची स्थापना केली. सहकार क्षेत्रात सर्व विचारांचे सुसंस्कारित कार्यकर्ते असावेत असा त्यांचा आग्रह होता. म्हणून त्यांना एकत्र आणण्याचे काम सहकार भारतीच्या माध्यमातून लक्ष्मणरावांनी केले. अनेक संस्थापक जसे की, माधवराव महादेव हरी तथा

अण्णासाहेब गोडबोले, डॉ. अविनाश आचार्य, अँडव्होकेट अनंत असरकर, श्रीराम आसेगावकर, पंडितराव अभ्यंकर इत्यादी निर्माण झाले आणि दूध उत्पादक सहकारी संस्था, पानमळा सहकारी संस्था, दीनदयाळ नागरी सहकारी संस्था अशा अनेक संस्था उभे राहिल्या की, ज्या आजही जोमाने काम करत प्रगतीपथावर आहेत आणि हेच खरे सहकार भारतीचे यश होय.

**\* सहकारातून समृद्धी** - सेवाभावाने काम करणारी माणसे असतील तर सहकार क्षेत्र पुन्हा एकदा तरारून उठेल याची लक्ष्मणरावांना खात्री होती. सहकारामुळेच सदस्यांच्या गरजांना प्राधान्य मिळते. नफा वृद्धी, रोजगार निर्मिती होते. अपना भांडार, रेल्वे एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी यासारख्या मोठ्या संस्थांमध्ये घाऊक तत्त्वावर खरेदीमुळे सदस्यांना चांगल्या प्रतवारीच्या वस्तू स्वस्तात मिळतात. सहकारी बँकांमुळेच अल्प दरात गृह कर्जे, शिक्षणासाठी कर्जे उपलब्ध होतात. सेल्फ हेल्प ग्रुप / अत्यल्प उत्पन्न गटास यामुळेच उन्नतीचा मार्ग दिसतो. समाज उन्नतीस हातभार लागतो. शाश्वत विकासास पूरक वातावरण निर्माण होते. म्हणूनच आज कित्येक पतपेढ्या आणि विपणन केंद्रे सहकार क्षेत्रात कार्यरत राहून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावत आहेत; शिवाय केंद्र सरकारने स्वतंत्र असे सहकार मंत्रालय जुलै २०२१ मध्ये स्थापन केले आहे. सहकारातून समृद्धी साधण्यासाठीचे शासनाने उचललेले 'भारत टॅक्सीची स्थापना' हे पाऊल पुरेसे बोलके आहे.

**\* उपसंहार** - आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षात पुन्हा एकदा पंच परिवर्तन आणि कुटुंब प्रबोधन यावर भर देत संस्कार आणि सहकारातून समृद्धी याचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. संघ विचाराने दाखवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार झालेली सहकार भारतीची स्थापना आणि त्यानुसार सहकारातून समृद्धीकडे नेणाऱ्या प्रकाशवाटा भारतवर्षाच्या उत्कर्षाचा एक भाग असतील यात काहीही शंका नाही.

- डॉ. श्रीराम विठ्ठल दप्तारदार

निवृत्त कंपनी संचालक व व्यवस्थापन सल्लागार

मोबाईल: ७०२११७२१२६

ई-मेल: Shriram.daptardargmail.com

\*\*\*\*\*

# नेट एनपीए विरुद्ध ग्राँस एनपीए

## आरबीआयचा दृष्टिकोन व ग्राँस एनपीएचे अपरिहार्य महत्त्व

**रि**झर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) सहकारी बँकांच्या आर्थिक विश्लेषणामध्ये अलीकडे नेट एनपीएला अधिक महत्त्व देत आहे.

यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिरता, तरतूद क्षमता आणि जोखीम पेलण्याची क्षमता तपासणे हा असतो.

परंतु यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो -

१) ग्राँस एनपीएचे महत्त्व कमी झाले आहे का?

२) आर्थिक अहवालामध्ये ग्राँस एनपीए दाखवणे बंधनकारक का आहे?

प्रत्यक्षात पाहता, नेट एनपीए आणि ग्राँस एनपीए हे दोन्ही निर्देशक वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी महत्त्वाचे आहेत. नेट एनपीए बँकेची वर्तमान आर्थिक स्थिती दाखवतो, तर ग्राँस एनपीए बँकेच्या कर्ज गुणवत्तेचे आणि भविष्यातील जोखमीचे वास्तविक चित्र समोर आणतो.

**\* ग्राँस एनपीए विरुद्ध नेट एनपीए - मूलभूत फरक**

**ग्राँस एनपीए -** १) एकूण थकीत कर्ज. २) कर्ज मूल्यांकन, कर्जदार निवड आणि देखरेखीची गुणवत्ता दर्शवतो.

**नेट एनपीए -** १) ग्राँस एनपीए - तरतूद. २) बँकेवर येणारा प्रत्यक्ष आर्थिक भार दर्शवतो.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास - ग्राँस एनपीए समस्या किती आहे हे दाखवतो, तर नेट एनपीए त्या समस्येचा बँकेवर उरलेला परिणाम दाखवतो.

**\* आरबीआय नेट एनपीएला अधिक महत्त्व का देते?**

१) **खरी आर्थिक स्थिती** - नेट एनपीए हा तरतुदीनंतरचा आकडा असल्यामुळे ताळेबंदावरील खरा आर्थिक परिणाम स्पष्ट दिसतो.

२) **तरतूद शिस्त** - बँक नियमानुसार योग्य तरतूद करते का, तसेच जोखीम पेलण्याची क्षमता किती आहे हे समजते.

३) **स्थिरतेचा निर्देशक** - नेट एनपीए कमी असल्यास बँक सध्या तुलनेने स्थिर असल्याचे संकेत मिळतात. म्हणूनच आरबीआयच्या देखरेखीमध्ये नेट एनपीएवर विशेष लक्ष दिले जाते.

**\* ग्राँस एनपीए का अत्यंत महत्त्वाचा आहे?**

१) **कर्ज पोर्टफोलिओतील कमकुवतपणा दर्शवतो** - ग्राँस एनपीए जास्त असल्यास खालील नुटी स्पष्ट होतात. चुकीचे कर्ज मूल्यांकन, चुकीची कर्जदार निवड, देखरेखीतील अपयश. म्हणजेच समस्या कर्ज मंजुरीच्या टप्प्यावरच सुरू होते.

२) **पूर्वसूचना संकेत** - नेट एनपीए तरतुदीमुळे काही प्रमाणात नियंत्रणात ठेवता येतो. परंतु ग्राँस एनपीए सतत वाढत असेल, तर भविष्यातील संकट निश्चित असते. म्हणून ग्राँस एनपीए भविष्यातील जोखमीचा निर्देशक.

३) **नफ्यावर थेट परिणाम** - सुरुवातीला नफा चांगला असल्यास तरतूद करून नेट एनपीए नियंत्रणात ठेवता येतो.

परंतु जर ग्राँस एनपीए सतत वाढत राहिला तर १) तरतुदीची गरज वाढली २) नफा कमी झाला ३) भांडवलाची झीज सुरू झाली, तर शेवटी नेट एनपीएसुद्धा वाढतो. म्हणून नेट एनपीए नियंत्रण हा तात्पुरता उपाय आहे; ग्राँस एनपीए नियंत्रण हा कायमस्वरूपी उपाय आहे.

**\* ग्राँस एनपीए आर्थिक अहवालामध्ये बंधनकारक का आहे?**

१) **पारदर्शकता** - ठेवीदार, नियामक, लेखापरीक्षक आणि इतर संबंधित घटकांना बँकेतील वास्तविक धोका किती आहे, हे समजणे आवश्यक असते. फक्त नेट एनपीए कधी कधी दिशाभूल करणारा ठरू शकतो.

२) **मालमतेच्या गुणवत्तेचे खरे प्रकटीकरण** - ग्राँस एनपीए बँकेच्या मालमतेच्या गुणवत्तेचे खरे चित्र समोर आणतो.

तो कर्जपुस्तकाची गुणवत्ता स्पष्टपणे दाखवतो.

३) **व्यवस्थापन कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन** - व्यवस्थापनाने - योग्य कर्ज मंजूर केले का? जोखीम नियंत्रण केले का? हे ग्राँस एनपीएवरूनच स्पष्ट होते.

४) **तरतूद पुरेशी आहे का याची तपासणी** - ग्राँस एनपीए व नेट एनपीए यांची तुलना करून खालील बाबी तपासता येतात - तरतूद योग्य आहे का? अपुरी तरतूद आहे का? सुरक्षित / असुरक्षित भागानुसार तरतूद झाली का?

एनपीए खात्यांतील तारणमूल्याचे पुनर्मूल्यांकन योग्यरीत्या झाले का?

५) **नियामक व लेखापरीक्षाची आवश्यकता** - आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्राँस एनपीए जाहीर करणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षक सुद्धा ग्राँस एनपीएवर विशेष भर देतो.

६) **गुंतवणूकदार व ठेवीदारांचा विश्वास** - ग्राँस एनपीए जास्त असल्यास जोखमीची भावना वाढते.

म्हणून पारदर्शकता अत्यावश्यक ठरते.

**\* ग्राँस एनपीएचा वर्षानुवर्षे तुलनात्मक अभ्यास महत्त्वाचा का?**

आरबीआयच्या परिपत्रकांमध्ये नेट एनपीए टक्केवारी महत्त्वाची असते, कारण ती बँकेची सध्याची आर्थिक क्षमता दर्शवते. परंतु ग्राँस एनपीए हा बँकेचा मूलभूत आरोग्य निर्देशक आहे. म्हणून त्याचा वर्षानुवर्षे (धशरी प धशरी) तुलनात्मक अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

**\* ग्राँस एनपीए वाढला असल्यास** - कर्ज मूल्यांकन / देखरेखीत नुटी आहेत. नवीन थकीत खाती वाढत आहेत. भविष्यातील जोखमीचा ठोस इशारा आहे.

**\* ग्राँस एनपीए कमी झाला असल्यास** - वसुलीचे प्रयत्न प्रभावी आहेत. कर्ज शिस्त सुधारत आहे. पोर्टफोलिओची गुणवत्ता सुधारत आहे.

**\* महत्त्वाची बाब म्हणजे नेट एनपीए तरतुदीमुळे नियंत्रणात आणता येतो, परंतु ग्राँस एनपीएचा कल नियंत्रणात आणणे म्हणजे मूळ समस्या नियंत्रणात आणणे होय. म्हणूनच ग्राँस एनपीएचा वर्षानुवर्षे बदल हा बँकेच्या कामगिरीचा आणि जोखीम व्यवस्थापनाचा खरा निर्देशक आहे. एका वर्षाचा नेट एनपीए कमी असू शकतो, परंतु जर ग्राँस एनपीए सतत वाढत असेल, तर ती दीर्घकालीन टिकावासाठी धोक्याची घंटा असते.**

**\* संतुलित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन नेट एनपीए दर्शवतो, वर्तमान आर्थिक स्वास्थ्य, तरतूद क्षमता.**

**\* ग्राँस एनपीए दर्शवतो -** १) कर्ज गुणवत्ता २) भविष्यातील जोखीम ३) व्यवस्थापन कार्यक्षमता. म्हणून दोन्ही निर्देशक परस्परपूरक आहेत, पर्याय नाहीत.

**\* निष्कर्ष** - आरबीआय नेट एनपीएला महत्त्व देते कारण त्यातून बँकेची सध्याची आर्थिक क्षमता आणि तरतूद क्षमता तपासता येते. परंतु ग्राँस एनपीए हा बँकेच्या कर्ज व्यवस्थेचा मूलभूत आरसा आहे. तो बँकेतील कर्ज मूल्यांकनाची गुणवत्ता, देखरेखीची परिणामकारकता, भविष्यातील जोखीम, व्यवस्थापन कार्यक्षमता, दीर्घकालीन टिकाव यांचे स्पष्ट चित्र समोर आणतो.

म्हणून आर्थिक अहवालामध्ये ग्राँस एनपीए दाखवणे ही केवळ नियामक आवश्यकता नसून, ती बँकेच्या वास्तविक स्वास्थ्याची आवश्यक ओळख आहे. अगदी योग्य शब्दांत सांगायचे झाल्यास नेट एनपीए आपल्याला आपण किती तोटा पेलला हे दाखवतो, परंतु ग्राँस एनपीए आपण किती जोखीम निर्माण केली हे दाखवतो.

- व्यंकटेश कुळकर्णी, प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख.

सहकार भारती सहकार प्रशिक्षण सहकारी संस्था मर्यादित पुणे.

\*\*\*\*\*

# श्रीकृपा ग्रामीण सहकारी संस्थेचा रौप्य महोत्सव उत्साहात साजरा



धुळे - श्रीकृपा ग्रामीण सहकारी संस्था यांच्या रौप्यमहोत्सवी सांगता समारंभ उत्साहात पार पडला. प्रमुख अतिथी म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष अजय ब्रम्हेचा सद्गुरू डॉ. मुकुंदराज महाराज यांच्या उपस्थितीत

हा सोहळा झाला.

ग्रामीण भागात २५ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली पतसंस्था सोसायटी रौप्यमहोत्सव साजरा करत आहे. ही अभिमानाची बाब आहे. संस्थेने गावातील नागरिकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी

मोलाचे योगदान दिले असून अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांना स्वावलंबी बनवले आहे.

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ब्रम्हेचा यांच्या हस्ते संस्था सुरू करीत असलेल्या 'मोबाईल ॲप्स'चेही उद्घाटन करण्यात आले. सहकार भारतीचे प्रदेश संघटन प्रमुख शरद जाधव यांनी धुळे जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक पतसंस्था रौप्यमहोत्सव साजरा करत असल्या तरी श्रीकृपा ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित ही वेगळेपणामुळे विशेष ठरते, असे नमूद केले. धुळे पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शहाजी यांनी मार्गदर्शन केले.

## गोवा शासनाचे नवे सहकार धोरण सहकाराला बळकटी देणारे - शिरोडकर

पणजी, गोवा - गोवा शासनाच्या वतीने नव्याने तयार करण्यात आलेल्या राज्य सहकार धोरणामुळे सहकार क्षेत्राला बळकटी मिळणार आहे, असे मत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी व्यक्त केले आहे. ते एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांच्या हस्ते सहकारी संस्थासाठी ९ ऑनलाईन मोड्युल्सचे अनावरण करण्यात आले.

ते म्हणाले, गोव्यात प्रथमच सहकार धोरण आणण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे हे धोरण केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहे तरी देखील गोवा राज्याच्या आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करण्यात आले आहेत. स्वयंपूर्ण गोवा आणि विकसित भारत करण्यासाठी हे धोरण मदत करणारे ठरणार आहे. तसेच सहकार क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी आणि आवश्यक ते बदल करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. नवीन सहकार धोरणानुसार सहकार क्षेत्रातील कर्मचारी प्रशिक्षण, संस्थांना आर्थिक मदत, डिजिटायझेशन, तक्रार निवारण प्राधिकरण ऑनलाईन सुविधा अशा शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले.

## पूर्णवादी सहकारी बँकेच्या व्यवसायात ९५ कोटीने वाढ

बीड - पूर्णवादी नागरिक सहकारी बँकेने प्रतीवर्षाप्रमाणे आर्थिक कामगिरीचा आलेख उंचावत ठेवला आहे. सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात कामगिरीचा आलेख उंचावला असून बँकेच्या व्यवसायात ९५ कोटींनी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्षाअखेर बँकेच्या एकूण ठेवी ९६१.०१ कोटी असून कर्जे वाटप ५६८.९५ कोटीची आहेत.

बँकेचा एकत्रित व्यवसाय १५२९.९६ कोटींचा झाला आहे. भागभांडवल २९.६४ कोटी असून निव्वळ नफा ४.०६ कोटी एवढा आहे. बँकेच्या नेट एनपीएचे प्रमाण केवळ ०.६२ टक्के आहे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुलकर्णी यांनी माहिती सांगितली. बँकेचे सर्व सभासद, ग्राहक, संचालक व कर्मचारी यांचे मोठे योगदान आहे. अध्यक्ष डॉ. सुभाष जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच बँकेचे ज्येष्ठ संचालक डॉ. अरुण निरंतर यांच्या मार्गदर्शनाने, उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत पारनेरकर, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष सी.ए. एस.पी. लड्डा व सर्व संचालक कार्यरत आहेत.

## राज्याचा सहकार कायदा सक्षम करण्याचा बैठकीत निर्धार

पुणे - राज्याच्या सहकार कायदा बदल समितीच्या माध्यमातून राज्याचा सहकार कायदा अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार नुकत्याच झालेल्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आला. राज्याच्या सहकार कायदा बदल उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक सहकार आयुक्त कार्यालयात झाली. अध्यक्षस्थानी सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे होते.

राज्य सहकार कायदा बदल उच्चस्तरीय समिती सदस्य राज्य सहकारी बँक प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकार भारती प्रदेश महामंत्री विवेक जुगादे, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व्यवस्थापकीय संचालक, संजय खताळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी फेडरेशन अध्यक्ष सुहास पटवर्धन ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशन अध्यक्ष सिताराम राणे,

माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, माजी अपर आयुक्त दिनेश ओऊळकर, एस. बी. पाटील, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण सचिव मिलींद भालेराव आदी बैठकीला उपस्थित होते.

बैठकीमध्ये राज्याच्या कायदा बदल संदर्भात चर्चा झाली. राज्याचे सहकार धोरण ठरल्यानंतर संपूर्ण कायद्यामध्ये कालानुरूप परिवर्तन करण्याचा ठराव करण्यात आला. सहकार कायदा बदल समितीच्या माध्यमातून सहकार कायदा अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार आला.

या बैठकीत नवीन सहकार कायदा करण्यासंदर्भातील विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेचा समावेश कसा करता येईल यावरही भाष्य करण्यात आले.

## अत्याधुनिक सेवा-सुविधांमुळे ग्राहकांमध्ये विश्वासाहता निर्माण - बळीराम जगताप

सातारा - जनता अर्बन को-ऑप. बँकेने अत्याधुनिक सेवा-सुविधांमुळे ग्राहकांमध्ये मोठी विश्वासाहता निर्माण केली आहे. गरजू नागरिकांनी बँकेच्या विविध सेवा-सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बँकेचे अध्यक्ष बळीराम जगताप यांनी केले. येथील १७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

संचालक जगन्नाथ कदम, सुनंदा फरांदे, विठ्ठल कदम, सीए विनय लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली बुलुंगे तसेच माजी संचालक डॉ. विकास फरांदे उपस्थित होते.

बँकेचे संस्थापक-संचालक सुरेश कोरडे यांनी सांगितले. ग्राहकांनी अडचणीच्या काळात बँकेवर दाखवलेला विश्वास हेच बँकेच्या यशाचे मुख्य गमक आहे. विश्वासाच्या बळावर बँकेने सर्वच क्षेत्रात प्रगती साधली. मार्चअखेर शाखेकडे १० कोटींच्या घरात ठेवी जमा झाल्या असून ५ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. शाखेचा एनपीए शून्य टक्के आहे. निव्वळ नफा १३ लाख झाला आहे.

# डिजिटल क्रांती आणि मानवी विश्वास : बँकिंग क्षेत्राचा नवा श्वास!

बँकिंग क्षेत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून जबाबदारी सांभाळताना आणि राज्यभरातील अनेक बँकांमध्ये प्रशिक्षक या नात्याने प्रशिक्षण देण्याचे काम करताना मला एक अनुभव कायम येत गेला. तो म्हणजे, जेव्हा लहान रकमेचे व्यवहार असतात, तेव्हा ग्राहक अत्यंत सहजपणे 'डिजिटल' माध्यमांचा वापर करतात. पण जेव्हा विषय मोठ्या रकमेच्या हस्तांतरणाचा (Large Value Transactions) येतो, तेव्हा ग्राहकाची मानसिकता बदलते. मोठ्या रकमेचे डिजिटल ट्रान्सफर करताना ग्राहकाला केवळ 'क्लिक'वर समाधान मिळत नाही, तर त्याला बँकेच्या प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांचा विश्वास हवा असतो. कर्मचाऱ्याने दिलेला शब्द आणि तो आश्वासक चेहरा असेल तरच ग्राहक समाधानाने आणि निवांतपणे बँकिंग करू शकतो. हा अनुभवच मुळात बँकिंगच्या बदलत्या चेहऱ्याचे वास्तव सांगतो. आज आपण तंत्रज्ञानाच्या शिखरावर असलो, तरी बँकिंगचा पाया हा आजही 'मानवी विश्वासावर' उभा आहे. या पार्श्वभूमीवर, बँकिंगचा नवा प्रवास 'तंत्रज्ञान की मनुष्यबळ' (Digital or physical) या द्वंद्वपेक्षा त्यांच्या सहअस्तित्वावर, म्हणजेच 'फिजिटल' (Phygit) मॉडेलवर कसा आधारलेला आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

आपण जेव्हा बँकिंग आता डिजिटल झाले आहे असे म्हणतो, तेव्हा देशाच्या लोकसंख्येच्या अफाट आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारताची लोकसंख्या १.४० कोटींच्या पार गेली आहे. जरी भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असली, तरी आजही देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ४०% ते ४५% लोक सक्रियपणे इंटरनेटचा वापर करतात. स्मार्टफोनच्या बाबतीतही हेच चित्र आहे, भारतातील सुमारे ३०% ते ४०% लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत.

याचा अर्थ असा की, आजही ५५% ते ६०% लोकसंख्या ही स्मार्टफोन आणि हाय-स्पीड इंटरनेटपासून दूर आहे. अशा परिस्थितीत, जर बँकांनी केवळ डिजिटल होण्याचा अट्टाहास धरला, तर देशाचा एक मोठा भाग बँकिंग मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला जाण्याची भीती आहे. म्हणूनच, बँकिंग सेवा केवळ 'डिजिटल' असून चालणार नाही, तर ती सर्वसमावेशक असणे गरजेचे आहे.

**भारत विरुद्ध इंडिया :** दरी सांधण्याचे आव्हान, माझे वैयक्तिक मत असे आहे की, आपल्या देशात काही लोक 'भारतात' राहतात तर काही 'इंडिया'मध्ये. म्हणजेच, एकीकडे आपण डिजिटल झालो आहोत असे जरी मानले, तरी आजही देशाच्या अफाट लोकसंख्येच्या मानाने किती लोक प्रत्यक्षात स्मार्टफोन वापरतात आणि किती इंटरनेटशी जोडले गेले आहेत, याचा गांभीर्यने विचार करावा लागेल. 'इंडिया'मध्ये राहणारा तरुण एका क्लिकवर कर्ज मिळवतो, तर 'भारत'मध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्याला किंवा सामान्य माणसाला आजही बँकेत जाऊन कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधल्याशिवाय सुरक्षित वाटत नाही. ही डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी बँकांना आता फक्त 'डिजिटल' किंवा फक्त 'फिजिकल' राहून चालणार नाही, तर त्यांना 'फिजिटल' (Phygit) व्हावे लागेल. 'फिजिटल' म्हणजे तंत्रज्ञानाची गती (Digital) आणि प्रत्यक्ष मानवी उपस्थिती (Physical) यांचा अचूक मेळ होय.

बँकिंगमधील ऑटोमेशनमुळे 'कार्यक्षमता' (Efficiency) आणि 'अचूकता' (Accuracy) निश्चितच वाढली आहे. मानवी चुकांची शक्यता कमी झाली असून बँकांकडे असलेला 'बिग डेटा' विश्लेषित करून ग्राहकांच्या गरजा ओळखणे आता सोपे झाले आहे. यूपीआय (UPI)

आणि नेट बँकिंगमुळे व्यवहारांची गती प्रचंड वाढली आहे. यामुळे बँकांचा परिचालन खर्च कमी झाला आहे, ज्याचा थेट फायदा अर्थव्यवस्थेला होत आहे. परंतु, हे तंत्रज्ञान केवळ व्यवहाराचे एक साधन आहे, ते मानवी संवादाची जागा पूर्णपणे घेऊ शकत नाही.

तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी बँकिंग हा मुळात 'विश्वासाचा' (Trust) व्यवसाय आहे. जेव्हा एखादा मध्यमवर्गीय माणूस आपल्या आयुष्यभराची कमाई बँकेत ठेवतो, तेव्हा त्याला केवळ स्क्रीनवर दिसणाऱ्या आकड्यांवर पूर्ण समाधान लाभत नाही. मोठ्या व्यवहारांच्या वेळी ग्राहकाच्या मनात निर्माण होणारी धाकधूक केवळ एक जबाबदार बँक अधिकारीच शांत करू शकतो. मशीनकडे गणना करण्याची बुद्धिमत्ता असू शकते, पण 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' (Emotional Intelligence) नसते. आर्थिक संकट काळात किंवा तांत्रिक अडचणीच्या वेळी जेव्हा व्यवहार अडकतात, तेव्हा ग्राहकाला 'चॅटबॉट'च्या साचेबद्ध उत्तरांपेक्षा एका जिवंत माणसाचा आश्वासक आवाज अधिक धीर देतो. मोठ्या व्यवहारांसाठी लागणारी खात्री हाच बँकिंगचा आत्मा आहे.

'फिजिटल' युगात बँक कर्मचाऱ्यांची भूमिका अधिक आव्हानात्मक आणि महत्वाची झाली आहे. आता कर्मचाऱ्याला केवळ पुस्तकी नोंदी करून चालणार नाही, तर त्याला तंत्रज्ञान आणि ग्राहक यांच्यातील दुवा बनावे लागेल. बँकेत येणाऱ्या ग्राहकाला डिजिटल व्यवहारांचे महत्त्व पटवून देणे आणि त्यांना सुरक्षित डिजिटल बँकिंगचे शिक्षण देणे ही कर्मचाऱ्यांची नवी जबाबदारी आहे. 'सायबर सुरक्षितते'बाबत जनजागृती करण्यासाठी मनुष्यबळाची अत्यंत गरज आहे. आजचा कर्मचारी हा केवळ 'ऑपरेटर' नसून ग्राहकांचा 'सोल्यूशन प्रोव्हायडर' (Solution Provider) आहे. कर्मचाऱ्यांनी तंत्रज्ञानासोबत स्वतःला अद्ययावत करणे, ही काळाची गरज बनली आहे.

बँकिंगचा नवा चेहरा हा केवळ रोबोटिक किंवा केवळ पारंपरिक असून चालणार नाही. तो 'फिजिटल' असायला हवा. तंत्रज्ञान बँकिंगला 'स्मार्ट' बनवेल, तर मनुष्यबळ त्याला 'जबाबदार' आणि 'संवेदनशील' बनवेल आपण भारत आणि इंडिया या दोघांनाही सोबत घेऊन चालले पाहिजे. ४०% स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांसाठी आधुनिक डिजिटल सेवा आणि उर्वरित ६०% लोकांसाठी सक्षम मानवी सेवा, अशा दुहेरी कसरतीतूनच परिपूर्ण बँकिंग सेवा देणे शक्य होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या 'सहकारातून समृद्धी' आणि 'विकसित भारत' या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाची गती आणि मानवी संवेदनांचा विवेक एकत्र येणे आवश्यक आहे तंत्रज्ञान हे इंजिन आहे, तर मनष्यबळ हा त्या इंजिनाला योग्य दिशा दाखवणारा चालक आहे. या दोघांच्या 'फिजिटल' समन्वयातूनच बँकिंगचे भविष्य अधिक उज्ज्वल आणि सुरक्षित होईल.

– मंगेश देहेडकर, सहकार प्रशिक्षक

मो. नं. : ९९२१३ ०४८११

\*\*\*



मंगेश देहेडकर

९९२१३ ०४८११

# जळगाव जनता सहकारी बँकेच्या संचालकपदी जवाहर पटेल, डॉ. विलास रेलन



**जळगाव** – जळगाव जनता सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील दोन रिक्त जागांवर बँकेच्या मुख्य कार्यालयात सहाय्यक निबंधक विशाल ठाकुर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत जवाहर पटेल व डॉ. विलास

रेलन यांची उर्वरित कालावधीसाठी बिनविरोध निवड करण्यात आली.

पटेल हे जळगाव शहरातील व्यावसायिक असून विविध सामाजिक संस्थांशी संबंधित आहेत. डॉ. रेलन हे धुळे येथील असून, सेनादल व खासगी क्षेत्रात वैद्यकीय सेवेनंतर आर्थिक क्षेत्रात सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत.

नवनियुक्त संचालकांचा सत्कार बँकेचे अध्यक्ष सतीश मदाने व सहाय्यक निबंधक विशाल ठाकुर यांचे हस्ते करण्यात आला. ज्येष्ठ संचालक अनिल राव, डॉ. अतुल सरोदे, जयंतीलाल सुराणा, हरिश्चंद्र यादव, विवेक पाटील, डॉ. सुरेंद्र सुरवाडे, हिरालाल सोनवणे, मधुकर पाटील, नितीन झंवर, डॉ. पराग देवरे, डॉ. आरती हुजुरबाजार, संध्या देशमुख, सुभाष लोहार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय नागमोती, वरिष्ठ महाव्यवस्थापक सुनिल अग्रवाल व सुनीत तिजारे उपस्थित होते. केशवस्मृती समुहाचे प्रमुख डॉ. भरत अमळकर व संजय बिरला यांनी नवनियुक्त संचालक यांचे अभिनंदन केले आहे.

## पतसंस्था पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण यशस्वी

**यवतमाळ** – महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागरी/ग्रामीण व नोकरदार पतसंस्थांचे अधिकारी कर्मचारी व पदाधिकारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण येथे आयोजित करण्यात आले होते.

अध्यक्ष अजित डेहनकर यांचे स्वागत धनंजय डोईफोडे यांनी केले. अध्यक्षीय भाषण डेहनकर यांनी केली. प्रशिक्षण का करावे यासाठी लाकूडतोड कामगारांचे उदाहरण देऊन महत्त्व पटवून दिले. यामधून प्रशिक्षणाचा महत्त्वाचा घटक समजावण्यात आला, याबाबत माहिती त्यांनी सांगितली.

## देवगिरी बँकेचे विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम

**छत्रपती संभाजीनगर** – देवगिरी नागरी सहकारी बँकेच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम यशस्वीरित्या करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला चालना देण्यासाठी संगीत साहित्य, तसेच आवश्यक ते साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले.

बँकेच्या वतीने सामाजिक बांधिलकीच्या जाणिवेतून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी सांगितली. कार्यक्रमाला महापौर समीर राजुरकर, महापालिका आयुक्त अमोल येडगे उपस्थित होते.

बँकेचे अध्यक्ष शितोळे यांनी सांगितले की, परिस्थिती कशीही असली तरी जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर सामोरे गेल्यास यश नक्की मिळते. यावेळी संचालक राजेश सावळकर, सुरेश जगाडे, सरदारसिंग बैनाडे, शुभदा वैद्य, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण नांदेडकर उपस्थित होते.

## विभागीय सहनिबंधक कार्यालयातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा स्नेह मेळावा

**नागपूर** – येथील सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधक लेखा परीक्षण कार्यालयातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा स्नेह सोहळा नुकताच पार पडला. विभागीय सहनिबंधक सदानंद वुडके यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यामध्ये ६२ सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांना सन्मानचिन्ह प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले.

कर्मचाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त करून सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. विभागीय सहनिबंधक विनोद पारनवार यांनी सूत्रसंचालन तर उपलेखापरीक्षक जान्हवी लांभाडे यांनी प्रास्ताविक आणि प्रशांत ठाकरे यांनी आभार मानले.

## निवेदिता महिला सहकारी पतसंस्थेचा पाणपोई उपक्रम

**नवरागाव** – निवेदिता महिला सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने बस स्थानकावर थंड पाण्याची पाणपोई उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. याबरोबर अन्य विविध सामाजिक उपक्रम हाती घेण्यात येत असतात. त्यामध्ये गुणवंत विद्यार्थी सत्कार, समाज सेवाव्रतींचा सत्कार, आरोग्य शिबीर असे विविध उपक्रम घेण्यात येतात.

पाणपोई उपक्रमाचे उद्घाटन शशिकांत मेश्राम आणि रजनी मेश्राम यांच्या हस्ते करण्यात आले. संस्थेच्या सध्या ११ शाखा कार्यरत आहेत.

## निवेदिता महिला सहकारी पतसंस्थेच्या १२व्या शाखेचे उद्घाटन

**नवरागाव** – निवेदिता महिला सहकारी पतसंस्थेच्या १२व्या शाखेचे आणि नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन विश्व हिंदू परिषदेचे विदर्भ प्रांत सेवा सहविभाग प्रमुख मनोह हंबर्डे यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. यावेळी माजी आमदार कृष्णा गजबे, संस्था अध्यक्ष सुनंदा वाकरे आदी संचालक अधिकारी उपस्थित होते. संस्थेच्या सध्या १२ शाखा कार्यरत असून २१९ कोटींच्या ठेवी आहेत. सूत्र संचालन धनवंत लोंधे यांनी तर उपाध्यक्ष प्रज्ञा कवासे यांनी आभार मानले.

## संत सोपानकाका सहकारी बँकेला १०.६३ कोटी नफा

**पुणे** – संत सोपानकाका सहकारी बँकेने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात १३.०७ कोटीपेक्षा अधिक व्यवसाय पूर्ण केला आहे तर नफा १०.६३ कोटी इतका मिळविला आहे. बँकेने राज्यात २० शाखांसह विस्तार केला आहे. बँक कार्यक्षेत्र पुण्यासह ९ जिल्ह्यात आहे. एकूण ठेवी ८३०.६७ कोटी असून कर्ज वाटप ४७६.४७ कोटी इतके करण्यात आले आहे. एनपीएचे प्रमाण शून्य टक्के राखण्यात यश मिळविले आहे, अशी माहिती बँक अध्यक्ष रमणिकलाल कोठाडिया यांनी सांगितली.

## दि नांदेड मर्चंट्स को-ऑप. बँकेच्या २२व्या शाखेचा प्रारंभ

नांदेड - येथील दि नांदेड मर्चंट्स को-ऑप. बँकेच्या २२व्या शाखेचा प्रारंभ नुकताच झाला. सुंदरलाल सावजी सहकारी बँक अध्यक्ष मुकुंद कळसकर ओमप्रकाश देवडा पीपल्स को-ऑप. बँक उपाध्यक्ष सुनील देवडा हे उपस्थित होते. बँक अध्यक्ष लक्ष्मण संगेवार यांनी बँकेच्या आर्थिक प्रगतीचा आणि विविध योजनांचा आढावा घेतला. एकूण ठेवी ८२४ कोटी असून कर्ज वाटप ५२१ कोटी इतके करण्यात आले आहे. भाग भांडवल २७ कोटी आहे. बँकेने आजवर १ हजार ३५० कोटी रुपयांचा व्यवसायाचा टप्पा गाठला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सनतकुमार बनवसकर यांनी सूत्रसंचालन तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा देशमुख यांनी आभार मानले.

## नांदणी सहकारी बँकेने पूर्ण केला एकूण ४०० कोटींचा ठेवींचा टप्पा

जयसिंगपूर, कोल्हापूर - येथील नांदणी सहकारी बँकेने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण ४०० कोटींचा ठेवींचा टप्पा पूर्ण केला आहे. बँकेला ४ कोटी ९८ लाख ढोबळ नफा मिळविला आहे, अशी माहिती बँक अध्यक्ष अप्पासाहेब लट्टे यांनी सांगितली. बँकेने शून्य टक्के एनपीएची परंपरा कायम टिकविली आहे. बँकेचे भाग भांडवल १५ कोटी ३८ लाख असून राखीव निधी २७ कोटी ६३ लाख झाला आहे. बँकेने विविध योजनेत १६५ कोटी ६६ लाख सुरक्षित गुंतवणूक केली आहे.

## सहकारी पतसंस्था पिग्मी एजंटाचे कमिशन अडीच टक्क्यांपर्यंत

पुणे - सहकारी पतसंस्थांच्या पिग्मी एजंटाचे कमिशन अडीच टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, अशा सूचना सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिल्या आहेत. यामुळे दर समान असल्याने एकसूत्रीपणा आणि निकोप स्पर्धा अपेक्षित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांनी सुधारित आदर्श उपविधी स्वीकारले असले अथवा नसले तरी दैनिक बचत प्रतिनिधीमार्फत जमा करण्यात येणाऱ्या



ठेवींबाबत त्यांना देय कमिशन २.५ टक्के पेक्षा अधिक असणार नाही असे त्यांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून कर्ज वितरण, कर्ज वसूली अथवा अन्य कामे करता येणे शक्य आहे मात्र त्यासाठी कोणतेही कमिशन दिले जाणार नाही.

राज्यात सध्या नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था १३ हजार ४१२ असून त्यातील ठेवीची रक्कम ७२ हजार ६८४ कोटी इतकी आहे तर पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था संख्या ६ हजार ५३८ असून त्यातील ठेवी १७ हजार ८१६ कोटी इतकी आहे. म्हणजे राज्यातील २० हजार पतसंस्थांमध्ये ९० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. ठेवी संकलनात सहभागी प्रतिनिधी यांचा कमिशनचा दर एकच असल्याने याचा फायदा पतसंस्थांसह सर्व घटकांना होणार आहे.

## चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेला ४२ कोटी ७५ लाख व्यवसायिक नफा

चिपळूण - चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेने केवळ ३२ वर्षांच्या कार्यकाळात उल्लेखनीय आणि दिमाखदार प्रगती साधली आहे. मार्च २०२६ अखेर संस्थेला ४२ कोटी ७५ लाखांचा व्यवसायिक नफा झाला असून, संस्थेने २३११ कोटींच्या व्यवसायाचा टप्पाही पूर्ण केला आहे.

संस्थेची सभासद संख्या १ लाख ४६ हजार ६८२ इतकी असून भाग भांडवल ८४ कोटी तर एकूण स्वनिधी १८२ कोटी इतके आहे. केवळ ३२ वर्षांच्या कालखंडात सभासद संख्या, भाग भांडवल व स्वनिधी या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ साधत राज्यातील निवडक अग्रगण्य संस्थांमध्ये पतसंस्थेने भक्कम स्थान निर्माण केले आहे.

संस्थेच्या ठेवी १२४५ कोटी असून एकूण कर्जव्यवहार १०६६ कोटी आहे. एकूण व्यवसाय २३११ कोटीचा असून या वर्षात २५०० कोटींच्या



टप्पापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

संस्थेचे एकूण स्वनिधी १८२ कोटी इतके आहे. आर्थिक बळकटीसह सामाजिक बांधिलकी जपण्यातही संस्थेला लक्षणीय यश प्राप्त झाले आहे. सभासदांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच ठेवीदारांनाही त्यांच्या गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त परतावा देण्याची धोरणात्मक भूमिका संस्थेने कायम ठेवली आहे.

गेली २७ वर्षे संस्था आपल्या सभासदांना त्यांच्या भागभांडवलावर १५ टक्के डिव्हिडंड सातत्याने देत आहे. आर्थिक सक्षमतेबरोबरच संस्थेच्या सभासदांच्या हितासाठी प्रतिवर्षी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. पतसंस्थेने विविध ठेव योजना कार्यान्वित केल्या आहेत.

## श्री आनंद सहकारी पतसंस्थेला १ कोटी २१ लाख रुपयांचा नफा

नाशिक - येथील श्री आनंद सहकारी पतसंस्थेने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात १ कोटी २१ लाख रुपयांचा विक्रमी नफा मिळविला आहे, अशी माहिती पतसंस्था अध्यक्ष सुनील जैन यांनी सांगितली. ते म्हणाले, संस्थेच्या ठेवी १ कोटी ८० लाख रुपयांच्या असून कर्ज वितरण १० कोटी ६ लाख इतके करण्यात आले आहे.

तसेच ११ कोटी २४ लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. खेळते भांडवल २३ कोटी ९९ हजार आहे तर नेट एनपीए शून्य टक्के ठेवण्यात यश मिळविले आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी उपाध्यक्ष आणि संचालक उपस्थित होते.

## आदर्श को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीला ३२ लाख ६५ हजार रुपयांचा निव्वळ नफा

सांगली, आटपाडी - येथील आदर्श को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीला नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात ३२ लाख ६५ हजार रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे, अशी माहिती सोसायटीचे अध्यक्ष प्रकाश बोंडे आणि उपाध्यक्ष दीपक देशमुख यांनी सांगितली.

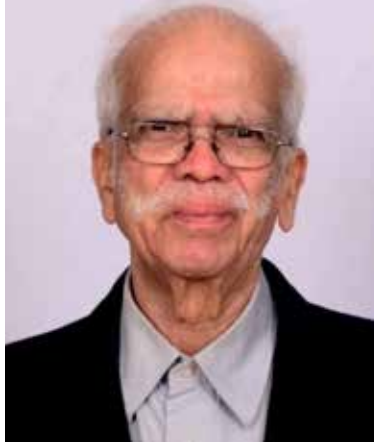
ते म्हणाले संस्थेचे भाग भांडवल १ कोटी १० लाख असून राखीव निधी ९८ लाख ५५ हजार रुपये आहे तर ठेवी ८ कोटी ३३ लाख आणि गुंतवणूक ३ कोटी ५५ लाख ९४ हजार आहे. संस्थेने ७ कोटी १ लाख ७३ हजार इतके कर्ज वाटप केले आहे. वर्षभरात संस्थेने ३७ कोटी ८५ लाख रुपयांची उलाढाल केली आहे. यावेळी संचालक, पदाधिकारी अधिकारी उपस्थित होते.

# सहकारी बँकिंग क्षेत्रात अमूल्य योगदान देणारे डॉ. मुकुंद अभ्यंकर

**डॉ.** मुकुंद अभ्यंकर यांनी सन १९७८ पासून सलग ४६ वर्षांहून अधिक

काळ कॉसमॉस बँकेच्या संचालक मंडळात काम केले. विशेष म्हणजे, त्यांनी तब्बल ९ वेळा बँकेचे अध्यक्षपद भूषवले होते. शालेय शिक्षण पुणे येथे नूतन विद्यालयात झाले. मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण केली. बी.ए.च्या वर्षाला असताना त्यांनी 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स'मध्ये आपले नाव नोंदवले. अर्थशास्त्र विषयातील बी.ए.ची पदवी पुणे विद्यापीठाची अर्थशास्त्र विषयातील एम.ए.ची पदवी संपादन केली. शेतकी खात्यात सांख्यिकी विभागात सहाय्यकाची नोकरी लागली. शेतकी खात्यात अधिकारी असल्यामुळे त्यांना सर्व जिल्ह्यांमध्ये फिरावे लागे. त्याकाळात वाहनांची सोय नसल्यामुळे त्यांना बराचसा प्रवास पायी करावा लागे. परभणी येथे बदली झाल्यावर नोकरीचा राजीनामा दिला. सातारा येथील कूपर इंजिनिअरिंग कंपनीत दाखल झाले.

पुणे विद्यापीठात पीएच.डी.साठी 'व्यवसाय व्यवस्थापन' विषयासाठी नावनोंदणी केली. विद्यापीठाला प्रबंध सादर केला. दै. केसरीमध्ये ते व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. दीड वर्षांनी त्यांनी ही नोकरी सोडली व भोसरी येथे रंग तयार करण्याचा स्वतःचा कारखाना स्थापन केला. दरम्यान नागरी सहकारी बँकेचे प्रभारी सचिव या नात्याने कामाला सुरुवात केली. पदवीधर मतदारसंघातून वाणिज्य विद्याशाखा प्रतिनिधी म्हणून पुणे विद्यापीठाच्या विधी सभेवर बहुमताने निवडून आले वाणिज्य व व्यवस्थापन विभागाची स्थापना केली. पद्मश्री विखे-पाटील सहकार अध्यासन व डी.एस. सावकार बँकिंग अध्यासन



कॉसमॉस सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांचे वृद्धापकाळामुळे निधन झाले. ते ८९ वर्षांचे होते. बँकेच्या संचालक मंडळात सन १९७८ पासून कार्यरत होते आणि बँकेचे अध्यक्षपद त्यांनी ९ वेळा भूषविले होते.

याखेरीज नॅफकबचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले होते. सहकारी बँकिंग क्षेत्रात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. तसेच आरबीआयच्या विविध समित्यांवर त्यांनी काम केले. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, सून, मुलगी, जावई आणि नातवंडे असा परिवार आहे.

या दोन अध्यासनांची स्थापना केली. विद्यापीठात व्यवस्थापनशास्त्राच्या शिक्षणाची व्यवस्थाही केली.

पुणे विद्यापीठाच्या अर्थसमितीवर काम करीत असताना विद्यापीठाला आर्थिक तुटीतून बाहेर आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. वाणिज्य पदवीच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याचे काम केले. बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या काळात बँकेची व्यावसायिक प्रगती करण्यावर पहिला भर दिला. व्यापाऱ्यांनी कर्ज घेताना अर्जासोबत संस्थेचा ताळेबंद सादर केला पाहिजे, ही नवी संकल्पना रूढ झाली. रिझर्व्ह बँकेने त्यांना नागरी सहकारी बँकांसाठी असणाऱ्या 'स्थायी सल्लागार समिती'वर तज्ज्ञ म्हणून नेमले.

व्यास प्रतिष्ठानतर्फे दिला जाणारा महर्षी व्यास पुरस्कार त्यांना देण्यात आला. सहकार शताब्दीनिमित्त गुजरातमधील कालूपूर व्यावसायिक या सर्वात मोठ्या नागरी बँकेने कार्यकर्त्यांचा गौरव केला. त्यामध्ये अभ्यंकरांसहित महाराष्ट्रातील दोन जणांचा समावेश होता. सामाजिक कृतज्ञता प्रतिष्ठानने उत्कृष्ट समाजकार्य करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार देण्यास सुरुवात करण्यात आली. अभ्यंकर या पुरस्काराचे पहिले मानकरी ठरले. त्यांना महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालयातर्फे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील उत्कृष्ट व भरीव कार्याबद्दल आर्यभूषण पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याचा उचित गौरव करण्यात आला.

रोटरी क्लबतर्फे दिला जाणारा सर्व्हिस अबाऊट सेल्फ हा पुरस्कार प्राप्त झाला.

— संजीव वेलणकर, पुणे.

मोबाइल नं. - ९४२२३०९७३३

\*\*\*\*\*

## आर्थिक वर्षात कॉसमॉस बँकेची सर्व आघाड्यांवर यशस्वी कामगिरी

पुणे - नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात कॉसमॉस सहकारी बँकेने सर्व आघाड्यांवर यशस्वी कामगिरी नोंदविली आहे. वर्षाअखेर बँकेने ४४ हजार कोटीचा व्यवसाय पूर्ण केला आहे. बँकेने विविध आघाड्यांवर उत्तम कामगिरीची नोंद केली आहे.

बँकेच्या ठेवीमध्ये ३२१५ कोटीची वाढ झाली आणि एकूण ठेवी २६,११२ कोटी तर कर्ज वाटप १७,८७८ कोटी इतके करण्यात आले आहे. लहान कर्जाचे प्रमाण ५२.५२ टक्के करण्यात आले आहे. बँकेच्या व्यवसायात ५३६६ कोटीची वाढ झाली असून एकूण व्यवसाय ४४ हजार कोटीपेक्षा अधिक झाला आहे म्हणजे १४ टक्के वाढ झाली आहे.

मार्च २०२६ अखेर बँकेच्या ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण ३.१० टक्के असून नक्त अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण ०.९० टक्के आहे.

बँकेने गुजरात राज्यात नव्याने १० शाखा सुरू केल्या आहेत आणि बँकेच्या एकूण ७ राज्यात १९३ शाखा झाल्या आहेत. गुजरात राज्यात ३८ शाखा झाल्या आहेत. आगामी काळात दक्षिण भारतात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर शाखा विस्तार करण्यात येणार आहे.

यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष सीए यशवंत कासार, व्यवस्थापन मंडळ अध्यक्ष सीए मिलींद काळे तसेच व्यवस्थापकीय संचालिका अपेक्षिता ठिपसे आणि संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.



## कॉसमॉस बँक अध्यक्षपदी सचिन आपटे



पुणे - कॉसमॉस सहकारी बँकेचे ज्येष्ठ संचालक सचिन आपटे यांची बँकेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली आहे. विद्यमान अध्यक्ष प्रल्हाद कोकरे यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे रिक्त जागेसाठी निवड करण्यात आली आहे.

बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. आपटे हे सन २०१९

पासून बँकेच्या संचालक मंडळावर कार्यरत आहेत. या कालावधीत त्यांनी बँकेच्या उपाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. ते व्यवसायाने सिव्हील इंजिनियर असून प्रवर्तक आणि विकसक म्हणून गेल्या ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ देशात आणि परदेशात कार्यरत आहेत.

# येता अफवांचे वादळ, संयम ठेवावा प्रबळ!

महाराष्ट्राच्या आर्थिक जडणघडणीत सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांचा वाटा अतिशय मोलाचा आहे. सामान्य माणसाला, बळिराजाला आणि छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणण्याचे ऐतिहासिक काम या संस्थांनी केले आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या क्षेत्राबद्दल एक प्रकारची कमालीची संवेदनशीलता निर्माण झाली आहे. फेसबुक किंवा व्हॉट्सअपसारख्या समाज माध्यमांतून पसरणाऱ्या एखाद्या निनावी चित्रफितीमुळे किंवा संदेशामुळे दशकानुदशके निष्ठेने उभा केलेला विश्वासाचा डोलारा क्षणात कोसळू पाहत आहे. हे केवळ अर्थकारण नाही, तर हा जनमानसातील विश्वासाचा खेळ आहे. कारण 'तिजोरीतील पैशापेक्षा लोकांच्या मनातील विश्वास हाच बँक आणि पतसंस्थेचे खरे भांडवल असते.' जेव्हा हा विश्वास डळमळीत होतो, तेव्हा होणारे नुकसान हे केवळ त्या एका संस्थेचे नसते, तर ते संपूर्ण सहकार चळवळीचे आणि पर्यायाने सामान्य ठेवीदारांच्या कष्टाचे असते.

इतिहासात डोक्यावर पाहिले, तर केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही अशा अनेक बँका आणि पतसंस्थांची उदाहरणे आहेत, ज्या केवळ अफवांच्या वादळामुळे आणि लोकांच्या अतिघबराटीमुळे कोसळल्या. एखादी वित्तीय संस्था प्रत्यक्षात बंद पडण्यापेक्षा, ती बंद होईल, या केवळ 'भीतीपोटी' होणारी पळापळ त्या संस्थेला जास्त घातक ठरते. हे वास्तव आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.

जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज म्हणतात, 'धैर्य धरी धरी, उतरसी पैलतीरी' म्हणजेच संकटाच्या काळात केवळ संयम आणि धैर्यच आपल्याला तारून नेऊ शकते. मुळात कोणतीही वित्तीय संस्था एका रात्रीत कधीच अडचणीत येत नाही, ती व्यक्ती-केंद्रित असली, तरी तिची आर्थिक मुळे खोलवर रुजलेली असतात. त्यामुळे, ठेवीदारांनी अशा संकटाच्या वेळी सारासार विचार करून, केवळ कोणाच्या तरी सांगण्यावरून घाईने मुदतपूर्व पैसे न काढता प्रबळ संयम राखणे, हाच स्वतःच्या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्याचा आणि संस्थेचे अस्तित्व टिकवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरतो.

कोणत्याही संस्थेवर आर्थिक अडचणी या नेहमी टप्प्याटप्प्याने येत असतात आणि त्यावर मात करण्यासाठी व्यवस्थापनाकडे पुरेसा वेळ असतो. परंतु, दुर्दैवाने आजच्या वेगवान युगात 'अफवा' मात्र वाऱ्याच्या वेगाने पसरतात. फेसबुक किंवा व्हॉट्सअपवर एखादा छोट्यासा निनावी संदेश फिरतो, की 'अमुक एक बँक किंवा पतसंस्था अडचणीत आहे, किंवा बंद होणार आहे,' आणि त्या एका चुकीच्या माहितीमुळे हजारो ठेवीदार कसलीही शहानिशा न करता एकाच वेळी बँकेच्या दारात उभे राहतात. जेव्हा लोक केवळ भीतीपोटी आपल्या ठेवी काढून घेण्यासाठी झुंबड करतात, तेव्हा त्यातून एक कृत्रिम संकट निर्माण होते. ठेवीदारांनी हे तांत्रिक वास्तव समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, की कोणत्याही वित्तीय संस्थेचे कामकाज हे 'तरलता' आणि 'गुंतवणूक' या दोन मुख्य तत्वांवर चालते.

उदाहरणार्थ, तुम्ही बँकेत १०० रुपये ठेवले, तर ती संस्था कायदानुसार त्यातील दैनंदिन व्यवहारापोटी काही रक्कम स्वतःकडे, तर निर्धारित तरलतेपोटी मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये गुंतवणूक अशी एकूण ३० ते ३५

टक्के रक्कम बाजूला ठेवते; आणि उर्वरित ६५ ते ७० टक्के रक्कम इतर गरजू सभासदांना कर्जरूपाने वाटली जाते. या वाटलेल्या कर्जाच्या व्याजातूनच संस्था आपला खर्च भागवते आणि ठेवीदारांना व्याज देते. अशा परिस्थितीत, जर १५ ते २० टक्के ठेवीदारांनी एकाच वेळी त्यांचे सर्व पैसे परत मागितले, तर जगातील कोणतीही बँक मग ती सरकारी असो, खासगी असो वा सहकारी... एवढी मोठी रोख रक्कम एकाच वेळी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. अशा वेळी बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही केवळ रोख रकमेच्या अभावामुळे हतबल होते आणि यातूनच सुस्थितीत असलेल्या संस्थेचा अंत होतो.

सहकारी संस्थांच्या विश्वात 'व्यवस्थापन संकट' आणि 'आर्थिक संकट' यातील सीमारेषा समजून घेणे ठेवीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेकदा एखाद्या बँकेचे किंवा पतसंस्थेचे अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैधानिक कालमर्यादामुळे, वाढत्या वयामुळे किंवा कायदेशीर तरतुदींच्या पालनासाठी पदावरून पायउतार होतात अथवा राजीनामा देतात. परंतु अशा वेळी सामान्य ठेवीदारांमध्ये विनाकारण घबराट पसरते. याला जितकी ठेवीदारांची भीती कारणीभूत असते, तितकीच संस्थेची कार्यपद्धतीही जबाबदार असते.

संस्थेची व्यवसाय वृद्धी करताना अनेक ठिकाणी ही संस्था अमुक एका व्यक्तीचीच आहे, किंवा 'संस्थेशी संबंधित सर्व निर्णय अमुक एक किंवा दोनच व्यक्ती घेतात,' असे चित्र

जनमानसासमोर सतत मांडल्यामुळे आणि एखाद्या व्यक्तीलाच सर्वस्व मानल्यामुळे, उद्या ती व्यक्ती पदावरून बाजूला झाली, की ठेवीदारांचा संस्थेवरील विश्वासही डळमळीत होतो. नेतृत्वाचे असे उदात्तीकरण करणे संकटकाळात संस्थेसाठीच धोक्याचे ठरते. वास्तविक, नेतृत्व बदलल्याने उद्भवणारे 'व्यवस्थापन संकट' हे केवळ प्रशासकीय असते, त्याचा अर्थ संस्थेची तिजोरी रिकामी झाली असा मुळीच नसतो. उलट, अशा काळातही संस्थेचा पाया मजबूत असू शकतो. जोपर्यंत संस्थेचा ताळेबंद भक्कम आहे, तोपर्यंत खुर्चीवर कोण बसले आहे यावरून भीती वाटून घेणे हे स्वतःचेच आर्थिक नुकसान करून घेण्यासारखे आहे.

याउलट, 'आर्थिक संकट' हे थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढल्याने येते. जर एखाद्या संस्थेची प्रमुख व्यक्ती काही वैयक्तिक कारणामुळे किंवा राजीनाम्यामुळे बाजूला झाली, तर तो त्या व्यक्तीचा प्रश्न असतो, संस्थेच्या आर्थिक क्षमतेचा नाही; मात्र लोक अशा वेळी आता प्रमुख माणूसच नाही, तर आमचे पैसे बुडणार का? अशा भ्रामक भीतीपोटी पैसे काढण्यासाठी गर्दी करतात. ही झुंबड एका चांगल्या चाललेल्या संस्थेची रोख तरलता संपवते आणि एका साध्या प्रशासकीय बदलाचे रूपांतर भयंकर आर्थिक आपत्तीत होते. म्हणूनच, संस्थेची ओळख ही 'व्यक्ती' नसून तिची 'आर्थिक शिस्त' असली

पाहिजे. जोपर्यंत संस्थेचा ताळेबंद भक्कम आहे, तोपर्यंत खुर्चीवर कोण बसले आहे यावरून भीती वाटून घेणे हे स्वतःचेच मोठे आर्थिक नुकसान करून घेण्यासारखे आहे. सुस्थितीत असलेली संस्था केवळ लोकांच्या अनाटायी भीतीमुळे आणि संस्थाचालकांकडून केलेल्या व्यक्ती-केंद्रित प्रचारामुळे डबघाईला येणे, हे सहकार चळवळीचे मोठे दुर्दैव आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील एका तांत्रिक सत्याचा ठेवीदारांनी गांभीर्याने विचार

पुढील पानावर...



गणेश निमकर

९८२२५ ६८५५०



## येता अफवांचे वादळ, संयम ठेवावा प्रबळ!

करणे आवश्यक आहे. कोणतीही बँक अथवा पतसंस्था आपल्याकडील सर्व पैसा तिजोरीत कुलूप लावून ठेवत नाही; त्यातील मोठा हिस्सा गरजू कर्जदारांना दिलेला असतो, ज्यातून मिळणाऱ्या व्याजातूनच ती बँक अथवा पतसंस्था ठेवीदारांना परतावा देते. जेव्हा आपण अफवांना बळी पडून पैसे काढण्यासाठी रांगा लावतो, तेव्हा आपणच त्या संस्थेची रोख तरलता संपवून तिला आर्थिक कोंडीत पकडतो. संस्था सक्षम असूनही केवळ लोकांच्या अनाठांशी भीतीमुळे ती वेळेवर पैसे देण्यात असमर्थ ठरते, म्हणूनच अशा वेळी 'संयम हाच सर्वात मोठा विमा' ठरतो. यामुळेच, गुंतवणूक करताना केवळ परताव्याचा विचार न करता सुरक्षिततेचा समतोल राखणे ही काळाची गरज आहे.

सहकारी बँकांमधील ठेवींना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते, जे नागरी पतसंस्थांच्या बाबतीत सद्यःस्थितीत उपलब्ध नसले, तरी पतसंस्थांचे कामकाज केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली चालते, जिथे व्याजदर आकर्षक असले, तरी सद्यःस्थितीत विम्यासारख्या सुरक्षेची हमी नसते. त्यामुळे केवळ अधिक व्याजाच्या आमिषाने सर्व पुंजी एकाच संस्थेत न ठेवता ती विभागून ठेवणे अधिक शहाणपणाचे ठरते. आता बँकिंग नियमन कायदानुसार प्रत्येक संस्थेला आपली आर्थिक स्थिती, बुडीत कर्जे आणि गुंतवणुकीचा तपशील फलकावर किंवा वार्षिक अहवालात जाहीर करणे बंधनकारक आहे. केवळ पासबुक अद्ययावत करण्याबरोबरच या माहितीचा अभ्यास करणे हा तुमचा अधिकार आहे

गुंतवणूक करणे म्हणजे केवळ संपत्ती वाढवणे नव्हे, तर ती सुरक्षित हातांत सोपवणे होय. समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात, 'आधी प्रचिती मग विश्वास'; म्हणजेच कोणत्याही संस्थेत पैसे ठेवण्यापूर्वी तिची प्रत्यक्ष स्थिती पारखून घेणे हाच शहाणपणा ठरतो. यासाठी संस्थेचा लेखापरीक्षण वर्ग सलग तीन वर्षे 'अ' असणे अनिवार्य आहे. तांत्रिकदृष्ट्या संस्थेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण भक्कम असावे, जेणेकरून भविष्यातील कोणत्याही धक्क्याला सोसण्याची ताकद संस्थेत राहील. अनुत्पादित कर्जांचे (थकीत कर्जांचे) प्रमाण ५ टक्क्यांच्या आत असणे सुदृढ आरोग्याचे लक्षण आहे.

विशेषतः जोखीम केंद्रीकरण तपासताना, संस्थेचे पहिले २० मोठे ठेवीदार व कर्जदार यामध्ये एकूण ठेवींचा व कर्जांचा किती मोठा हिस्सा आहे, याकडे डोळसपणे पाहावे. हे प्रमाण जेवढे अधिक, तेवढा त्या संस्थेचा तरलतेचा धोका अधिक असतो. जर मोठ्या कर्जदारांमध्येच थकबाकी असेल, तर संस्थेचा पाया डळमळीत होतो. तसेच, ठेव-कर्ज प्रमाण ६५ ते ७० टक्क्यांच्या दरम्यान असावे, जेणेकरून ठेवीदारांना पैसे परत देताना तरलता टिकून राहील. आजच्या युगात केवळ आर्थिक व्यवहारच नव्हे, तर संस्थेची संगणकीय सुरक्षा किती मजबूत आहे, हे पाहणेही तितकेच गरजेचे आहे.

काही वेळा संस्था बंद होणार आहे या अनाठांशी भीतीपोटी ग्राहक अफवांना बळी पडतात. अशा वेळी ग्राहक केवळ मुदत संपण्यापूर्वीच आपल्या ठेवी काढून घेत नाहीत, तर सोने-जिन्नस अथवा आपली अन्य तारण मिळकत सोडवण्यासाठी चक्क सावकाराकडून पठाणी व्याजाने पैसे घेऊन कर्ज बंद करतात. जेव्हा ग्राहक असा टोकाचा निर्णय घेतो, तेव्हा ते दुहेरी नुकसान ठरते. पहिले नुकसान ग्राहकाचे असते; कारण ठेवींवरील हक्काच्या व्याजावर पाणी सोडावे लागते आणि दुसरीकडे सावकारी व्याजाचा मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.

दुसरे नुकसान संस्थेचे असते; कारण ठेवीदारांच्या या आकस्मिक गर्दीमुळे संस्थेचे आर्थिक नियोजन कोलमडते आणि त्यांना आपली गुंतवणुकीचे नुकसान सोसून रोखीकरण करावे लागते. तसेच, भीतीपोटी मोठ्या प्रमाणात कर्ज रकम एकदम जमा झाल्याने संस्थेचे देखील मोठे आर्थिक नुकसान होते. थोडक्यात, घबराटीतून घेतलेला असा कोणताही निर्णय ग्राहक आणि संस्था या दोघांसाठीही आर्थिकदृष्ट्या घातक ठरतो.

सहकार क्षेत्रातील संस्था या आपल्याच समाजातील लोकांनी लोकांसाठी उभ्या केलेल्या असतात, त्यामुळे त्यांना जपणे ही आपली सर्वांचीच सामाजिक जबाबदारी आहे. परंतु, ही जबाबदारी पार पाडताना सजग आणि डोळस असणे गरजेचे आहे. संस्थेचे सभासद आणि ग्राहक

यांना व्यवहार करताना तसेच संस्थेच्या आर्थिक स्थितीविषयी परिपूर्ण आणि अचूक माहिती देऊन पारदर्शकता राखणे, ही जशी संस्थेची नैतिक जबाबदारी आहे; तशीच ती माहिती समजून घेणे हे ग्राहकांचे कर्तव्य आहे. जेव्हा संस्था, ठेवीदार आणि कर्जदार यांच्यातील हा संवादाचा सेतू तुटतो, तेव्हाच संशयाचे भूत उभे राहते आणि अफवांचे पीक फोफावते. अशा परिस्थितीत पारदर्शकता आणि ग्राहक साक्षरता हेच अफवांवरचे एकमेव प्रभावी औषध आहे

गुंतवणूक करताना ग्राहकाने देखील अत्यंत सतर्क राहणे गरजेचे आहे. केवळ अफवांवर अंधविश्वास न ठेवता, एक जागरूक ग्राहक म्हणून संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचा वेळोवेळी

आढावा घेणे आवश्यक आहे. एक जबाबदार ग्राहक या नात्याने, अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत संस्थेला सहकार्य करण्याची जशी ग्राहकाची जबाबदारी आहे, तसेच संस्थेचे आर्थिक बाबतीत काही चुकत असेल, तर वेळीच व्यवस्थापनाला सावध करणे हे देखील त्याचे कर्तव्य आहे.

अफवांवर अंधविश्वास ठेवून आपल्या कृतीमुळे संस्थेचे आणि इतर ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये, ही प्रत्येक ग्राहकाची जशी नैतिक जबाबदारी आहे; तसेच आपण ज्याला आपला 'रखवालदार' (वित्तीय संस्था) मानले आहे, तो कायम प्रामाणिक आणि शिस्तबद्ध राहावा यासाठी जागरूक राहणे हे आपले देखील ठेवीदारांचे कर्तव्य आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात, 'धनासाठी आणिला रखवालदार, त्यानेच धनाचा केला फस्त पारा' अशी देखील वेळ आपल्यावर येऊ नये, यासाठी आपल्या गुंतवणुकीवर वारंवार लक्ष ठेवणे आणि सतत दक्षता घेणे हाच गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे.

थोडक्यात, संस्थेवर विश्वास ठेवतानाच आपली डोळस नजर कायम ठेवणे, यातच सर्वांचे हित आहे. कष्टाने कमावलेला पैसा केवळ समाज माध्यमांवर आलेल्या एखाद्या निनावी संदेशामुळे किंवा भीतीपोटी धोक्यात घालू नका. सहकारी बँका आणि पतसंस्था हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत; ग्राहकांनी संयम आणि जागरूकता दाखवली, तरच हा कणा मजबूत राहील आणि आपली सर्वांगीण आर्थिक प्रगती साधली जाईल.

— गणेश रामचंद्र निमकर, पुणे.

बँकिंग सल्लागार मोबाईल - ९८२२५ ६८५५०

बी. कॉम, जी. जीडीसीए, सी.ए.आय.आय.बी.

ई मेल - nimkarganesh@gmail.com

\*\*\*\*\*

# पतसंस्था, तंत्रज्ञान व मनुष्यबळ व्यवस्थापन यांचा मेळ आवश्यक

तंत्रज्ञान हा भारतीय समाजरचनेतील महत्वाचा भाग झाला आहे. व्यावहारिक समज आलेल्या मुलांपासून तर ८० वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकही रोख रक्कम संभाळण्याच्या समस्येमुळे, वेगवेगळ्या गरजा भागवण्यासाठी, वेळ वाचवण्यासाठी, कॅशलेस व्यवहारासाठी टेक्नॉलॉजी वापरत आहेत. यामुळे अल्पावधीत बँकिंग सेक्टर वेगाने बदलत आहे. पतसंस्थाही स्पष्टतः उतरल्या असल्या, तरी मनुष्यबळ व तंत्रज्ञान याचा मेळ घालताना द्विधा मनःस्थितीत मॅनेजमेंट आहे.

मनुष्यबळ/स्टाफ नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारताना साशंक आहे तर नवीन टेक्नॉलॉजी स्टाफ घेताना सीनिअर स्टाफला जॉबबद्दल शंका मनात येते. परंतु काळानुसार पतसंस्थांना बदलताना अधिकारी व स्टाफ यांची भूमिका निर्णायक असणार आहे. जेथे आवश्यक तेथे तंत्रज्ञान वापरणे, सभासद वर्ग मराठी भाषेवर प्रभुत्व असणारा असल्यामुळे सॉफ्टवेअरही फ्रेंडली व त्यांना वापरास सोपे असेच वापरावे लागणार आहे. नवीन युवा सभासद मिळवणे, कर्ज वितरण व वसुली यात तंत्रज्ञान महत्वाची भूमिका बजावत आहे. क्रेडिट स्कोअर चेकिंग, KYC, बँक खाती पडताळणी, जीएसटी GST व आयटी IT रिटर्न पडताळणी या गोष्टी तंत्रज्ञानाने सोप्या व अल्पावधीत होतात, त्यामुळे कर्ज वितरण सुलभ होत आहे, तर रिकव्हरीसाठी वेगवेगळे मॉडेल सॉफ्टवेअर कंपन्यांकडे आहेत. एआय AI तंत्रज्ञान, एसआय SI, हॅच सारखे मॉडेल आल्यामुळे रिकव्हरी सोपी होत आहे.

पण पतसंस्थांची विश्वासाची परंपरा ही प्रत्यक्ष भेटी, संवादावर, जनसंपर्कावर अवलंबून आहे, हे नाकारून चालणार नाही. यासाठी सीनिअर अधिकारी यांना मार्केटिंग, स्नेह भेटी, सभासदांच्या कुटुंबाशी संवादात्मक संबंध व समुपदेशन यासाठी तयार करावे लागेल. तंत्रज्ञान व मनुष्यबळ हे एकमेकांचे स्पर्धक नाही तर एकमेकांसाठी पूरक आहेत हा विश्वास व खात्री व्यवस्थापनाने सहकाऱ्यांमध्ये निर्माण करणे गरजेचे आहे. जेथे गरज आहे, तेथे सुलभपणे तंत्रज्ञान वापरणे हे पतसंस्थांसाठी गरजेचे आहे. यासाठी स्टाफला वारंवार तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, आपल्याकडे जे सॉफ्टवेअर आहे, त्या कंपनीकडून प्रशिक्षण घेऊन बदलणारे तंत्रज्ञान व नियम यांची सांगड घालायला हवी. कितीही म्हटले तरी आपल्याकडे फेसलेस, नेमलेस बँकिंग-विशेषतः पतसंस्थांमध्ये ही संकल्पना रुजायला

वेळ लागणार आहे. टेक्नॉलॉजी स्वीकारून, त्यात अभ्यासपूर्वक काम करणारा स्टाफ तयार करणे व टिकवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. टेक्नॉलॉजी परिपूर्ण असली, तरी तिचा वापरकर्ता हाही सजग व केलेल्या व्यवहारांची, त्यातून होणाऱ्या परिणामांची जाणीव असणारा असायला हवा आहे.

आपण तंत्रज्ञान क्षेत्रात विकसित झालोय. टेक्नॉलॉजीतही जागतिक पातळीवर वरच्या स्थानी आहोत पण निर्माता व वापरकर्ता यामध्ये मोठी दरी आहे, हे मान्य करावे लागेल. कारण निर्मात्याने तयार केलेले सॉफ्टवेअर किती टक्के % पतसंस्थेतील वापरकर्त्या स्ट्राफपर्यंत पोहोचते हा यक्ष प्रश्न आहे. जोपर्यंत ही दरी कमी होत नाही, तो पर्यंत टेक्नॉलॉजी शाप की वरदान? तंत्रज्ञान विरुद्ध मनुष्यबळ या तुलनेतच अडकणार आहोत. यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या, फिनटेक कंपन्या, स्टार्टअप यांना पुढाकार घेऊन पतसंस्थांमधील सीनिअर स्टाफ, अधिकारी व नवतरुण यांना दर्जेदार ट्रेनिंग वारंवार देऊन तयार करावे लागेल. तंत्रज्ञान आपल्यासाठी वरदान आहे, हे पतसंस्था चळवळीला व स्ट्राफला पटेल, त्या वेळी ते हातात हात घालून संस्थेला टेक्नॉलॉजीत पुढे नेतील, यात शंका बाळगण्याचे कारण नसेल.

डिजिटल बँकिंग प्रणाली, कोअर बँकिंग स्वीकारणे अपरिहार्य तर आहेच पण सहकार विभागही यासाठी आग्रही आहे. आरबीआय कंप्लॉयन्ससाठी बँकांना जशी स्वतंत्र टीम, व्यवस्था करावी लागते आहे, तशी वेळ भविष्यात पतसंस्थांवरही येणार आहे. त्यासाठी सहकार विभागाच्या कंप्लॉयन्ससाठी सॉफ्टवेअर कंपन्यांना तयार व्हावे लागेल. पतसंस्था ग्रामीण भागात प्रामुख्याने काम करीत असल्यामुळे मनुष्यबळाची उपलब्धता कमी पगारावर होत असली, तरी भविष्यात सर्व स्ट्राफ हा तंत्रज्ञानस्नेही असावा लागेल. त्यासाठी सॅलरी ही आजच्या पेक्षा जास्त देणे क्रमप्राप्त होणार आहे. एआय AI मुळे सर्वच स्तरावर व समाज जीवनावर मोठा परिणाम होत असला, तरी मनुष्यबळाला आज तरी पर्याय नाही, हे लक्षात घेऊन मनुष्यबळ टेक्नॉलॉजी होणे हाच सुवर्णमध्य आहे.

— वासुदेव काळे

कुटुंबप्रमुख, श्री सिद्धिविनायक पतसंस्था परिवार, श्रीरामपूर

मो.नं. — ९८२२८ ३७०२५

\*\*\*\*\*

## कर्ज वाटप प्रक्रिया सोपी तरी कर्जाची वसूली अवघड — दिलीप पतंगे



**सोलापूर** — आर्थिक क्षेत्रात कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सोपी असली तरी त्या कर्जाची वसूली करणे अवघड प्रक्रिया असल्याची माहिती जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन संस्थापक अध्यक्ष दिलीप पतंगे यांनी सांगितली.

ते म्हणाले, पतसंस्थांनी आर्थिक स्थैर्य टिकविण्यासाठी चालू खाते आणि बचत खाते यांचे प्रमाण नियमित कसे राखता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज व शासनाने तयार केलेले निकष पाळण्यावर भर दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले. फेडरेशनच्या संचालिका शुभदा पटवर्धन यांनी मनोगत व्यक्त केले. अंजली मोरे यांनी प्रास्ताविक तर संतोष मिसळ यांनी आभार मानले.

## सहकारी पतसंस्थातील ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू

**नाशिक** — राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये असणाऱ्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सांगितली. येथे आयोजित केलेल्या सहकार महापरिषदेत ते बोलत होते.

नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले, पुणे पीपल्स सहकारी बँक अध्यक्ष सुभाष मोहिते, माजी सहनिबंधक डी. ए. चौगुले उपस्थित होते. महापरिषदेत पतसंस्था समोरील विविध अडचणी, कर्ज वसुली धोरण सहकारी संस्था डिजिटायझेशन आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

या सहकार परिषदेत पतसंस्थांसमोरील अडचणींबाबत काय उपाययोजना करता येतील याबाबत देखील व्यापक चर्चा करण्यात आली.

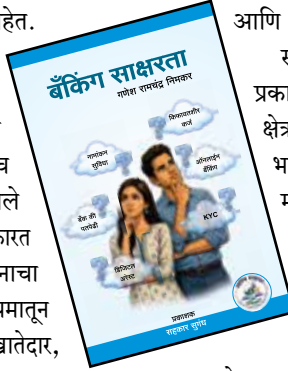
# ‘बँकिंग साक्षरता’ची गरज अधोरेखित करणारे पुस्तक

मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा कमी अधिक पणाने स्पर्श झाला आहे. अगदी रोजच्या व्यवहारात त्याचा अनुभव येतो आहे. या सर्व क्षेत्रातील एक महत्वाचे क्षेत्र म्हणजे बँक होय. नवनवीन तंत्रज्ञानाचे जसे फायदे आहेत, त्याचप्रमाणे काही तोटे जाणवत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जेष्ठ बँकिंग तज्ञ गणेश निमकर लिखित बँकिंग साक्षरता पुस्तक नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे.

गेल्या काही वर्षात बँकिंग क्षेत्रात वेगाने बदल घडत आहेत आणि त्याचा स्वीकार हा अनिवार्य आहे, म्हणजेच घर बसल्या बँकिंग व्यवहार करता येणे सहज शक्य झाले आहे. त्यामुळे बदलत्या काळातील आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारत असताना कोणकोणती काळजी घ्यायची आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन या पुस्तकाच्या माध्यमातून लेखकाने केले आहे. एका अर्थाने वाचकांच्या बरोबरीने खातेदार, ग्राहक, ठेवीदार यांच्या जागरूकता निर्माण करण्याचा आवश्यक असा प्रयत्न लेखकाने केला आहे, असे म्हणता येईल.

तीनशेपेक्षा अधिक पानांचे बँकिंग साक्षरता पुस्तक सचित्र आणि आवश्यक ती आकडेवारीने उपयुक्त झाले आहे. यामध्ये देशातील बँकिंग संकल्पना - रचना आणि बँकांचे प्रकार, नागरी सहकारी बँकांवरील निर्बंध, बँक गुंतवणूक आणि दक्षता, विविध ठेवींचे प्रकार, ठेवी आणि कर्ज, विमा आणि पत हमी महामंडळ, ठेवीदार आणि आयकर नियमांची जागरूकता, बँक लॉकर



सुविधा, ग्राहक सेवा, डिजिटल पेमेंट, कर्ज व्यवहार आणि आर्थिक शिस्त, सहकारी पतसंस्था आणि अर्थव्यवस्था अशा विविध विषयांची सखोल आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी पुस्तकाच्या माध्यमातून केली आहे. त्यामुळे वाचनीय आणि संग्राह्य असे पुस्तक झाले आहे.

सहकार सुगंध मासिकाचे संपादक भालचंद्र कुलकर्णी या पुस्तकाचे प्रकाशक असून या नात्याने मनोगत व्यक्त केले आहे. पुस्तकाला या क्षेत्रातील तज्ञांचे शुभेच्छा संदेश लाभले आहेत. त्यामध्ये सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी, आरबीआय संचालक सतीश मराठे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण आयुक्त अनिल कवडे, राज्य सहकारी बँक प्रशासक विद्याधर अनास्कर, राज्य अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन अध्यक्ष अजय ब्रम्हेचा, नॅफकब उपाध्यक्ष मिलिंद काळे आणि राधेश्याम चांडक यांचा समावेश आहे. तसेच लेखक गणेश निमकर यांनी मनोगतामधून पुस्तक लेखनामागची भूमिका मांडली आहे.

पुस्तकाची सजावट आणि मांडणी प्रथमेश जोशी आणि अर्चना गाढवे यांनी केली असून पुस्तकाची ही प्रथम आवृत्ती आहे. पाने ३०४ असून त्याची किंमत ३५० रुपये इतकी आहे.

– लेखक – गणेश निमकर मो.नं. – ९८२२५ ६८५५०

किंमत रुपये – ३५०/- पृष्ठ संख्या – ३०४

\*\*\*\*\*

## पैशांकडे पाहण्याची दृष्टी देणारे पुस्तक : ‘पैसा झाला मोठा’

आधुनिक कष्ट करून प्रत्येकजण पैसा मिळवतो. असा पैसा कमावणे अनेकांना जमते मात्र या पैशाला गुंतवून ठेवणे, त्याला आपल्या तालावर नाचायला लावणे, भल्याभल्यांना जमत नाही. दैनंदिन आयुष्यात घेतलेले लहान मोठे आर्थिक निर्णय आपले भवितव्य ठरवत असतात, हे कळते तेव्हा बराच उशीर झालेला असतो. जर तुम्हास वाटत असेल की, पैशाचा गोंधळ कमी व्हावा आणि भविष्यात योग्य आर्थिक निर्णय घ्यायला सुरुवात करावी, तेव्हा तुमच्या हातात स्वानंद समुद्र यांनी लिहिलेले ‘पैसा झाला मोठा’ श्रीमंतीकडे नेणारा व्यवहार्य मार्ग हे पुस्तक असायलाच हवे.

पुस्तकाचे लेखक स्वानंद समुद्र हे गेली ३९ वर्षे आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणूक या क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांनी अनेकांना श्रीमंतीकडे नेणाऱ्या व्यवहार्य राजमार्गावर चालायला शिकविले आहे. ‘पैसा झाला मोठा’ हे पुस्तक आपल्याशी संवाद साधते. यात झटपट श्रीमंत होण्याचे कोणतेही स्वप्न दाखविण्यात आलेले नाही तर संयम, शिस्त, सातत्य आणि योग्य निर्णय याचे महत्त्व सांगितले आहे. एकूणच या पुस्तकामुळे पैशाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी मिळते.

आर्थिक साक्षरतेची ओळख आणि भारताचा दृष्टिकोन, आर्थिक



मानसिकता आणि विचारधारा, वेळ, निर्णय आणि आर्थिक शिस्त, कर्ज, कार्ड आणि आर्थिक सापळे, गुंतवणूक, गणित आणि संपत्ती वाढीचे रहस्य, गुंतवणूक, सुरक्षा आणि मानसिक शांतता, नाती, आरोग्य आणि कुटुंबीय आर्थिक नियोजन, जीवनाचे टप्पे आणि भविष्य नियोजन, उत्पन्न, महागाई आणि आर्थिक सुरक्षा, गुंतवणूक पर्याय, म्युच्युअल फंड्स आणि शेअर बाजार आणि उत्पन्न, महागाई आणि आर्थिक सुरक्षा अशा एकूण अकरा भागात हे पुस्तक विभागण्यात आले आहे.

‘पैसा झाला मोठा’ हे पुस्तक म्हणजे ‘आर्थिक नियोजनाचा सोबती’ असून हे पुस्तक प्रत्येकाच्या घरी हवेच.

– प्रसाद घारे, मुक्त पत्रकार पुणे

मोबाईल नं. – ९३७३० ०५४४८

Email- ghare.prasad16gmail.com

किंमत : रुपये ४४० पृष्ठ संख्या : २७६

लेखक : स्वानंद समुद्र

मोबाईल नं. – ९८२२४ ४९९४२

\*\*\*\*\*

## सहकार परिषदेत श्रीवेद मल्टिस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीचा सन्मान

नांदेड – सहकारातून समृद्धि या संकल्पनेवर आधारित आयोजित करण्यात आलेल्या सहकार परिषदेत येथील श्रीवेद मल्टिस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीचा सन्मान करण्यात आला. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मारोतीराव कंठेवाड आणि कार्यकारी संचालीका सविता कंठेवाड यांनी हा सन्मान स्वीकारला.

ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, राज्य पतसंस्था

फेडरेशन उपाध्यक्ष डॉ. शांतीलाल सिंगी, जिल्हा उपनिबंधक समृत जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

परिषदेत बहुराज्यीय संस्थांच्या योगदानावर चर्चा करण्यात आली. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सहकार क्षेत्राची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली. या कार्यक्रमात कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले.

## श्री समर्थ सहकारी बँकेला १ कोटी १६ लाखांचा नफा

नाशिक – येथील श्री समर्थ सहकारी बँकेने नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात १ कोटी १६ लाख रुपयांचा नफा मिळविला आहे, अशी माहिती बँक अध्यक्ष राधाकृष्ण नाईकवाडे यांनी सांगितली.

नेट एनपीए ०.७४ टक्के असून एकूण ठेवी १६६ कोटी तर कर्ज वाटप ९१ कोटीचे आहे. बँकेने ८३.९४ कोटीची गुंतवणूक केली आहे. यावेळी बँकेचे संचालक, पदाधिकारी, उपस्थित होते.

# बँकांमधील बदल्यांचे स्वतंत्र धोरण असले पाहिजे

**भा**रतातील बँकांमध्ये ठराविक काळानंतर कर्मचारी, अधिकारी यांच्या बदल्या करणे बंधनकारक आहे. बँकांच्या नियामक असलेल्या रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने याबाबतील मार्गदर्शक सूचना सर्व बँकांसाठी जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे बँकांमधील जोखमीच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या तीन वर्षांनंतर बदल्या करणे बंधनकारक आहे.

सर्वांना सर्व प्रकारची कामे करता यावीत प्रत्येकाला सर्व विभागात काम करण्याची संधी मिळावी, एकाच ठिकाणी काम केल्यामुळे येणारे शैथिल्य टाळणे, हा बदल्यांमागचा मुख्य उद्देश असतो. एक व्यक्ती एका ठिकाणी अनेक वर्षे काम करत असल्यास असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून गैरप्रकाराची शक्यता देखील असते. हे टाळण्यासाठी नियमितपणे बदल्या कराव्यात अशा रिझर्व बँकेच्या सूचना आहेत.

रिझर्व बँकेच्या व्यतिरिक्त सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन यांनी तसेच वित्त मंत्रालयानेदेखील बदल्यांबाबत दोबळ स्वरूपाच्या सूचना बँकांना दिलेल्या आहेत.

बँकांमधील अफरातफरीच्या आलेल्या अनुभवांवरून सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन यांनी या सूचना दिलेल्या आहेत. लेखनिकांपासून ते वरिष्ठ पातळीवरील सर्व अधिकारी वर्गाच्या देखील बदल्या कराव्यात असे संकेत आहेत.

राष्ट्रीयकृत बँकेत कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांसोबत चीफ मॅनेजर, असिस्टंट जनरल मॅनेजर, चीफ जनरल मॅनेजर आणि मोठ्या बँकांतील एक्झिक्यूटिव्ह डायरेक्टर यांच्यादेखील नियमितपणे बदल्या होतात.

राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी बदल्यांबाबतचे धोरण ठरविलेले असून ते सर्व कर्मचारी, अधिकारी वर्गाला लागू आहे. बँकेच्या शाखा, कार्यालये जिथे असतील तेथे बदली होऊ शकते. प्रत्येक बढतीनंतर बदली हा सर्व बँकांमधील बदल्यांसाठी नियम असून लेखनिक श्रेणीतील कर्मचारी अधिकारी झाल्यावर त्याचीही बदली करण्यात येते.

बँकांमधील अधिकारी वर्गाच्या बदल्या करण्याच्या बाबतीत बरेचदा दुसऱ्या फळीच्या व्यवस्थापनाचा (सक्सेशन प्लॅन) उद्देश असतो. वरिष्ठ पातळीवर सर्व अधिकाऱ्यांना सर्व कामांचा अनुभव यावा, गरज पडल्यास विभागात काम करण्याची संधी द्यावी आणि कोणताही विभाग हा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली अनेक वर्षे असू नये यासाठीही हे नियोजन असते. लेखापरीक्षण विभाग, कर्ज विभाग, गुंतवणूक विभाग, वसुली विभाग, विधी विभाग हे बँकिंगमधील जोखमीचे विभाग समजले जातात. विविध अधिकाऱ्यांना कामाची संधी मिळावी आणि ठराविक अधिकाऱ्यांची त्या विभागाची मत्केदारी नसावी, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.

**\* बदल्यांबाबत नियोजन आणि पारदर्शकता** – बँकेच्या मनुष्यबळ विभागाने ज्या कर्मचारी, अधिकारी वर्गाची तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत, अशांची यादी मार्च महिन्यापूर्वी तयार करावी. चांगले काम करणाऱ्यांना पुढील चांगली संधी मिळावी तसेच बँकेच्या अपेक्षेप्रमाणे काम न करणाऱ्यांना पूर्व सूचना देऊन अन्यत्र बदली करणे हे पारदर्शकतेचे धोरण ठरू शकते. बढतीमुळे होणाऱ्या बदल्यांबाबत तोंडी किंवा लेखी सूचना देऊन जबाबदारीविषयी अवगत करण्यात यावे. नव्या पोस्टिंगमुळे जबाबदारीत कोणता बदल होणार आहे आणि बँकेची या बदलीपासून कोणती अपेक्षा आहे, हे स्पष्ट करण्यात यावे. बदल्यांबाबत पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मर्जीतील लोकांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे बदल्या आणि इतरांना शिक्षेच्या स्वरूपातील बदल्या (पनिशमेंट ट्रान्सफर्स) हे धोरण बँकांसाठी घातक ठरू शकते. योग्य कामासाठी योग्य व्यक्ती (राईट मॅन फॉर राईट जॉब) हे व्यवस्थापन शास्त्रातील महत्वाचे तत्त्व आहे. त्या त्या विषयातील ज्ञान असणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या आवडीचे काम करण्यासाठी बदल्यांचा उपयोग करता येऊ शकतो. कर्मचारी अधिकारी वर्गाची दुसरी फळी तयार करण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने बदल्या केल्यास बँकेचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यास मदत होते.

**\* बदल्यांच्या वेळा आणि खर्च** – मार्च महिना अखेर बदल्यांची पूर्वतयारी करावी. ऑडिट संपल्यानंतर एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात बदल्यांची प्रक्रिया शक्यतो पूर्ण व्हावी. जॉइनिंगसाठी पुरेसा वेळ देण्यात यावा. चार्ज देणे, घेणे यासाठीही पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. विशेषतः मोठ्या शाखांच्या बाबतीत ही काळजी घेतली जावी. मे महिन्यामध्ये शालेय वर्ष सुरू होते याचा विचार करून त्याआधी बदल्या झाल्या पाहिजेत, याची काळजी घेण्यात यावी. बदली झालेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्याला घर समान वाहतुकीचा खर्च, कुटुंबियांच्या प्रवासाचा खर्च बँकेच्या नियमांच्या चौकटीत देण्यात यावा. अडचणीच्या ठिकाणी बदल्या झाल्यास काही बँकांमध्ये गैरसोयीबद्दल भत्ता देण्यात येतो. मोठ्या शहरात बदली होत असल्यास नियमाप्रमाणे घर भाडे देण्यात यावे. शाखाधिकारी यांना क्वार्टर मिळण्यास अडचण असल्यास काही दिवस हॉटेलमध्ये राहण्याचा खर्च देण्याची काही बँकांची पद्धत आहे. बदलीनंतर कर्मचारी, अधिकारी नव्या जागी जावा अशा पद्धतीच्या वातावरण निर्मितीची जबाबदारी बँकेची आहे.

**\* बदल्यांबाबत अपवाद** – अपंग कर्मचाऱ्यांच्या शक्यतो बदल्या करू नयेत, अशा प्रकारचे नियम काही बँकांतून आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांना शक्यतो त्यांच्या सोयीच्या बदल्या देण्याची काही बँकांची पद्धत आहे. पती-पत्नी एकाच बँकेत असल्यास त्यांना एकाच गावात बदली देण्याची ही काही बँकांची पद्धत आहे. आजारपण, मुलांची शिक्षणे पालकांचे आजारपण या कारणासाठी विनंतीवरून बदल्या देण्याची काही बँकांची पद्धत आहे. नोकरीच्या कार्यकाळात एकदा किंवा दोनदा विनंतीवरून बदली देण्यात येते. नोकरीमधील शेवटची बदली कर्मचारी, अधिकाऱ्याच्या सोयीची करण्याची सर्व बँकांची पद्धत आहे. कर्मचारी अधिकारी वर्गाच्या बदल्या करणे हा व्यवस्थापनाचा हक्क आहे. कोणाला कुठे पाठवायचे याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय व्यवस्थापनाच्या अखत्यारीमध्ये असतो.

**\* नागरी सहकारी बँकांतील बदल्या** – नागरी सहकारी बँकांनी आपल्या शाखा, अन्य कार्यालये याचा विचार करून बदल्यांबाबतचे सुस्पष्ट धोरण आखणे गरजेचे आहे. संचालक मंडळाने याबाबतीत सुस्पष्ट धोरण तयार करून दरवर्षी बदल्या होतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. लिपिकांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व पातळीवर तीन वर्षांनी बदल्या झाल्याच पाहिजेत.

मुख्य कार्यालयातील विभाग प्रमुखांच्या आंतरविभागीय बदल्या होणे गरजेचे असते, त्यामुळे सर्वांना वेगवेगळ्या विभागातील कामांचा अनुभव येतो. बँकेला गरजेप्रमाणे त्यांची त्या त्या विभागात बदली करता येते. बढतीनंतर बदली हा नियमच असला पाहिजे. एकाच विभागात, एका शाखेत वारंवार बदल्या होणार नाहीत याची व्यवस्थापनाने काळजी घेतली पाहिजे. बदल्या हा प्रशासनाचा भाग असल्यामुळे संचालक मंडळांनी बदल्यांमध्ये अजिबात हस्तक्षेप करू नये. महिला कर्मचारी, पती-पत्नी, अपंग कर्मचारी यांच्याबाबतीत बदल्यांचे स्वतंत्र धोरण असले पाहिजे. बदल्या या पारदर्शक पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. कोणाची बदली का झाली याचे सुस्पष्ट कारण आवश्यकता पडल्यास सांगता आले पाहिजे. बँकेमधील नोकरीच्या काळात बदल्या होणारच हे कर्मचारी अधिकारी वर्गाने नेहमी गृहीत धरले पाहिजे. बढतीच्या प्रसंगी बदलीची तयारी ठेवली पाहिजे. निरनिराळ्या ठिकाणी झालेल्या बदल्यामुळे अनुभवांचे विश्व व्यापक होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी नव्याने ओळखी होतात. वैयक्तिक आणि बँकेच्या व्यवसायालादेखील उपयोग होतो. बँकेतील कर्मचारी, अधिकारी वर्गाने बदलांकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहण्याची सवय ठेवावी.

– डॉ. अभय मंडलिक (लेखक बँकिंग विषयाचे अभ्यासक असून खामगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक आहेत.)

\*\*\*\*\*



डॉ. अभय मंडलिक  
९४०३० ८०७२५



# शालिवाहन सहकारी पतसंस्थेची ३२२ कोटी व्यवसायाची भरारी



पैठण - येथील शालिवाहन सहकारी पतसंस्थेने उल्लेखनीय कामगिरी करतांना ३१ मार्च २०२६ अखेर ३२२ कोटी व्यवसायाचा टप्पा पार करत २ कोटी ११ लाख रुपये निव्वळ नफा मिळवला असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष किशोर चौहान यांनी सांगितली.

‘सहकारातून समृद्धीकडे’ या तत्त्वानुसार २९ वर्षांच्या प्रवासात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ३२२ कोटी व्यवसायाचा टप्पा पार करतांना एका आर्थिक वर्षात

२२ टक्क्यांनी व्यवसाय वाढ केली. आर्थिक वर्षाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संस्थेचा शून्य टक्के एन.पी.ए. सोबत ९९% कर्ज वसुली, १८०.८० कोटींच्या ठेवी, १४१.४० कोटींचे कर्ज वाटप, एकूण गुंतवणूक ६१.३६ कोटी, रोख तरलता निधी २.२६ टक्के एकूण गुंतवणूक तरलता निधी ३३.९२ टक्के भागभांडवल ७.५२ कोटी, राखीव व इतर निधी १५.११ कोटीसोबत संस्थेने २ कोटी ११ लाख रुपये निव्वळ नफा मिळविला आहे.

पतसंस्थेला सर्वोत्कृष्ट बँकिंगसोबत समाजोपयोगी सेवा दिल्याबद्दल, बँको ब्लू रिबन, राष्ट्रीय सन्मान पुरस्कार, दीपस्तंभ, गोदावरी पुरस्कार २०२५, व्यापारी अग्रणी पुरस्कार, बेस्ट चेअरमन पुरस्कार, बेस्ट सी.ई.ओ. पुरस्कार, मराठवाडा गौरव २०२६ या सारख्या राज्य पातळीवरील विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. संस्थेच्या वतीने ग्राहक साक्षरता अभियान राबविण्यात येत असल्याची माहिती संस्थेचे चौहान, उपाध्यक्ष डॉ. जयंत जोशी, मानद सचिव प्रकाश कासलीवाल यांनी सांगितली.

## सेकंडरी स्कूल एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीचे नवीन कार्यालय सुरु

मुंबई - सेकंडरी स्कूल एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी दादर येथील नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे सहकार खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, सहकार भारतीचे प्रदेश महामंत्री विवेक जुगादे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि संरक्षक दीनानाथ ठाकूर, संस्था अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि संचालक मंडळ सदस्य सहभागी झाले.

सहकार भारतीचे मुंबईतील आठ विभागातील अध्यक्ष व जिल्हा पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित होते. संस्थेच्या सभागृहात मुंबई सहकार भारतीची बैठक बैठक पार पडली.

माजी अध्यक्ष ठाकूर यांनी मुंबईत सद्य स्थितीत सहकार भारती करत असलेल्या कामाचे स्वरूप आणि आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी सर्वांनी अगत्यपूर्वक प्रयत्न करावेत असा सल्ला दिला. महामंत्री जुगादे यांनी आगामी संस्था सदस्यता अभियानात मोठ्या संख्येने संस्था सदस्य नोंदणी करण्यासाठी आवाहन केले.

मुंबई सहकार भारतीचे अध्यक्ष राहुल पाटील, संगठन प्रमुख संतोष सुर्वे, सहसंघटन प्रमुख जगदीश लाड वंजारी, सह्याद्री सहकारी बँक संचालक आणि प्रदेश ऑडिट प्रकोष्ठ प्रमुख, विजय शेलार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामकृष्ण आवारे आणि उत्तर मुंबई, वायव्य मुंबई, पश्चिम मुंबई, ईशान्य मुंबई, मध्य मुंबई, पूर्व मुंबई, दादर भाग, दक्षिण मुंबई जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

## सहकार भारती सहकार प्रशिक्षण सहकारी संस्था मर्या; (शासन मान्यताप्राप्त शिखर प्रशिक्षण संस्था)

मान्यताप्राप्त शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आमच्या प्रशिक्षण संस्थेचे नाव अधिसूचित केले आहे. अधिसूचित संस्थेकडून सहकारी संस्थांनी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे. नागरी सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था इ. सर्व संस्थाकरिता संचालक, पदाधिकारी, कर्मचारी व सभासदांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जातात.

### नागरी सहकारी बँकांसाठी

आमची संस्था बँकेच्या गरजेप्रमाणे दर्जेदार प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन बँकेच्या ठिकाणी जाऊन करते. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांबरोबरच नवीन भरती, स्टाफसाठी प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पदोन्नतीपूर्व प्रशिक्षण तसेच पदोन्नती परीक्षांचेही वाजवी दरात आयोजन करते. तरी याचा लाभ सहकारी बँकांनी घ्यावा. वरील सेवांसाठी कृपया संपर्क साधावा.

श्री. व्यंकटेश कुलकर्णी (प्रशिक्षण प्रमुख) - ९४०३० ८०७५१

श्री. उदय पेंडसे (संचालक) - ९८६९० ३४६६२

\* प्रशिक्षण कार्यालय - फ्लॅट नं. ३, रामेश्वर अपार्टमेंट, साई सर्व्हिस पेट्रोल पंपामागे, पूलाची वाडी, डेक्कन जिमखाना, पुणे ४११ ००४ ई-मेल - saharprashikshan@gmail.com

# शैक्षणिक क्षेत्रासाठीच्या विविध कर्ज योजना

एप्रिल-मे महिन्यात बहुतांशी विद्यार्थ्यांच्या सर्व परीक्षा आटोपलेल्या असतात. अभ्यासाचे ओझे उतरलेले असते. सुट्टीत काय करावचे, कुठे जायचे असे विचार घोंगावत असतात. त्यात पुढील वर्षही मध्येमध्ये डोकावते नक्कीच. कुठली निवड करावची पासून, कुठल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळेल, जवळ-लांब, बरे-वाईट याचा शोध आधीपासूनच सुरु झालेला असल्याने ठरवाठरवीला गती मिळते. सर्व शिक्षणासाठी लागणाऱ्या पैशाची तजवीज करणे सर्वात महत्वाचे... अग्रस्थानी असते.

पैसा असल्याशिवाय काही करता येत नाही, असाच समज त्या वयात आधी येतो. त्यांनाच सांगू इच्छिते, की जरी अडचण आली, तरी उदास व्हायचं नाही. सर्व सहकारी बँका शैक्षणिक कर्ज देतात. इतरही देतातच. १२ वी नंतरच्या शिक्षणाची सोय यामध्ये केली जाते. साधारणपणे पन्नास हजार ते दीड कोटीपर्यंत बँका कर्ज मंजुरी देऊ शकतात. ते काय शिकणार, विद्यापीठ कुठले, भारतात की परदेशात हे सर्व कागदपत्रांची दाखवावे लागते. सर्वात महत्वाचे असते हा विद्यार्थी अभ्यासात कसा होता, आहे, त्याला ठरवलेला कोर्स झेपणारा आहे का? त्याची कुवत जोखली जाते. खरं तर या कर्जासाठी त्याची क्षमता, बुद्धी, विचार, कर्ज फेडायची इच्छाशक्ती, एकूण तो/ती कशी आहे यावर अवलंबून त्यास कुठल्या शिक्षणासाठी किती कर्ज द्यावे लागेल, त्यानुसार पूर्णतः विद्यार्थ्यांच्या भल्याचा विचार केला जातो. शाळा-कॉलेज मधील निकाल व इतर गोष्टींची तपासणी होते. कागदपत्रांचा पूर्ण विचार, विद्यार्थी व त्याचे पालक यांच्याशी चर्चा होते. येणारा खर्च प्रत्येक वर्षानुसार काढला जातो. पुढे बँकेच्या पद्धतीने मंजुरी मिळते देखील.

प्रत्येक वर्षाला ठरवलेली रक्कम बँकेकडून विद्यार्थ्यास मिळते. त्याच्या खात्यात जमा न होता, डायरेक्ट कॉलेजला पाठवली जाते. कळवले जाते. इथे केलेल्या खर्चाच्या सर्व पावत्या बँकेकडे सुपूर्द कराव्या लागतात. बँकेचे काम खूप शिस्तित असते, पैशाचा घोटाला, फसवाफसवी चालत नाही. सध्या मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक कर्ज फेडले जातेच असे नाही. ते अगदी चुकीचे आहे. काही खाती एनपीए - (NPA - Non Performing Assets) - अनुत्पादित कर्ज - बँकेला काहीही उत्पन्न न देणारी कर्ज खाती - असे संबोधले जाते. बँकेला याने खूप त्रास होतो. आत्ताच्या टेक्नॉलॉजीची काळात जगातून एखाद्या व्यक्तीला शोधणे खूप सोपे झालेले आहे. शिवाय तुमची महत्वाची कागदपत्रे बँकेकडे असतात. तेव्हा कर्ज घेऊ मग बघू द्यायचे की नाही? अशी विचारधारा असणाऱ्याने बँकेत येऊच नये कर्ज प्रकरण करायला. बँका अशा विद्यार्थ्यांना विद्यार्थिनींना बरोबर शोधून काढतात. अशा परिस्थितीत मिळालेली नोकरी, बसलेला व्यवसाय सगळं संपते. तेव्हा घेतानाच निश्चय हवा, की या कर्जामुळे मला शिक्षण घेता आलेले आहे. मी बँकेचे कर्ज हप्ते वेळेवर फेडणार आहे. ही समज कर्जदारास हवीच हवी.

बारकाईने इथे इतकेच बास आहे. बाकीच्या गोष्टी बँकेत जाऊन चौकशी करून समजून घ्याव्यात.

※ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम - याची सुरुवात २०१५ मध्ये झाली होती. वरचेवर काहीतरी बदल होतातच. आता त्यानुसार इथे मुद्दे मांडलेले आहेत. ही योजना विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावी. गुगल करावे. मग पुढे जावे. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारतीय बँक संघ (IBA - Indian Bank's Association) आणि NSDL-e governance (www.egov-nsdl.co.in) या सर्वांनी मिळून एक पोर्टल सुरु करून सर्वप्रकारे बघितले जाते. पुढील माहिती विद्यार्थ्यांनी

www.vidyalakshmi.co.in पोर्टलवर बघावी.

देशाची सर्वप्रकारे प्रगती होत आहे. त्यात नवीन शैक्षणिक धोरण २०२४ मध्ये लागू केलेले आहे. तसेच इथेही बदल आहेत. शैक्षणिक कर्ज धोरणे सुलभ, सहज उपलब्ध, तारणमुक्त असा पर्याय देऊन, बँकेच्या योजनेनुसार पुढे जाते. प्रत्येक बँकेच्या योजनेत फरक असतो. ते समजून घेणे महत्वाचे आहे.

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भारत सरकारची उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी आखलेली आर्थिक साहाय्य देणारी योजना आहे. मॉडेल एज्युकेशन लोन स्कीम आणि डिजिटल कार्यभाग कर्ज मंजुरीला गतिमान करणारा महत्वाच भाग आहे. नव्याने आलेल्या बदलांपैकी महत्वाचे काही बदल इथे देत आहे. त्याचा विचार लक्षात घ्यावा. विद्यार्थ्याला/ विद्यार्थिनीला कर्ज मिळू शकते.

※ कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी आहे.

※ १० लाखांपर्यंतचे हे कर्ज कोणतेही तारण किंवा गॅरंटी न देता मिळू शकते.

※ काही विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या व्याजदरात ३% सूट दिली जाते. त्याचे बारकावे बघावेत.

※ पात्र विद्यार्थी निवड - राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क - NIRF - National Institutional Ranking Framework

- स्थापना सप्टेंबर, २०१५) मधील दर्जेदार - नंबर १०० ते २०० मध्ये येणाऱ्या सरकारी आणि खासगी नामांकित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होतो. तेव्हा कुठे प्रवेश घेत आहात हे ठरवताना याचा विचार केला पाहिजे. लक्षात ठेवले पाहिजे.

※ रुपये ४ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण लागत नाही.

※ पीएसयू - पब्लिक सेक्टर बँका ७.५० लाखांपर्यंतचे कर्ज विनातारण देतात. त्यापुढील त्यांच्या त्यांच्या धोरण व योजनेनुसार दिले जाते.

※ शैक्षणिक कर्ज संपूर्ण योजना ऑनलाइन केली जाते. अर्ज करणे, कागदपत्रांची तपासणी, कर्ज प्रपोजल, तपासणी, मंजुरी, वाटप सर्वच आता संगणकावर होत असल्याने पटापट कामे होताना आपण बघतो.

※ ज्यांना कोणाला कर्ज घ्यायचे असेल, त्यांनी त्यांची खाते जिथे असेल तिथे जाऊन चौकशी करावी. इतरही बँकेत जावे, तुलनात्मक अभ्यास करून बँक निवडावी. त्यांच्या योजना समजून घेणे गरजेचे आहे.

इथे लिंक्स देत आहे. त्याही बघता येतील. अवश्य बघाव्यात...

● प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना - www.vidyalakshmi.co.in

● प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना - PM-USP-CSIS

a) CSSS :: Central Sector Scheme of Scholarship

b) Sspecial Scholarship Scheme for Jammu Kashmir, Ladakh.

c) CSIS :: Central Sector Subsidy Scheme

● Credit Guarantee Fund for Educational Loan (CGFSEL)

● प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम - यूएसपी) २०२३-२०२४ https://pslm.in/prime-ministers-special-scholarshi-yojna-2024/ ज्याला शिकायचे आहे, त्याला मदत करणारे हात मिळतात. त्यांनी अवश्य प्रयत्न करावेत, आधी सर्वांगाने विचार, अभ्यास, आपली कुवत बघून मगच पाऊल टाकावे. अशांनी कष्टाची तयारी ठेवली, तर यश दूर पळत नाही हे नक्की. अशांना खूप शुभेच्छा!

- वंदना धर्माधिकारी मो.नं. - ९८९०६ २३९१५  
Email - vandana10d@yahoo.co.in \*\*\*



वंदना धर्माधिकारी  
९८९०६ २३९१५



**सहकार सुगंध मासिकात माहिती देणे, वर्गणी भरणे तसेच जाहिरातीसाठी  
जिल्हा प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा ही विनंती - संपादक  
श्री. संतोष गावंडे : रिजनल हेड (विदर्भ) 9420116337**

| पश्चिम महाराष्ट्र विभाग |                        |                          | उत्तर महाराष्ट्र विभाग |                        |                          |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| रहाटणी, पुणे            | श्री. डी. एस. कुलकर्णी | 9420655316               | जळगाव                  | श्री. विश्वास कुलकर्णी | 9922653022               |
| पिंपरी चिंचवड           | श्री. शिरीष लिपारे     | 9762830555               | धुळे                   | श्री. कृष्णा जाधव      | 8482993517               |
| इचलकरंजी                | श्री. प्रशांत कुलकर्णी | 9421172965               | नंदूरबार               | श्री. महादू हिरणवाळे   | 9823842991<br>8208147121 |
| सोलापूर जिल्हा          | श्री. चंद्रकांत धोंडे  | 9881139150               | नाशिक                  | श्री. राजीव चंद्रात्रे | 9403261226               |
| संगमनेर                 | श्री. विजय भिडे        | 9975516360               | नाशिक                  | श्री. नितीन बीबीकर     | 9665778497               |
| बेलापूर, जि. नगर        | श्री. अरविंद शहाणे     | 9922707677               | मराठवाडा विभाग         |                        |                          |
| सातारा                  | श्री. विनायक भिसे      | 9923396312               | छत्रपती संभाजीनगर      | श्री. योगेश भोसले      | 9421704116               |
| कोकण विभाग              |                        |                          | पैठण                   | श्री. देवेश इनामदार    | 9404981212               |
| मुंबई-अंधेरी            | श्री. रामकृष्ण आवारे   | 9619318544               | परभणी                  | श्री. मंगेश पाठक       | 8149355759               |
| मुंबई-विक्रोळी          | श्री. प्रभाकर कांबळे   | 9594293734               | जालना                  | अॅड. दशरथ इंगळे        | 9422723784               |
| मुंबई-जोगेश्वरी         | श्री. गणेश खिलारे      | 9322161526               | नांदेड                 | श्री. संदीप चिलकेवार   | 7507921655               |
| मुंबई-बोरिवली           | श्री. केशव खाडे        | 9969825835               | विदर्भ विभाग           |                        |                          |
| डोंबिवली                | श्री. संदीप गव्हाणे    | 7738449033               | नागपूर                 | श्री. महेश राव         | 9545741474               |
| पालघर                   | श्री. सदानंद पावगी     | 8888880680               | यवतमाळ                 | श्री. संतोष गावंडे     | 9420116337               |
| मुरुड, जंजिरा           | श्री. मेघराज जाधव      | 9561710445<br>9421164777 |                        |                        |                          |
| मुंबई-सायन              | श्री. भरत चिंचोले      | 7021862169               |                        |                        |                          |

**सहकारी संस्थांना अत्यंत उपयुक्त खालील पुस्तके सहकार सुगंध कार्यालयात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.**

| क्र. | पुस्तकाचे नाव                 | किंमत  | क्र. | पुस्तकाचे नाव                 | किंमत |
|------|-------------------------------|--------|------|-------------------------------|-------|
| १    | सहकार महर्षी ग्रंथ            | १५००/- | ३    | नागरी सहकारी बँकेचे प्रशिक्षण | १२५/- |
| २    | सहकार बँकांचे कर्ज व्यवस्थापन | ३५०/-  | ४    | बँकिंग साक्षरता               | ३५०/- |

वरील पुस्तकांसाठी रक्कम तसेच सहकार सुगंधची वर्गणी भरण्यासाठी सहकार सुगंधच्या वरील जिल्हा प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा किंवा खालील बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी खालील क्यूआर कोड वापरावा.



सहकार सुगंधची वर्गणी १ जानेवारी २०२५ पासून-  
वार्षिक रु. ७००/- त्रैवार्षिक रु. १८००/-

**UPI ID**

SahakarSugandha@DNSbank

A/c Name : Sahakar Sugandha  
Bank Name : Dombivali Nagari Sahakari Bank Ltd.  
(Sihagad Road, Pune Branch)  
Current a/c No. : 078011100000065  
IFS Code - DNSB0000078

कृपया वर्गणी जमा केल्यानंतर आपला नाव व पत्ता पुढील ई मेलवर कळवा. [sahakar.sugandha@gmail.com](mailto:sahakar.sugandha@gmail.com)



**UPI ID**

SahakarSugandha@SBI

A/c Name : Sahakar Printing & Publications Pvt. Ltd.  
Bank Name : State Bank of India  
(Hingne Khurd, Pune Branch)  
Current a/c No. : 36931889346  
IFS Code - SBIN0007159

**महाराष्ट्रात जिल्हा प्रतिनिधी नेमणे आहेत. संपर्क : ८८०५९८१६७३**



THE YAVATMAL URBAN CO-OP., BANK LTD., YAVATMAL

दि यवतमाळ अर्बन को-ऑप.बँक लि., यवतमाळ



मुख्य कार्यालय : एल.आय.सी. चौक, गार्डन रोड, यवतमाळ 445001 | फोन : 07232-244241, 243703, 237442

Mail - ho\_adm@yavatmalurbanbank.com | Website - www.yavatmalurban.bank.in

# अमृत वर्षा

## पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना

**6.60%\***

योजनेचा सामान्य व्याजदर

**7.10%\***

जेष्ठ नागरिकांकरिता व्याजदर

गुंतवणूक कालावधी 444 दिवस  
अंतिम तारीख - 31 मार्च 2027 पर्यंत



**डॉ. नितीन खर्चे**

अध्यक्ष

**अजिंदरसिंह चावला**

उपाध्यक्ष

**श्रीधर कोहरे**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

- संचालक -

श्री. अजय विठ्ठलदासजी मुंधडा, श्री. आशिष हरिहरराव उत्तरवार, श्री. प्रशांत अरुण माधमशेट्टीवार,  
श्री. संजय चिंतामणराव डेहणकर, श्री. प्रमोद मधूकरराव धुर्वे, अॅड. श्री. प्रफुल्लसिंह लक्ष्मणसिंह चौहान,  
श्री. गोवर्धन दयाराम राठोड, श्री. परिमल प्रेमकुमार देशपांडे, डॉ. श्री. महेश दामोदर सारोळकर, श्री. वसंता रामजी सुपारे,  
श्री. संतोष विष्णूकांत पेन्शनवार, श्रीमती मिरा राजेश घाटे, सौ. शिला राजेश्वर निवल, श्री. नरेंद्र देवराव देशपांडे (तज्ञ संचालक),  
अॅड. श्री. संतोष विठ्ठलराव कुचनकर (तज्ञ संचालक)

सहकार चळवळीतील महनीय व्यक्तींचा जीवनप्रवास  
महाराष्ट्रातील १७५ कार्यकर्तृत्वांचा सचित्र आलेख

द्वितीय आवृत्तीचे प्रकाशन दि. २१ सप्टेंबर २०२४, शिर्डी



सहकार भारती प्रकाशित  
सहकार सुगंध निर्मित...

# सहकार महर्षी

सहकार चळवळीतील प्रत्येकाने  
आवर्जून वाचावा असा ग्रंथ

सहकार महर्षी ग्रंथ - प्रतीनुसार विशेष किंमत (कुरिअर मोफत)

|                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| १ ते ५ ग्रंथ घेतल्यास         | - | रु. १५००/- प्रमाणे प्रती ग्रंथ |
| ६ ते १० ग्रंथ घेतल्यास        | - | रु. १३५०/- प्रमाणे प्रती ग्रंथ |
| ११ व त्यापेक्षा अधिक घेतल्यास | - | रु. १२००/- प्रमाणे प्रती ग्रंथ |



- महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थेचा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार प्राप्त
- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांनी शिफारस केलेला ग्रंथ

A/c Name :  
Sahakar Printing & Publications Pvt. Ltd.  
Bank Name :  
State Bank of India  
Branch :  
Hingne Khurd, Pune Branch  
Current a/c No. : 36931889346  
IFS Code : SBIN0007159



UPI ID SahakarSugandha@SBI  
सोबत दिलेला QR कोड स्कॅन करून  
ऑनलाईन पेमेंट करावे व तसे कार्यालयास कळवावे.

बुके नको 'बुक' देऊ या! आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकाला 'सहकार महर्षी' ग्रंथ देऊ या!



# OM SALES CORPORATION



## All our Products are BIS Standards

Our  
Certificates



ISO 14001 : 2004

IS 5244 : 2014



CM/L-7500087614

IS 550 : 2014



CM/L-3978088

IS 11188 : 2014



CM/L-2870669



ISO 9001 : 2008



Electronic  
safe

Depository  
safe

Gold Safe

Fire Resistant  
Cabinet

Fire  
Resistant  
Filing Cabinet

Industrial  
Locker

Compactor

**Nilesh Bonde Mob.: 9850120090 / 8698337947**

**Website : [www.omsalescorporation.net](http://www.omsalescorporation.net) | Id : [omsales.safeage@gmail.com](mailto:omsales.safeage@gmail.com)**

**Add. : S.No. 179, Fuge Vasti, Behind Pyramid Hotel,  
Near Gajanan Maharaj Mandir, Magazine Chowk,  
Bhosari-Alandi Road, Bhosari - 411039.**

**Factory Add - Safeage Security Products Pvt. Ltd., Shiye, Jyotiba Road, Kolhapur**

**We are authorised distributor for Pune, Satara, Sangli, Solapur, Ratnagiri,  
Sindhudurg, Raigad, Ahemadnagar, Nashik, Jalgaon, Dhule, Nandurbar,  
Aurangabad, Jalna, Parbhani, Hingoli, Usmanabad, Beed, Latur, Nanded,  
Buldhana, Akola, Amravati, Yavatmal, Washim, Nagpur, Bhandara,  
Wardha, Chandrapur, Gadchiroli, Gondiya,**

**सोलर  
लोनची साथ,  
गृह कर्जसोबत  
नवा विश्वास,**

**आता वाढत्या वीज  
बिलावर करा मात !**

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0)  
अंतर्गत सबसिडीस पात्र  
आपले गृह स्वप्न साकार करणं आता होईल सोपं !

**गृहकर्ज व्याजदर**

**7.90%\***

पाझून पुढे  
(सिबिल आधारित व्याजदर)

**गृहकर्ज घेतलेस रुफटॉप  
सोलर पॅनेल कर्ज  
व्याजदरसुद्धा**

**7.90%\***

(सिबिल आधारित व्याजदर)

पीएम सूर्यधर मोफत वीज योजना अंतर्गत  
भारत सरकार सबसिडीस पात्र

**सांगली  
अर्बन बँक  
कार लोन  
8.35%\***

पाझून पुढे  
(सिबिल आधारित व्याजदर)

**कार लोनवर  
व्याजदर कमी,  
आनंदाची  
शंभर टक्के हमी !**

किंमत व अटी खणगे

किंमत व अटी खणगे



**सांगली अर्बन को-ऑप. बँक लि., सांगली**

(शेड्युल्ड को-ऑप. बँक)

प्रधान कार्यालय : ४०४, खणभाग, सांगली ४१६४१६, फोन : (०२३३) २३७६२३६ / ३७/३८

मोबाईल : ७८८८००९७९८

अधिक माहितीसाठी आमच्या नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधा.

**सहकार भारतीचे मुखपत्र सहकार सुगंध निर्मित**



**नागरी सहकारी 2026  
बँक / पतसंस्था दैनंदिनी**



नागरी सहकारी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या  
सर्व परिपत्रकांचा मराठीत संक्षिप्त गोषवारा  
तसेच QR कोडच्या मदतीने RBI ची सर्व  
मूळ परिपत्रके उपलब्ध असणारी एकमेव  
दैनंदिनी व नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या  
दैनंदिनीमध्ये गेल्या तीन वर्षातील  
सर्व महत्वाच्या परिपत्रकांचा समावेश  
देशभरातील नागरी सहकारी बँका  
व पतसंस्थांच्या संख्येनुसार आर्थिक  
स्थितीच्या उपयुक्त माहितीसह...



किंमत रु. 400/-

अधिक प्रतीसाठी  
विशेष सवलत

आजच नोंदणी करा!

**नागरी  
सहकारी  
बँक दैनंदिनी  
२०२६**

किंमत रु. 500/-

अधिक प्रतीसाठी  
विशेष सवलत

आजच नोंदणी करा!

**नागरी  
सहकारी  
पतसंस्था दैनंदिनी  
२०२६**



सहकार भारतीचे मुखपत्र 'सहकार सुगंध' कार्यालय : ऑफिस नं. १५, विष्णुप्रिया अपार्टमेंट,  
गणेशमळा, सिंहगड रोड, पुणे - ४११०३० मो. : 8805981673 ईमेल : sahaakar.sugandha@gmail.com

50<sup>+</sup>  
YEARS OF  
MOMENTUM



दि कल्याण जनता  
सहकारी बँक लि.

मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक

ज्येष्ठ नागरिकांनो,  
ऑनलाईन फसवणूक करणारे  
तुम्हाला फसवण्याआधी  
तुम्हीच त्यांना ओळखा व  
त्यांच्या जाळ्यात अडकणे टाळा.

सजग रहा, सुरक्षित बँकिंगचा अवलंब करा.



अधिकृत  
अॅप्सचाच  
वापर करा

अनोळखी कॉल  
किंवा संदेशांवर  
प्रतिसाद टाळा!

अर्थ सहकारेण कल्याणम्

OTP कधीही  
शेअर करू  
नका!

अनोळखी  
लिंकवर  
क्लिक टाळा!

TOLL FREE: 1800 233 1919  kalyanjanata.bank.in    KJSBank



## महाराष्ट्र दिनाप्रित्यर्थ हार्दिक शुभेच्छा!



2 वर्षापेक्षा जास्त  
1 लाखावर  
मिळवा  
**₹ 900/-**

2 वर्षापेक्षा कमी  
1 लाखावर  
मिळवा  
**₹ 850/-**

### • मुदत ठेव (F.D.) योजना •

| गुंतवणूक कालावधी   | व्याजदर |
|--------------------|---------|
| 30 ते 45 दिवस      | 7.00%   |
| 46 ते 180 दिवस     | 8.00%   |
| 181 ते 365 दिवस    | 9.00%   |
| 366 दिवसांहून अधिक | 10.00%  |

455 दिवस  
10.00%

90  
महिण्यात  
दाम दुप्पट

**प्राईड ऑफ महाराष्ट्र पुरस्कार**  
द्वारा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल अँड इकॉनॉमिकल  
डेव्हलपमेंट अँड एस.एम.ई. चेंबर्स ऑफ इंडिया

**बँको पुरस्कार**  
१५-१६, १६-१७, १७-१८, १८-१९, १९-२०, २०-२१, २१-२२ द्वारा अवीज पब्लिकेशन, कोल्हापूर

**प्रतिबिंब पुरस्कार**  
द्वारा सहकार सुगंध,  
पुणे

**सहकार गौरव पुरस्कार**  
२१-२२, २२-२३ द्वारा फेडरेशन ऑफ मल्टिस्टेट  
को-ऑप.क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, पुणे

**दीपस्तंभ पुरस्कार**  
२०१६-१७, १७-१८, १८-१९, १९-२०, २०-२१,  
२१-२२, २२-२३ द्वारा राज्य फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य

**राष्ट्रीय पुरस्कार-बेस्ट को-ऑप.सोसायटी**  
द्वारा चेंबर ऑफ इंडियन मायक्रो स्मॉल  
अँड मिडीयम एंटरप्रायजेस

**अर्थरत्न पुरस्कार**  
द्वारा सहाद्री उद्योग समूह,  
अहमदनगर

**सर्वोत्कृष्ट संस्था पुरस्कार**  
२०२२ द्वारा मल्टिस्टेट फेडरेशन,  
पुणे

### धनंजय तांबेकर

व्यवस्थापकीय संचालक, गोदावरी अर्बन  
संचालक, मॅफको

### सौ. राजश्री हेमंत पाटील

अध्यक्ष,  
गोदावरी अर्बन



# गोदावरी अर्बन

मल्टिस्टेट क्रेडिट को-ऑप.सोसायटी लि. नांदेड  
कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, गोवा

Follow us on : [f](#) [i](#) [in](#) [www.godavariurban.com](http://www.godavariurban.com)

मुख्यालय : 'सहकारसूर्य' एमएसईबी समोर, तरोडा नाका, पूर्णा  
रोड, नांदेड-४३१६०५. फोन: ०२४६२-२६७२७७, ७७७५००५७७७  
Email : [officeadmin@godavariurban.com](mailto:officeadmin@godavariurban.com)  
प्रशासकीय कार्यालय : रिजेंट चेंबर्स, पहिला मजला,  
स्टेट्स हॉटेलच्या वर, नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२१

विश्वास  
तुमचा,  
जबाबदारी  
आमची!